

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



मार्च 2020

खंड 74 अंक 3

संपादन समिति
राजीव रंजन
डी. पी. रथ
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
एस. गंगाधरन
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2020

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

एनआईबीएम स्वर्णजयंती समारोह माननीय राष्ट्रपति - श्री राम नाथ कोविंद	1
21 वीं सदी में बैंकिंग परिदृश्य शक्तिकांत दास	5

लेख

भारत में मौद्रिक नीति संचरण – हालिया प्रवृत्तियाँ और बाधाएं	11
भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग : चुनौतियां और संभावनाएं	27
वर्तमान सांख्यिकी	43
हाल के प्रकाशन	89

भाषण

एनआईबीएम स्वर्णजयंती समारोह
माननीय राष्ट्रपति - श्री राम नाथ कोविंद
21 वीं सदी में बैंकिंग परिदृश्य
शक्तिकांत दास

एनआईबीएम स्वर्णजयंती समारोह*

- महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी
- गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री शक्तिकांत दास
- निदेशक, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, डॉ. के एल ढोंगरा
- प्रबंध मंडल के सदस्य, छात्र, संकाय और अन्य स्टाफ सदस्य
- विशिष्ट अतिथिगण
- देवियो और सज्जनो

राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) के स्वर्ण जयंती समारोह पर आप सभी के साथ रहने की मुझे असीम खुशी है। राष्ट्र के लिए पचास साल की सेवा गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर संस्थान से जुड़े हर व्यक्ति को हार्दिक बधाई देता हूँ।

क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना करना भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों की महान दूरदर्शिता थी। यह स्वायत्त सर्वोच्च संस्थान के रूप में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और बैंक प्रबंधन में परामर्श के लिए स्थापित किया गया था। यह अपने अधिदेश पर खरा उतरा है मुझे पता चला है कि स्थापना के बाद से यहां 1.1 लाख से अधिक बैंकरों को प्रशिक्षित किया गया है। एनआईबीएम परिसर ने लगभग 9,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अतिथ्य किया है। इस प्रकार संस्थान ने भारत की 'सॉफ्ट पावर' के निर्माण में विदेशों में बहुत योगदान दिया है। राष्ट्रपति के रूप में अपनी विदेश यात्राओं के दौरान, भारत के युवाओं के साथ-साथ भारत में शिक्षित या प्रशिक्षित उन युवाओं को देखकर मुझे खुशी हो रही है जिन्होंने छाप छोड़ी हैं।

* माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान पुणे, के स्वर्णजयंती समारोह में दिया गया संबोधन।

देवियो और सज्जनो,

बैंक हमारी आर्थिक प्रणाली के आधार हैं। इस भूमिका में उनकी दक्षता ने लोगों का विश्वास और सम्मान जीत लिया है। हमारे संविधान ने सभी नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय का वादा किया। इस संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बैंकों को महत्वपूर्ण उत्प्रेरक माना गया। इस अवसर पर, एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका से परे एक अधिदेश का अच्छी तरह अनुसरण करने के लिए मैं भारत के बैंकों की सराहना करता हूँ। वे हमारी आबादी के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए राज्य के प्रयासों का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं।

इन वर्षों में, बैंकों ने भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। आजादी के समय, बैंकिंग क्षेत्र को उपस्थिति की कमी और अस्थिरता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक नवजात गणतंत्र के लिए, अपने नागरिकों के लिए आर्थिक अवसर बनाने में ये बड़ी बाधाएँ थीं। तब से बैंकिंग क्षेत्र द्वारा की गई प्रगति संतोषजनक है। आज एक वर्ष में खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या आजादी के समय की कुल शाखाओं की संख्या के बराबर है। भारत के अधिकांश गाँवों में बैंकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक निगरानी ने भी बैंकिंग परिचालन में अधिक स्थिरता लायी है। मुझे पता चला है कि हाल ही में विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को मजबूत किया गया है। हमें विश्वास है कि यह कुप्रथाओं को दूर करेगा और हमारी वित्तीय प्रणालियों को और विश्वसनीय बनाएगा।

आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक, बड़ी संख्या में लोगों, विशेष रूप से गरीबों के लिए, बैंकिंग तक कोई पहुंच नहीं थी। "प्रधानमंत्री जन धन योजना" के अंतर्गत बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों ने इस स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। कोई यह कह सकता है कि इतिहास में पहले कभी भी इतने लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में नहीं लाया गया है। जैसे-जैसे योजना आगे बढ़ी, लगभग 35 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। यह संख्या हमारे और चीन के अलावा सभी देशों की जनसंख्या से बड़ी है।

मैं इसे संभव बनाने में बैंकिंग क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के प्रयासों की दिल से सराहना करता हूँ। मैं उनसे यह भी आग्रह करूँगा कि किसी भी नागरिक को पीछे न छोड़ें। बैंकर को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह 'मार्केट डेपथ' और 'डी-रिस्कंग ऑपरेशंस' हासिल करने का एक और उत्तम उपाय है।

वित्तीय समावेशन के माध्यम से, हमने अपनी जनसंख्या के बैंकिंग सेवा रहित क्षेत्रों को समावेश करने में तेजी से प्रगति की है। हमारे सामने अब शामिल लोगों को और अधिक तीव्रता से शामिल करने की चुनौती है। मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि सामाजिक व्यवस्था के हाशिए पर रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय उत्पादों के बारे में सोचें। मैंने देखा है कि एनआईबीएम में अच्छी अनुसंधान सुविधाएं हैं। इनका उपयोग आबादी के गरीब वर्गों के लिए वित्तीय उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। देश की प्रगति गरीबों की सामूहिक आर्थिक ताकत के योगदान पर निर्भर करती है। महिलाओं की अगुवाई में स्वयं सहायता समूह के आंदोलनों ने यह दिखाया कि गरीबों में निवेश करने से लाभ मिल सकता है।

सामाजिक व्यवस्था के हाशिए पर रहने वाले लोगों की सहभागिता के लिए बैंकर्स द्वारा सहानुभूति और अनुकंपा प्रकट करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी कम सेवा वाले बैंकों के क्षेत्र में अधिक से अधिक जुड़ाव और उनके प्रति नजरिए में बदलाव की जरूरत है। हमारे बैंकों ने आम आदमी के लिए सेवा उपलब्ध कराके अभिजात्य वर्ग से बैंकिंग को बदलने में एक सराहनीय काम किया है। गरीबों और जरूरतमंदों के बैंक खाते में, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाखों लोगों को प्रत्यक्ष निधि अंतरण का लाभ मिला है। मुझे पता चला है कि यह राशि लगभग 9.2 लाख करोड़ रुपये है। यह वास्तव में बहुत ही आश्चर्य करने वाला है और हम अपनी उम्मीदों के स्तर को बढ़ा सकते हैं।

आप सभी सहमत होंगे कि महिलाओं में अधिक वित्तीय कौशल है। मैं इस बात पर संतोष व्यक्त करता हूँ कि खाताधारकों में लिंग भेद तेजी से कम हो रहा है। यह हमें आर्थिक और सामाजिक न्याय के हमारे संवैधानिक लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मैं बैंकों से अनुरोध करता हूँ कि वित्तीय आस्तियों में अधिक से अधिक लिंग समानता लाने के लिए सक्रिय कदम उठाएँ। सामाजिक जिम्मेदारी के भाग के रूप में बैंक, महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को अपना सकते हैं। एनआईबीएम

टूलकिट डिजाइनिंग पर विचार कर सकता है, जो बैंक उपयोग कर सकते हैं।

भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी यात्राओं के दौरान मुझे कई 'दिव्यांग' व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिला। उनके साथ मेरी बातचीत से, सक्षम वातावरण दिए जाने पर उनकी जबरदस्त क्षमता का पता लगा। हमारी आबादी में 2 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं और हमें वित्तीय मुख्यधारा में उन्हें पूरी तरह से एकीकृत करने का हर संभव प्रयास करना होगा। मुझे पता चला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दिव्यांगजनों 'की बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुँच के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मैं भारतीय रिजर्व बैंक से आग्रह करूँगा कि हमारी 'दिव्यांगजन' बहनों और भाइयों 'को वित्तीय सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिए सभी उपाय करें।

देवियो और सज्जनो,

भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। बैंक भारत की विकास गाथा का निरंतर हिस्सा रहे हैं। जैसा कि भारत का लक्ष्य 5-ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, बैंकिंग क्षेत्र को अगली बड़ी छलांग के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से "बैंकिंग सेवा रहित क्षेत्र में बैंकिंग" और "असुरक्षित को सुरक्षित करना" शामिल है। इस खोज में, वैश्विक मानकों के बैंकिंग संस्थानों की सेवा करने के लिए कुशल प्रशिक्षित मानव संसाधन का एक पूल बनाने की जिम्मेदारी लेने का एनआईबीएम से मैं आग्रह करता हूँ।

यदि बैंक गहरी पहुँच प्रदर्शित करते हैं और अधिक कुशल बनते हैं तो भारत की भविष्य की यात्रा में बहुत सहायक होगा। हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार को देखते हुए, हमें दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों में एक से अधिक नाम रखने का लक्ष्य रखना चाहिए।

हमारे भविष्य के रोडमैप पर 'जनसांख्यिकीय लाभांश' पर भी विचार करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है कि यह लाभ उचित रूप से प्राप्त किया जाए। मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएं आकांक्षात्मक उद्यमियों को धन मुहैया करा रही हैं। मैं सभी बैंकों से निवेदन करूँगा कि वे गहरी नजर रखें और धन की कमी के लिए अच्छी योजनाओं को नष्ट न होने दें।

तकनीकी को अपनाने में बैंक सबसे आगे रहे हैं। तेज निपटान प्रणाली, इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान बैंकों जैसे नवाचारों ने ग्राहक

के लिए बैंकिंग को बहुत आसान बना दिया है। वैश्विक प्रशंसा जो कि स्वदेशी रूप से विकसित यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने खींची है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया एक उपहार है और सभी भारतीय इस पर गर्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए बैंक नई उभरती हुई तकनीकों को देख रहे हैं। मुझे भरोसा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक मार्गदर्शन भी दे रहा है, साथ ही प्रौद्योगिकी को अपनाने में उचित सुरक्षा उपायों के मुद्दे को भी संबोधित कर रहा है।

देवियो और सज्जनों,

स्वतंत्रता के बाद बैंकों को इक्विटी के साथ वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक करार का हिस्सा माना जाता था। देश की आर्थिक प्रणाली में बैंकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम लागू किया गया था। हमारे राष्ट्र के संस्थापक इस बात के प्रति बहुत सचेत थे कि बैंकों को सार्वजनिक न्यास के धारक के रूप में भूमिका निभानी होगी। मैं सभी बैंकों को इस कसौटी पर अपने कार्यों को परखने के लिए प्रेरित करूंगा। सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में, अर्थव्यवस्था में बैंकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव विवेकपूर्ण उपाय करने होंगे कि किसी भी तरह से

विश्वासघात न हो। हाल ही में निक्षेप बीमा कवरेज को ₹ 1 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख करने का प्रस्ताव बचतकर्ताओं को आश्वासन देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

छोटी शुरुआत से, बैंक बहुसांस्कृतिक संगठन बन गए हैं। इसलिए, बैंक हमारे संविधान में निहित अधिकता के मूल्यों के लिए खड़े हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम बैंकों के भीतर समानता और विविधता के साथ-साथ समाज के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करना जारी रखें।

यह प्रशंसनीय है कि एनआईबीएम को भारत और विदेशों में अध्ययन और उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। मुझे पता चला है कि एनआईबीएम हमारे बैंकिंग क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए जनशक्ति विकसित कर रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, वर्तमान और अतीत के निदेशकों, संकाय और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ और बैंकिंग उद्योग का समर्थन करने के लिए उनके अधिक समर्पण और योगदान की आशा करता हूँ।

मैं एनआईबीएम के छात्रों और संकाय सदस्यों को उनके भविष्य के प्रयासों और आगे के कई शानदार वर्षों में सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद।

21 वीं सदी में बैंकिंग परिदृश्य* शक्तिकांत दास

मिंट की वार्षिक बैंकिंग संगोष्ठी में आज यहां आना मेरे लिए वाकई खुशी की बात है। मुझे बताया गया है कि यह संगोष्ठी का 13वां संस्करण है, जो एक प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, जिसने वित्त और बैंकिंग उद्योग के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली मेधावियों को आकर्षित किया है। भारत के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के सभी हितधारकों को यह आकलन करने के लिए कि हम आज कहां खड़े हैं और कल कहां पहुंचना चाहते हैं, की हमारी तैयारी के लिए, यह संगोष्ठी, एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र जिन तमाम मुद्दों से दो-चार होता रहा है, उसने नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है। बैंकों के विनियामक और पर्यवेक्षक होने के नाते, रिजर्व बैंक देश में एक सुदृढ़ और मजबूत बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए व्यवसाय मॉडल और नई तकनीक के उद्भव और बैंकिंग व वित्त में इसके अनुप्रयोग ने नए अवसर पैदा किए हैं। इन नए घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर गहन दृष्टि डालने के प्रयोजन से, मैंने आज अपनी बात रखने के लिए जो विषय चुना है वह है “21वीं सदी में बैंकिंग परिदृश्य”।

वित्त और बैंकिंग वैश्विक आर्थिक विकास के इंजन के रूप में उभरे हैं। यह तर्क दिया गया है और मेरी राय में, यह तर्क ठीक भी है कि वित्तीय सेवाओं के प्रसार में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।¹ चेक, तार अंतरण, एटीएम और क्रेडिट कार्ड इसी प्रकृति के महत्वपूर्ण नवाचार थे। हाल के दिनों पर यदि सरसरी नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि हम तकनीकी क्रांति की पृष्ठभूमि में बैंकिंग में एक और ऐसा आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं, जो बेहतर - ग्राहक अनुभव, जोखिम प्रबंधन और शेयरधारकों

के लिए बेहतर रिटर्न का वादा करता है।² इस परिवेश में, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसके क्या मायने हैं और हम खुद को आने वाले समय के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में, मैं अब वैश्विक बैंकिंग के रुझानों पर चर्चा आरंभ करना चाहूंगा और फिर मैं भारतीय बैंकिंग में हाल के रुझानों, बैंकिंग के नए आयामों और इसके भावी मार्ग पर गौर करना चाहूंगा।

I. वैश्विक बैंकिंग : उभरते विनियामकीय रुझान

वैश्विक वित्तीय संकट बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इसने अन्यथा दुर्जेय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अंतर्निहित खामियों को उजागर किया है। इस संकट ने विनियामक ढांचे में आमूलचूल सुधार, आर्थिक और वित्तीय परिवेश में दीर्घकालिक बदलाव और वित्तीय सेवा उद्योग के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में एक बड़े परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

संकट-पूर्व विनियामक ढांचे की खामियों को दूर करने हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) जैसी अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय संस्थाएं तत्पर थीं। नतीजतन, वैश्विक वित्तीय प्रणाली को और अधिक आघात सहनीय बनाने के उद्देश्य से बासेल-III सुधारों के हिस्से के रूप में लीवरेज, नकदी और पूंजी पर्याप्तता सहित कई विनियामक मानदंडों की समीक्षा की गई। नकदी जोखिम को दूर करने के लिए, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) जैसे नये लिखतों को आरंभ किया गया था, जो बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क द्वारा प्रतिपूरित थे। इसने बड़े व जोखिमपूर्ण एक्सपोजर को सीमित कर दिया है। “टू बिग टू फेल (टीबीटीएफ)” समस्या के निराकरण के उद्देश्य से, एफएसबी ने वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) के लिए कुल हानि अवशोषण क्षमता (टीएलएसी) चरणबद्ध तरीके से आरंभ की ताकि वे अपने पूंजीगत बफर्स का पुनर्निर्माण कर सकें। विभिन्न अधिकारिताओं ने भी एफएसबी द्वारा शुरू किए गए अन्य प्रमुख सुधारों यथा

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक - 24 फरवरी, 2020 - मिंट की वार्षिक बैंकिंग संगोष्ठी, 2020 में सम्बोधन।

¹ आरनर, डी. डब्ल्यू. बर्बरिस, जे. & बकले, आर.पी. (2015)। द इवोल्यूशन ऑफ फिनटेक: ए न्यू पोस्ट-क्राइसिस पराडिज्मा। जॉर्जटाउन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, 47, 1271।

² गुप्ता, ए., & ज़िया, सी। (2018)। ए पराडिज्म शिफ्ट इन बैंकिंग : अनफोल्डिंग एशियाज फिनटेक एडवेंचर्स बैंकिंग एंड फाइनेंसियल इश्यू इन इमर्जिंग मार्केट्स (आर्थिक सिद्धांत और अर्थमिति में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, खंड 25)।

वित्तीय संस्थाओं के लिए अच्छा प्रस्ताव, शासन एवं मुआवजे की विधियों के प्रभावी पर्यवेक्षण को अपनाया है। गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) के संबंध में, एफएसबी 2011 से वार्षिक निगरानी अभ्यास कर रहा है। मुख्य तौर पर, यह देखा गया है कि, गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता के कई पहलू जिन्होंने वित्तीय संकट बढ़ाने में भूमिका निभाई है, को काफी हद तक रोक दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा की गई पहल को देखते हुए, नीति निर्माता अपने अधिकार-क्षेत्र में विनियामक ढांचे को सशक्त बना रहे हैं। इन नीतियों के अपनाने से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली को इसके बदले में मध्यावधि एवं दीर्घावधि में सुदृढ़ता और समुत्थानशीलता प्राप्त होगी। 2018 में शुरू हुई वैश्विक विकास मंदी के चलते, हाल ही में, ऋण वृद्धि की गति अवरुद्ध होने से, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आई है। इसके फलस्वरूप, बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आस्ति की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार के बावजूद, यूरो क्षेत्र में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में निरंतर वृद्धि और कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में थोक वित्तपोषण जैसी संरचनात्मक दुर्बलताएं बनी हुई हैं। फिर भी, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद शुरू किए गए विभिन्न विनियामक सुधारों के चलते प्रमुख उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की पूंजी स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है।

II - भारतीय परिदृश्य

भारतीय रिज़र्व बैंक में, हमने काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर (सीसीसीबी); सेंट्रल काउंटर पार्टियों (सीसीपी) के लिए पूंजी की आवश्यकताएं; लीवरेज अनुपात ढांचा; चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) ; निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर); प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक (डी-एसआईबी) की आवश्यकताएं; और बड़े जोखिमों को परखने और नियंत्रित करने के लिए एक पर्यवेक्षी ढांचे के संदर्भ में बड़े पैमाने पर बासेल मानकों का अनुपालन किया है। केंद्र सरकार द्वारा आईबीसी की धारा 227 के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में निराकरण के मोर्चे पर कुछ प्रगति हुई है। हालाँकि भारत में कार्यरत वित्तीय फर्मों में निराकरण के लिए हम निकट भविष्य में एक एकीकृत ढांचे की उम्मीद कर सकते हैं। भारत में एक

आघात सहनीय वित्तीय प्रणाली होने के नाते इस सुधार के कार्यान्वयन का विशेष महत्व है।

हाल ही में हुई प्रगति के संदर्भ में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के माध्यम से बड़े प्रस्तावों के साथ आस्ति की गुणवत्ता में हुई वृद्धि के चलते धीरे-धीरे सुधार की ओर अग्रसर है। खराब आस्ति में हाल ही में आई कमी और प्रावधान में महत्वपूर्ण सुधार के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता नाजुक बनी हुई है। हालाँकि, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने के प्रयासों के चलते बैंकों में पूंजी की स्थिति बेहतर हुई है। फिर भी, यह क्षेत्र दूरसंचार क्षेत्र के आसपास की घटनाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना जारी रखे हुए है।

नतीजतन, गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) का भावी दुष्प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है, जो कि ऋण वृद्धि पर भारी पड़ रहा है। इसके अलावा, मुनाफे में नरमी एवं कतिपय कॉर्पोरेट्स के डिलिवरेजिंग के मद्देनजर, जोखिमग्रस्त बैंकों ने अपना ध्यान बड़े बुनियादी ढांचे और औद्योगिक ऋणों से हटा कर खुदरा ऋणों की तरफ लगाना शुरू कर दिया है। विविधीकरण की यह कार्यनीति, जोखिमशमन उपकरण के रूप में सहायक तो है लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसके अलावा, दबाव के क्षेत्र में विशिष्ट इलाकों पर नीतिगत तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही, क्रेडिट में सम्यक श्रम करने और जोखिम मूल्य निर्धारण का प्राथमिक तौर पर महत्व है, ताकि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य से समझौता न किया जाए।

जैसा कि आरबीआई की दिसंबर 2019 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बताया गया है, बैंकिंग स्थिरता संकेतक एक सुधार दिखाता है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल गैर-निष्पादक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात को नीचे लाने के लिए तीव्र समाधान, बेहतर वसूली आदि जैसे समयबद्ध शमन उपायों को जारी रखने की जरूरत है। यद्यपि जीएनपीए को मापने के लिए ऋण वृद्धि की निम्न दर, सीमा के आकार को सीमित करती है, तथापि वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थितियों और भू-राजनैतिक विकास से उत्पन्न जोखिम बना हुआ है।

³ <https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=946>

III - बैंकिंग के नए आयाम

बैंकिंग की उभरती संरचना

वैश्विक बैंकिंग प्रणाली अभी वैश्विक वित्तीय संकट से उभरे अंतराल को दूर करने की प्रक्रिया में है, जबकि नए मुद्दे सामने आए हैं और मूल पारंपरिक बैंकिंग व्यवसाय को चुनौती दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर, बैंक, डिजिटल नवाचार का लाभ उठाने वाले गैर-पारंपरिक सहभागियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में बैंकिंग संरचनाएं इन नए आवेगों को अपना रही हैं।

कई फिनटेक स्टार्टअप्स ने बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग का गठन और विस्तार किया है। उन्होंने पीयर-टू-पीयर लेंडिंग, क्राउड-फंडिंग, ट्रेड फाइनेंस, इंश्योरेंस, अकाउंट एग्रीगेशन और वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में भुगतान और प्रेषण स्थल में प्रवेश ले लिया है। फिनटेक सहभागियों के सहयोग से, कई बैंक एक हाइब्रिड मॉडल लागू कर रहे हैं, जहां मोबाइल सेवाएं बैंकिंग सेवाओं के साथ संपर्क साध रही हैं।

बैंकों को न केवल फिनटेक कंपनियों से बल्कि वित्तीय सेवा उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रवेश कर रही बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों (बिगटेक) से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। डेटा-नेटवर्क की गतिविधियों की प्रकृति पुनर्नियोजन वाली होने के फायदों के आधार पर, कुछ बिगटेक-भुगतान, धन प्रबंधन, बीमा और उधार गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। वर्तमान में, वित्तीय सेवाएं, विश्व स्तर पर उनके व्यवसाय का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन, उनके आकार और पहुंच को देखते हुए, वित्तीय सेवाओं में उनके प्रवेश से वित्तीय क्षेत्र के परिदृश्य में तेजी से रूपांतरण की आशा है। बेशक, यह कई संभावित लाभ ला सकता है। बिग डेटा का उपयोग करते हुए, बिगटेक, उधारकर्ताओं के जोखिम का आकलन कर सकते हैं, जिससे कोलैट्रल की आवश्यकता कम हो जाती है। इसलिए, उनके कम लागत वाले संरचना व्यवसाय को आसानी से बैंक सेवा रहित आबादी को बुनियादी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ये घटनाक्रम बैंकों के साथ-साथ बैंकिंग नियामकों के लिए भी एक चुनौती हैं। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बैंकों को इन नई प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रथाओं का अनुकरण करना होगा।

दूसरी ओर, बैंकिंग नियामकों को नवाचार को बढ़ावा देने और एक मापित/आनुपातिक पर्यवेक्षी व विनियामकीय ढांचे को लागू करने के बीच संतुलन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन सभी का अर्थ है कि बैंकिंग का भविष्य अतीत की एक निरंतरता नहीं होगा। हम आने वाले वर्षों में संरचना और व्यवसाय मॉडल के संदर्भ में एक बहुत अलग बैंकिंग क्षेत्र देखेंगे।

सवाल यह है कि भारत में एक संभावित परिदृश्य क्या होगा? आने वाले वर्षों में बैंकिंग संस्थाओं के विशिष्ट क्षेत्र उभर सकते हैं। पहले खंड में वे बड़े भारतीय बैंक शामिल हो सकते हैं जिनकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति हो। इस प्रक्रिया को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के विलय से बढ़ाया जाएगा। दूसरे खंड में कई मध्य आकार की बैंकिंग संस्थाएं, जिनमें अर्थव्यवस्था की व्यापक उपस्थिति वाले प्रमुख बैंक हैं, शामिल हो सकते हैं। तीसरे खंड में निजी क्षेत्र के लघु बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को रखा जा सकता है, जो विशेष रूप से ग्रामीण/स्थानीय क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्रों में छोटे उधारकर्ताओं की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करते हों। चौथे खंड में वे डिजिटल सहभागी शामिल हो सकते हैं जो ग्राहकों से सीधे सेवा प्रदाताओं के रूप में या बैंकों के माध्यम से उनके एजेंट या एसोसिएट के रूप में कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से पुनःस्थापित बैंकिंग प्रणाली की खासियत बैंकों की निरंतरता होगी। बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत ग्राहक आधार के साथ पारंपरिक खिलाड़ी और नई तकनीक का नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे।

उभरते हुए परिदृश्य में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समुचित रूप से तैयार एकीकरण प्रस्ताव से कार्यबल और शाखाओं के आबंटन में तालमेल पैदा हो सकता है और साथ ही साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए परिचालन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुर्लभ पूंजी को दक्ष और युक्तिसंगत बनाए रखने में हुए महत्वपूर्ण सुधारों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रौद्योगिकी और कौशल निर्माण में निवेश को आगे बढ़ाना होगा। बड़े और फुर्तीले बैंक बेहतर प्रौद्योगिकी, कौशल और व्यावसायिक मॉडल से लैस होने के चलते बेहतर ब्रांडिंग अभ्यास के साथ खुद को पुनः मोर्चा संभालने में सक्षम बना सकते हैं।

⁴ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2019), 'वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट', जून।

अंततः, बैंकिंग प्रणाली की ताकत उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ताकत पर निर्भर करती है जो मजबूत और नैतिकता से प्रेरित अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देती है। इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निर्देश जारी करता रहा है। उदाहरण के लिए, बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों, सीईओ और भारी जोखिम लेने वालों के लिए मुआवजे के दिशानिर्देशों को भी काफी हद तक संशोधित किया गया है। बैंकों में बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले विचलन और धोखाधड़ी, उभरते जोखिमों के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बैंकों के भीतर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की भूमिका और प्रभावी उपयोग पर सवाल उठाए जाते हैं। श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य आंतरिक नियंत्रण कार्य-विधि को मजबूत करना है जो कि बोर्डों की लेखा परीक्षा समितियों को अधिक जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, अगस्त 2019 में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में जैसा कि संकेत दिया गया है तथा दिसंबर 2019 में प्रकाशित भारत में बैंकिंग की प्रगति और प्रवृत्ति पर रिपोर्ट 2018-19 में दोहराया गया है, आरबीआई बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मसौदा दिशानिर्देश भी जारी करेगा।

डिजिटल डिसरप्शन

संरचनात्मक परिवर्तनों के अलावा डिजिटल डिसरप्शन बैंकिंग क्षेत्र का रूपांतरण करना जारी रखेंगे। सरकार, रिज़र्व बैंक और उद्योगों द्वारा शुरू की गई पहल से सर्वव्यापी डिजिटलीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है जिसने प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए एक प्रोत्साहन दिया है। जनसांख्यिकीय लाभांश व जेएएम ट्रिनिटी आदि जैसे कई सकारात्मकताओं का अनूठा संगम, भारत में वित्तीय सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण में सहयोग करेगा।

अपने पारंपरिक व्यवसायों में जाने के साथ, बैंक- बीमा, आस्ति प्रबंधन, दलाली व अन्य सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रहे हैं। खुशी की बात है कि बैंकों की मानसिकता बदल रही है और वे फिनटेक फर्मों को हानिकारक नहीं मानते। दृष्टिकोण में इस बदलाव ने वित्तीय सेवा क्षेत्र को सुरक्षा की भावना दी है। इस बात के साक्ष्य हैं कि फिनटेक कंपनियां बैंकिंग परितंत्र में संबल प्रदाता के रूप में कार्य कर रही हैं। तकनीकी नवाचार को

अपनाने के लिए बैंक; फिनटेक कंपनियों में निवेश करने से लेकर अपनी फिनटेक सहायक कंपनियों की स्थापना करने, फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग करने तक, कई कार्यनीतियों पर भरोसा कर रहे हैं। बैंक और गैर-बैंक भारतीय उपभोक्ता को विश्वास और नवाचार के संयोजन की पेशकश करने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। इस “ दुनिया के दोनों सर्वश्रेष्ठ” दृष्टिकोण ने डिजिटल भुगतानों की संख्या में भारी वृद्धि की है, जो जारी रहने की उम्मीद है। ये कार्यनीति, प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित कर सकती है कि बैंक बाजार में अपना शेयर बनाए रखेंगे, क्योंकि ग्राहक तेजी से अधिक कुशल और किफायती सेवाओं को महत्त्व देते हैं।

इस विकास के आलोक में, पारंपरिक बैंकिंग डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगली पीढ़ी की बैंकिंग के लिए रास्ता बना रही है। पारंपरिक शाखाओं की आवश्यकता की समीक्षा की जा रही है क्योंकि डिजिटलीकरण ने शाब्दिक रूप से कहा जाए तो बैंकिंग को उंगलियों पर ला दिया है। इससे अधिकांश बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं रह गयी है।

डिजिटल भुगतान की दिशा में तेजी से भुगतान प्रणाली, जैसे कि तत्काल भुगतान सेवा (आइएमपीएस) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत की गई है जो लाभार्थियों को तत्काल क्रेडिट प्रदान करते हैं और चौबीसो घंटे उपलब्ध रहते हैं। डिजिटल पैठ की सीमा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि, भारत में भुगतान प्रणाली प्रत्येक दिन औसतन लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए से अधिक लेनदेन की प्रक्रिया पूर्ण करती है। आज, डिजिटल भुगतान की संख्या दैनिक भुगतान प्रणाली के कुल लेनदेन का लगभग 97 प्रतिशत है। यह पिछले पांच वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन की मात्रा में 50 प्रतिशत से अधिक की त्वरित वृद्धि के साथ संभव हुआ है।

रिज़र्व बैंक ने हाल ही में अपनी खुदरा भुगतान प्रणाली यथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) को 24 x7 के आधार पर संचालित करना शुरू कर दिया है। यह एक पासा पलट देने वाला खेल है और भारत को उन बहुत कम देशों में शरीक करता है, जो यह सुविधा प्रदान करते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक पेपर में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) ने उद्धृत किया है कि भारत का यूपीआई ढांचा न केवल देशों के अंदर बल्कि देशान्तर में भी त्वरित और सहज भुगतान की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है। डिजिटल भुगतान को

आगे बढ़ाने में हमारे अनुभव को समझने और जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों को काफी रुचि है और हमें इसे साझा करने और सहयोग करने में बहुत खुशी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई मॉडल को अन्य देशों में ले जाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सहयोगी संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है जो भारत की भुगतान प्रणालियों की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने में सहायता करेगा। खुदरा भुगतान के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, हमने अपनी वेबसाइट पर खुदरा भुगतान प्रणाली हेतु एक अखिल भारतीय न्यू अब्रंज एनटीटी (एनयूई) का एक मसौदा ढांचा भी जन साधारण की टिप्पणियों के लिए रखा है।

विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करना

इक्कीसवीं सदी में बैंकिंग क्षेत्र के निरंतर बढ़ते आयामों के संदर्भ में, हमें बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक गहन विनियामक और पर्यवेक्षी सुधारों के बारे में अवगत रहना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि वह अपने पर्यवेक्षी और विनियामकीय कार्यों की प्रभावकारिता में निरंतर सुधार लाए, ताकि विनियमित वित्तीय संस्थाओं के लचीलेपन को बढ़ाया जा सके। इस संबंध में हाल के दिनों में कई कदम उठाए गए हैं। हमने समन्वय को बेहतर बनाने और संसाधनों को बेहतर तरीके से आबंटित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से, रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण और विनियामक विभागों को पुनर्गठित किया है। पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से, यह प्रणालीगत और अज्ञात जोखिमों की पहचान में वृद्धि करेगा जो हमें ऑफ-साइट और ऑन-साइट पर्यवेक्षण टीमों के बीच तालमेल बनाने में मदद करेगा।

हम, जोखिमपूर्ण प्रथाओं और संस्थाओं पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने और अपने पर्यवेक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों और प्रौद्योगिकी की एक उपयुक्त श्रेणी को तैनात करने हेतु आवश्यक रूपात्मकता और मापनीयता लाने के लिए, एक जांचा परखा पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का भी पालन कर रहे हैं। हम अपने ऑन-साइट पर्यवेक्षण के लिए सहायक के रूप में एक कुशाग्र और अधिक दूरदर्शी ऑफ-साइट निगरानी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एकीकृत अनुपालन प्रबंधन और ट्रेकिंग प्रणाली के एक भाग के रूप में एक सुपर-टेक पहल को लागू किया जा रहा है। यह वेब-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से पर्यवेक्षित संस्थाओं के सभी लंबित अनुपालनों की पारदर्शी और कुशल निगरानी की सुविधा

प्रदान करेगा, निरीक्षण योजना प्रक्रिया और साइबर घटना रिपोर्टिंग को स्वचालित करेगा और डेटा का सहज संग्रह सुनिश्चित करेगा। बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में विषयगत अध्ययन किए जाएंगे। समय-समय पर पर्यवेक्षण के नए तत्व भी पेश किए जाएंगे। प्रस्तावित अनुसंधान और नीति प्रभाग और जोखिम विशेषज्ञ प्रभाग इस प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रणालीगत महत्व और वित्तीय प्रणाली के साथ उनके इंटर-लिंकेज को उचित रूप से पहचान देते हुए, रिजर्व बैंक ने उनकी आस्ति की गुणवत्ता और नकदी से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। 01 अगस्त, 2019 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन ने रिजर्व बैंक को एनबीएफसी के संचालन में रचनात्मक हस्तक्षेप करने के लिए और अधिक सशक्त बनाया है। शीर्ष 50 एनबीएफसी, जिनमें 5000 करोड़ रुपए से अधिक के आस्ति आकार की सभी एनबीएफसी शामिल हैं, की आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) की स्थिति और अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शीर्ष 51-100 एनबीएफसी के एएलएम की भी जांच की जा रही है।

पर्यवेक्षण के चार स्तंभों अर्थात साइट पर निरीक्षण, ऑफ-साइट सर्विलांस, मार्केट इंटेलिजेंस और सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की रिपोर्ट के अलावा, सभी हितधारकों - सांविधिक लेखा परीक्षकों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, क्रेडिट सूचना कंपनियों, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी में बड़े एक्सपोजर वाले बैंकों के साथ समय-समय पर चर्चा के रूप में पांचवां स्तंभ - सेक्टर में उभरते जोखिमों और विकास की एक स्पष्ट समझ रखने के लिए स्थापित किया गया है, ताकि जब भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके।

जहां तक सहकारी बैंकिंग खंड का संबंध है, हमने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एक मजबूत दबाव-परीक्षण ढांचा विकसित किया है। यह समुचित कार्रवाई के लिए कमजोर बैंकों की समय पर पहचान के उद्देश्य से सहकारी बैंकों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है। पर्यवेक्षी दृष्टि से यह प्रतिक्रियात्मकता से सकारत्मकता की ओर हुआ बदलाव है जिसका ध्येय निरंतरता आधार पर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में कमजोरियों की निगरानी सुनिश्चित करना है। 31 दिसंबर, 2019 तक, इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक बैंक अब कोर बैंकिंग

सॉल्यूशन (सीबीएस) में हैं, हालांकि अभी भी समाधानों को मानकीकृत करने की आवश्यकता है और बेहतर परिणामों के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में मजबूत आंतरिक नियंत्रण सेट की आवश्यकता है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए कैमल्स (पूजी पर्याप्तता, आरिस्त गुणवत्ता, प्रबंध, अर्जन, चलनिधि, प्रणाली एवं नियंत्रण) पर्यवेक्षी रेटिंग पद्धति को भी व्यापक स्तर पर संशोधित किया गया है। हमने सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों को लाने के लिए भी कदम उठाए हैं और क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम को खत्म करने व भावी वित्तीय समावेशन हेतु प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण के लक्ष्यों को बढ़ाने के प्रयोजन से एक्सपोजर नॉम्स पर ड्राफ्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन में सुधार के लिए, हमने 100 करोड़ रुपये या इससे बड़े के जमा आकार वाले यूसीबी के लिए प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के गठन पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अन्य छोटे यूसीबी द्वारा इसे अपना स्वैच्छिक रखा गया है। सहकारी बैंकों के संबंध में आरबीआई को, बैंकिंग कंपनियों के विषय में प्राप्त शक्तियों के समान ही, उपयुक्त विनियामक शक्तियां देने हेतु, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

IV भावी दिशा

एक मजबूत विनियामक और पर्यवेक्षी शासन की पृष्ठभूमि में बैंकों की बढ़ी सघनता और तकनीक-युक्त पर्यवेक्षण के साथ बैंकिंग उद्योग का बदलता परिदृश्य सामने आएगा। बैंकों के सामने

चुनौती अपनी आधार रेखा की रक्षा करते हुए मध्यवर्ती लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का सबसे अच्छा उपयोग करने की है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और बिग डेटा वित्तीय सेवाओं के नवाचार का केंद्र बनते जा रहे हैं। बड़े डेटासेट को संसाधित करने से वे धोखाधड़ी का पता लगाने और उधारकर्ताओं द्वारा धन के उपयोग की निगरानी के बेहतर तरीकों की पहचान करने, संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने आदि में मदद कर सकते हैं।

नीति निर्माताओं के लिए, विशेष रूप से भारत जैसे देशों में एक चुनौती बैंकिंग क्षेत्र में नए नवाचार, वित्तीय सेवाओं की लागत को कम करना और सीमा व उत्पादों तक पहुंच को सुरक्षित तरीके से बढ़ाकर ग्राहक की सेवा करना है। उभरते साइबर सुरक्षा जोखिमों का उन्नत विश्लेषण और उनकी वास्तविक समय आधार पर निगरानी इसके संभावित खतरों का पता लगाने और पूर्व एहतियाती कार्रवाई को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

जैसा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र एक उच्च कक्षा की ओर अग्रसर है, बैंकों को अपनी व्यावसायिक कार्यनीतियों को फिर से बनाने, ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को डिजाइन करने और उनकी दक्षता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करके बदले हुए आर्थिक परिवेश में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी सेवाओं पर कड़ी मेहनत करनी होगी। संभावनाएं बड़ी हैं। हमें मुद्दों को रोक कर समय रहते कार्रवाई करनी होगी।

लेख

भारत में मौद्रिक नीति संचरण –
हालिया प्रवृत्तियाँ और बाधाएं

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग :
चुनौतियां और संभावनाएं

भारत में मौद्रिक नीति संचरण – हालिया प्रवृत्तियाँ और बाधाएं *

यह लेख भारत में वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक नीति संचरण का परीक्षण करता है और विशेष रूप से फरवरी 2019 से लगातार जारी मौद्रिक नरमी के चक्र में बैंकों की जमा और ब्याज दरों पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गयी है। जहाँ मुद्रा बाजार और दीर्घावधि दरों में यह संचरण बहुत तेजी से और लगभग पूरी तरह हुआ है, वहीं जमा और उधार दरों में संचरण धीमा रहा है। बैंकों की उधार दरों में त्वरित और पर्याप्त संचरण को बाधित करने वाला एक प्रमुख कारक लंबी परिपक्वता अवधि वाले जमाओं का बड़ी संख्या में होना भी है। अन्यथा भी, बैंक अपनी जमा ब्याज दरों को समायोजित करने में धीमे हैं। 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी बाह्य बेंचमार्क प्रणाली के तहत, कुछ चुनिंदा प्रकार के ऋणों में यह संचरण अब जमा दरों में किए जाने वाले समायोजन पर निर्भर नहीं रहा है। बल्कि उधार दरों में होने वाले परिवर्तनों के इसके बजाय, जमा ब्याज दरों में बदलाव उधार दरों में हुए परिवर्तनों से प्रेरित होगा।

परिचय

मौद्रिक संचरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत दरों में परिवर्तन के रूप में दिए जाने वाले मौद्रिक नीति आवेगों का संचरण सभी प्रकार की ब्याज दरों में होता है, जैसे मुद्रा बाजार दरें, बॉन्ड प्रतिफल, बैंक जमा और उधार दरें और स्टॉक तथा आवास जैसी आस्तियों की कीमतों। अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटक यथा हाउसहोल्ड्स, फर्म और सरकार अपने खर्च के तौर-तरीकों को तदनु रूप समायोजित करते हैं। इससे समग्र मांग में बदलाव आता है और इस परिवर्तन को कुल आपूर्ति के साथ संरेखित करते हुए मूल्य स्थिरता हासिल करना और अर्थव्यवस्था की विकास दर को वहनीय बनाए रखना जैसे समष्टि आर्थिक नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है।

* यह लेख मौद्रिक नीति विभाग के अर्घ्य कुसुम मित्र और साधन कुमार चट्टोपाध्याय द्वारा तैयार किया गया है। लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और उस संस्था के नहीं जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। लेखक जॉइस जॉन और कृष्णा एम. कुशवाहा द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को स्वीकार करते हैं। आंकड़ों के संकलन में अवनीश कुमार, सुलभा नादागौडा, सुनील बी. सावंत और नीलेश दलाल द्वारा प्राप्त सहयोग के प्रति लेखक आभारी हैं।

भारत जैसे देश में, जहां बैंकिंग व्यवस्था वित्तीय प्रणाली का एक प्रमुख घटक है, बैंकों की जमा और उधार दरों में नीतिगत दरों का प्रभावी संचरण मौद्रिक नीति के व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने की कुंजी होता है। तथापि, ऐसे अनेक कारक हैं जो भारत में बैंकों की उधार दरों में संचरण में बाधा डालते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं नियत ब्याज दरों वाले दीर्घावधि परिपक्वता की जमाराशियाँ।

यह लेख मौजूदा मौद्रिक नरमी वाले दौर (फरवरी 2019 - जनवरी 2020) में वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक नीति के संचरण का आकलन करता है, जिसमें बैंकों की जमा और ब्याज दरों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इस दौरान, पॉलिसी रेपो दर में कुल मिलाकर 135 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की गयी और मौद्रिक नीति के रुख को फरवरी 2019 में नपी-तुली सख्ती से तटस्थ कर दिया गया और फिर जून 2019 में यह निभावकारी हो गया।

इस अध्ययन को छह भागों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। भाग II जहाँ संक्षेप में मुद्रा बाजार और बांड बाजार प्रतिफल में मौद्रिक नीति के संचरण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, वहीं भाग III वाणिज्यिक बैंकों की जमा और उधार दरों में इसके संचरण का आकलन करता है। भाग IV में भारत में मौद्रिक नीति के संचरण में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की गयी है। अनुभाग V ऋणों का कीमत निर्धारण आंतरिक बेंचमार्क की बजाय बाह्य बेंचमार्क के जरिए कराने के फायदों का संक्षिप्त ब्योरा प्रस्तुत करता है। भाग VI में प्रमुख निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कुछ निर्णायक टिप्पणियाँ की गयी हैं।

II. मुद्रा और बॉण्ड बाजार में संचरण

मौद्रिक नरमी वाले दौर में अब तक मुद्रा बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में और निजी कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में मौद्रिक नीति का संचरण पूरी तरह और पर्याप्त तेजी से हुआ है। उदाहरण के लिए, भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूसीआर) में नीतिगत दरों में परिवर्तन का संचरण तत्क्षण हुआ। मुद्रा बाजार के अन्य घटकों – त्रिपक्षीय रेपो दर और बाजार रेपो दर- में यह संचरण काल मनी दरों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हुआ। द्वितीयक बाजार में अल्पकालिक मुद्रा बाजार के लिखत जैसे 3-महीने के जमा प्रमाणपत्र (सीडी), 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और 91-

दिवसीय ट्रेजरी बिल (टी-बिल) में परिवर्तन नीतिगत दरों के अनुरूप ही हुए। कुल मिलाकर, 6 फरवरी 2019 से 31 जनवरी 2020 के दौरान नीतिगत दर में हुई 135 आधार अंकों की कुल गिरावट की तुलना में 3-माह टी-बिल के प्रतिफल में 144 आधार अंकों की गिरावट हुई। इसी तरह, 3-महीने की सीडी दर में 167 बीपीएस की गिरावट आई, जबकि गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) तथा गैर-एनबीएफसी द्वारा जारी 3-महीने के सीपीसी पर प्रतिफलों में क्रमशः 190 बीपीएस और 140 बीपीएस की गिरावट आई। हालांकि, सरकारी प्रतिभूति बाजार में यह संचरण अंशिक रहा और 5 वर्ष और 10-वर्ष की जी-सेक के प्रतिफलों में क्रमशः 74 बीपीएस और 76 बीपीएस की गिरावट के साथ आंशिक था। मौद्रिक नरमी की इस पूरी अवधि में कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल और पॉलिसी रेपो रेट के बीच स्प्रेड मोटे तौर पर स्थिर बना रहा, जो कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफलों में पॉलिसी रेपो दर का पूर्ण संचरण होने को दर्शाता है।

ओवरनाइट सेगमेंट में नीतिगत दरों का संचरण जहाँ निर्बाध, तत्काल और लगभग पूर्ण रूप से हुआ, वहीं लंबी अवधि की मुद्रा बाजार दरों और बॉन्ड बाजार के प्रतिफलों में इसका संचरण कई बार बाजार की खामियों के चलते और कई अन्य विचित्र कारणों जैसे क्रेडिट जोखिम के प्रति बदलती धारणाओं, बनती-बिगड़ती राजकोषीय स्थितियों और लेट की कीमतों में उतार-चढ़ाव से यह प्रभावित हुआ। उदाहरण के लिए, जून-

जुलाई 2019 के दौरान कुछ चुनिंदा एनबीएफसी द्वारा जारी सीपी की रेटिंग डाउनग्रेड किए जाने से सीपी मार्केट में संचरण को प्रभावित किया। इसी तरह, कुछ बैंकों के तुलन-पत्रों से जुड़ी चिंताओं के कारण सीडी में भी इसके संचरण में समय-समय बाधाएं आयीं। फरवरी और मध्य सितंबर 2019 के बीच (13 सितंबर, 2019 को समाप्त पखवाड़ा), ऋणों में वृद्धि जमा में वृद्धि से अधिक तेजी से होने लगी जिससे सीडी दरें बढ़ने का दबाव बना। इसी तरह, 2019 की पहली छमाही के दौरान तेल की कीमतों में गिरावट और मुद्रास्फीति कम रहने की उम्मीद ने लंबी अवधि के बॉन्ड पर प्रतिफल में कमी आयी। जुलाई के मध्य से सितंबर तक की अवधि में stimulus दिए जाने की आशंकाओं और घरेलू/भू-राजनीतिक तनाव की आशंका से राजकोषीय स्थिति कमजोर होने से जुड़ी चिंताओं के कारण दीर्घावधि प्रतिफलों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। 6 फरवरी 2020 को जिन अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपायों, यथा अपेक्षाकृत अधिक अवधि के 1-वर्ष और 3-वर्ष के रेपो की शुरुआत किए जाने से बाण्डों पर प्रतिफल कम हो गया।

दैनिक द्वितीयक बाजार के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, यह देखा गया है कि एक तरफ पॉलिसी रेपो दर और दूसरी तरफ एकदिवसीय दरों यथा, डब्ल्यूएसीआर, बाजार रेपो दर तथा त्रिपक्षीय रेपो दर के बीच सहसंबंध गुणांक 0.90 से 0.98 रहा (सारणी 1)। पॉलिसी दर और अन्य मुद्रा बाजार दरों जैसे

सारणी 1 : मुद्रा बाजार दरें और जी-सेक तथा कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल – सहसंबंध का स्वरूप
(फरवरी 2019 से जनवरी 2020)

लिखत	नीतिगत रेपो दर	डब्ल्यूएसीआर	बाजार रेपो	त्रिपक्षीय रेपो	3मा.टी-बिल	3 मा. सीडी	3 मा. सीपी-एनबीएफसी	5-वर्ष जी-सेक	5 वर्ष एए कॉर्पोरेट बॉण्ड	10 वर्ष जी-सेक	10 वर्ष एए कॉर्पोरेट बॉण्ड
नीतिगत रेपो दर	1.00	0.98	0.90	0.96	0.87	0.98	0.95	0.87	0.95	0.88	0.89
डब्ल्यूएसीआर		1.00	0.89	0.96	0.86	0.97	0.94	0.86	0.96	0.89	0.89
बाजार रेपो			1.00	0.90	0.72	0.88	0.86	0.72	0.84	0.76	0.78
त्रिपक्षीय रेपो				1.00	0.83	0.96	0.92	0.83	0.92	0.84	0.86
3 मा. टी-बिल					1.00	0.90	0.86	1.00	0.92	0.95	0.92
3 मा. सीडी						1.00	0.97	0.90	0.97	0.90	0.90
3 मा. सीपी- एनबीएफसी							1.00	0.86	0.94	0.86	0.86
5-वर्ष जी-सेक								1.00	0.92	0.95	0.92
5 वर्ष एए कॉर्पोरेट बॉण्ड									1.00	0.93	0.95
10 वर्ष जी-सेक										1.00	0.95
10 वर्ष एए कॉर्पोरेट बॉण्ड											0.97

मा. : माह

स्रोत : भा. रि. बैंक, ब्लूमबर्ग, लेखकीय गणना.

3-महीने के सीपी, सीडी और टी-बिल के सहसंबंध गुणांक भी काफी अधिक थे (0.87 से 0.98)। पॉलिसी रेपो दर और 5-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल के बीच सहसंबंध गुणांक 0.87 रहा, जबकि वह पॉलिसी रेपो दर और 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बांड प्रतिफल के बीच 0.95 था। इसके अलावा, इसी अवधि में 10-वर्षीय जी-सेक और 10-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल के लिए सहसंबंध गुणांक 0.88 और 0.89 पाए गए। पॉलिसी दर के साथ मुद्रा और बांड बाजार दरों के सहसंबंध गुणांक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण थे।

फरवरी 2019 - जनवरी 2020 की अवधि के लिए साप्ताहिक आंकड़ों के आधार पर प्रतिगमन विश्लेषण से पता चलता है कि नीतिगत दर और बाजार दरों के बीच सहगामी संबंध है। हालाँकि, त्रुटि माप में मानक विचलन भी काफी देखा गया जिससे इस बात की ओर संकेत मिलता है कि नीतिगत दरों के अतिरिक्त भी कुछ कारक ऐसे हैं जो संचरण को प्रभावित करते हैं (सारणी 2)। इसी वजह से, नीतिगत दर और बाजार दरों, विशेष रूप से बड़े छोर पर स्थित, के सहसंबंध गुणांक, 1 से कम पाए गए (सारणी 1)।

**सारणी 2 : मौद्रिक नीति संचरण :
प्रतिगमन विश्लेषण**

आश्रित चर (Y)	रेपो दर का गुणांक (X)	त्रुटि का मानक विचलन (ε)
डब्ल्यूएसीआर	0.982*	0.166*
त्रिपक्षीय रेपो	0.956*	0.269*
बाजार रेपो	0.958*	0.307*
3मा.टी-बिल	1.002*	0.237*
3 मा. सीडी	1.087*	0.430*
सीपी- 3 मा. एनबीएफसी	1.159*	0.399*
5-वर्ष जी-सेक	1.172*	0.213*
5 वर्ष एएए कॉर्पोरेट बॉण्ड	1.353*	0.170*
10 वर्ष जी-सेक	1.208*	0.217*
10 वर्ष एएए कॉर्पोरेट बॉण्ड	1.419*	0.259*

प्रतिगमन समीकरण है $Y = BX + \epsilon$, जहाँ X नीतिगत रेपो दर है और Y मुद्रा/बॉण्ड बाजार चरों पर ब्याज-दर है।

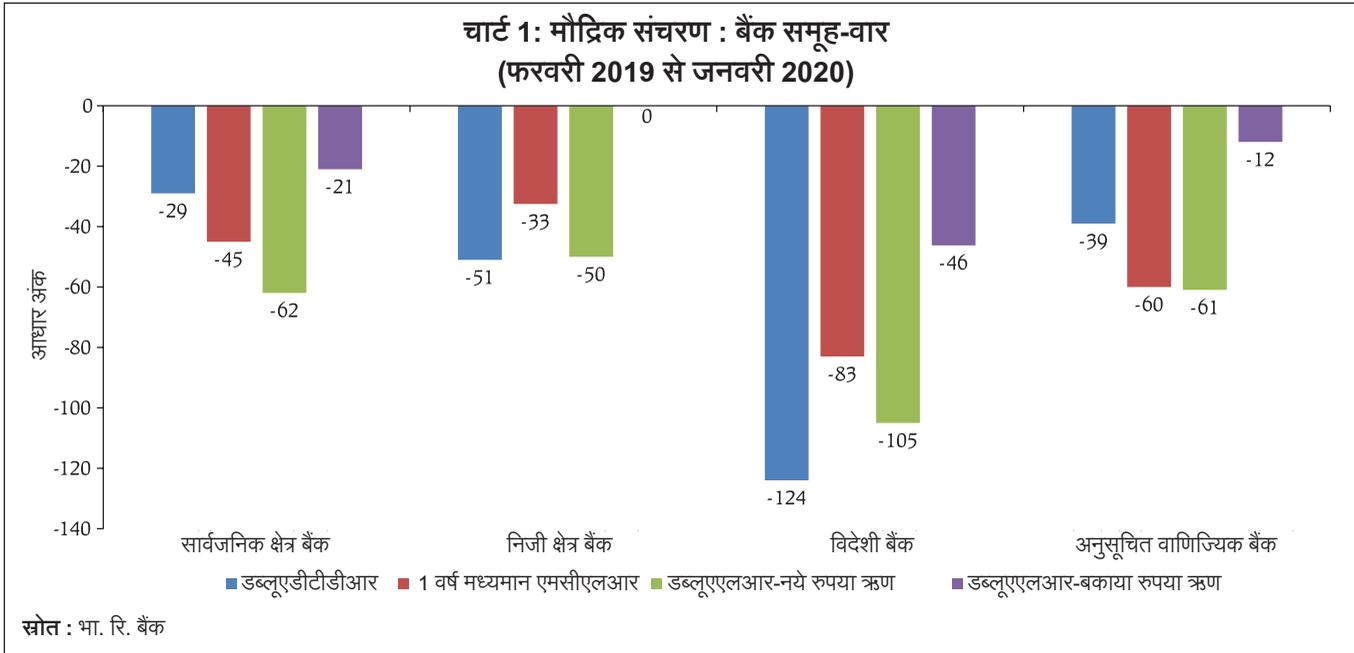
*: 1 प्रतिशत पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण।

III. जमा और उधार ब्याज दरों में संचरण

फरवरी 2019 से नीतिगत रेपो दर में संचयी रूप से 135 बीपीएस की कमी के प्रभाव स्वरूप, अधिकांश बैंकों ने अपनी सावधि जमा दरों में कमी की है; कुछ बैंकों ने अपनी बचत जमा ब्याज दरों में भी कमी की। बकाया जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में गिरावट सितंबर 2019 तक नगण्य रही। तथापि, खुदरा और सूक्ष्म और लघु नए उद्यमों (MSE) के फ्लोटिंग ऋणों की दरों को किसी बाह्य बेंचमार्क से जोड़ने की शुरुआत, जो 01 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुई, के बाद से डब्ल्यूएडीटीडीआर में अक्टूबर 2019 - जनवरी 2020 के दौरान 32 आधार अंकों की तीव्र गिरावट दर्ज की गयी, जबकि पिछले आठ महीनों में कुल मिलाकर सिर्फ 7 आधार अंकों की गिरावट हुई थी। कुल मिलाकर, फरवरी 2019 और जनवरी 2020 के बीच डब्ल्यूएडीटीडीआर में 39 बीपीएस की गिरावट की। फरवरी 2019 से जनवरी 2020 के दौरान नये रुपया ऋणों पर भारित औसत ऋण दर (डब्ल्यूएएलआर) में 61 आधार अंकों की गिरावट हुई जबकि बकाया रुपया ऋणों के मामले में यह गिरावट 12 आधार अंकों की रही।

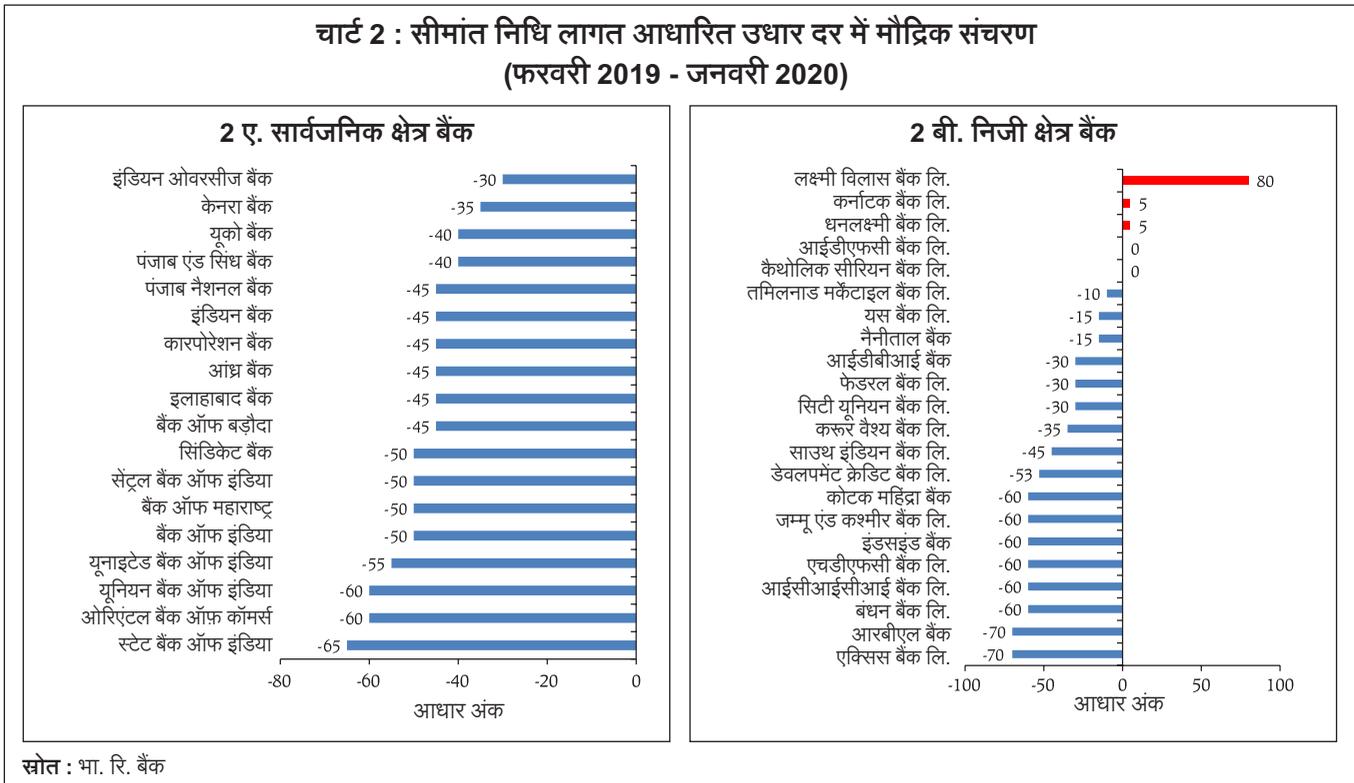
बैंक समूह स्तर पर देखें तो, जमा और उधार दरों में यह संचरण असमान रहा है, जिसके पीछे कई विचित्र कारक रहे हैं। डब्ल्यूएडीटीडीआर की बात करें तो विदेशी बैंकों के मामले में सबसे बड़ी गिरावट (124 बीपीएस) देखी गई, इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक (51 बीपीएस) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (29 बीपीएस) रहे। नये रुपया ऋणों के मामले में, सर्वाधिक गिरावट (105 बीपीएस) विदेशी बैंकों में रही और उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (62 बीपीएस) और निजी क्षेत्र के बैंकों (50 बीपीएस) का स्थान रहा। बकाया रुपया ऋणों की बात करें तो, गिरावट के मामले में विदेशी बैंक (46 बीपीएस) अक्वल रहे (चार्ट 1)।

अलग-अलग स्तर पर देखा जाए तो, 74 बैंकों ने अपनी 1-वर्ष सीमांत निधि-लागत आधारित उधार दरों (एमसीएलआर) में कटौती की जबकि 5 बैंकों ने अपनी 1-वर्ष एमसीएलआर बढ़ा दी। जहाँ 18 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और 17 निजी क्षेत्र के बैंकों ने एमसीएलआर घटाई वहीं तीन निजी क्षेत्र के बैंकों ने अपनी 1-वर्ष एमसीएलआर बढ़ा दी (चार्ट 2)।



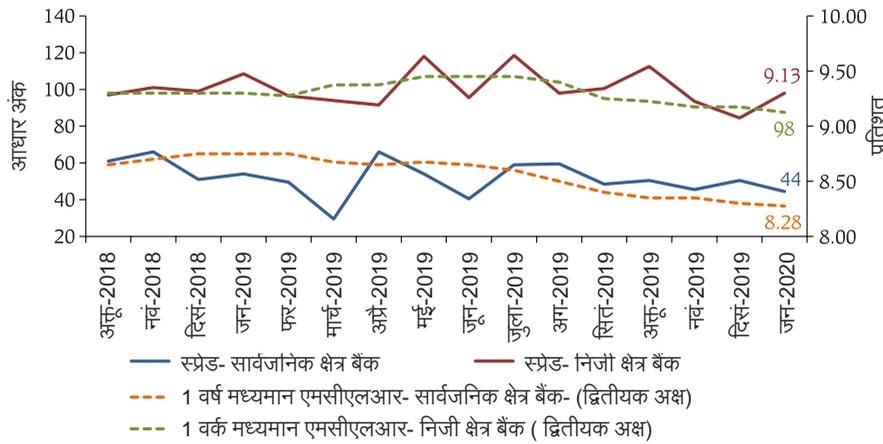
निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूली जाने वाली डब्ल्यूएलआर का मध्यमान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक था क्योंकि उनकी 1-वर्ष एमसीएलआर का मध्यमान अधिक था और साथ ही, वे एमसीएलआर पर अपेक्षाकृत अधिक स्प्रेड

वसूलते थे (चार्ट 3)¹। अधिक एमसीएलआर होने का मतलब है निधि लागत का अधिक होना जबकि स्प्रेड अधिक होना ऋण पोर्टफोलियो की विविधता और उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। कुल मिलाकर, बैंक ऋण दरों में संचरण, विशेष रूप से बकाया



¹ स्प्रेड को डब्ल्यूएलआर के रूप में परिभाषित किया गया है जो 1-वर्ष एमसीएलआर की तुलना में नए रुपया ऋणों पर लगायी जाती है।

चार्ट 3: मध्यमान स्प्रेड – 1-वर्ष एमसीएलआर पर डब्लूएलआर (नये ऋण)



जनवरी 2020	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	निजी क्षेत्र बैंक
मध्यमान एमसीएलआर (%)	8.28	9.13
एमसीएलआर पर स्प्रेड का मध्यमान (बीपीएस)	44	98
मध्यमान डब्लूएलआर (%)	8.63	9.77

टिप्पणियां : (i) क्योंकि विदेशी बैंकों के तुलना पत्रों का आकार छोटा होता है, अतः इन बैंकों के संबंध में स्प्रेड दर्शाया नहीं गया है।

(ii) बैंक ग्रुप का मध्यमान स्प्रेड उस समूह में शामिल प्रत्येक बैंक के स्प्रेड (डब्लूएलआर और 1-वर्ष एमसीएलआर का अंतर) से ज्ञात किया गया है।

स्रोत : भा. रि. बैंक

रुपया ऋणों में ना काफ़ी था यद्यपि हालिया अवधि में कुछ सुधार आया है।

IV. बैंकों की जमा और उधार ब्याज दरों में मौद्रिक नीति संचरण – बाधाएं

बैंक ऋण ब्याज दरों में मौद्रिक संचरण कई कारकों से प्रभावित होता है: अंतर्जात, जो बैंकिंग प्रणाली के नियंत्रण में हैं; और बहिर्जात, जो बैंकिंग प्रणाली के नियंत्रण में नहीं हैं, जिनका ब्योरा नीचे प्रस्तुत है।

IV.1 नियत ब्याज-दरों वाली जमाराशियों का दीर्घकालिक परिपक्वता प्रोफ़ाइल

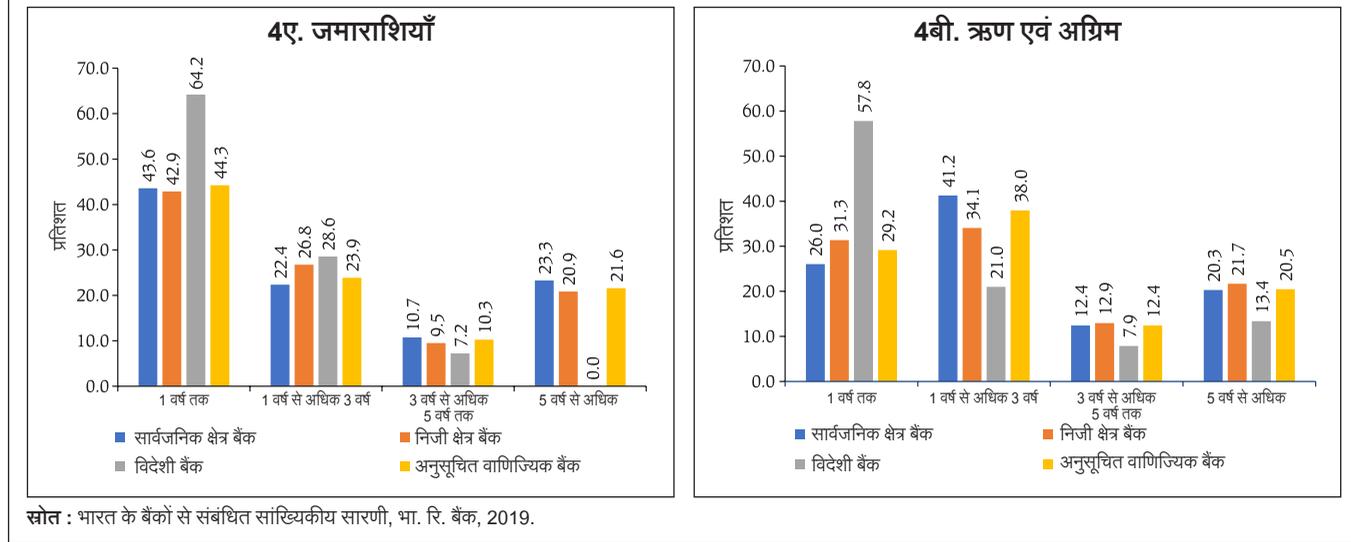
एमसीएलआर प्रणाली मुख्य रूप से निधि - इक्विटी और उधार राशियाँ (बैंकों के जमा और अन्य उधार)- की लागत पर आधारित होता है।² चूंकि बैंकों की निधियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुदरा जमाराशियाँ होती हैं, अतः बैंकों की एमसीएलआर में संचरण बहुतायत में इन जमाराशियों की लागत में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। हालांकि, बैंकों की निधियों की लागत दो कारणों से अपरिवर्तित रहती है : (i) बैंकों की जमाराशि की परिपक्वता लंबी होना; और (ii) ऐसी जमा राशियों पर ब्याज दर नियत होना। मार्च 2019 के अंत तक, जो आंकड़ों की उपलब्धता के लिहाज से अद्यतन अवधि है, वाणिज्यिक बैंकों के आधे से

अधिक डिपॉजिट 'एक वर्ष और उससे अधिक' परिपक्वता अवधि वाले समूह में थे, और 20 प्रतिशत से अधिक जमा की परिपक्वता अवधि 'पाँच वर्ष और उससे अधिक' थी (चार्ट 4 ए)।³ लंबी परिपक्वता प्रोफ़ाइल अपने आप में मौद्रिक संचरण को बाधित नहीं करती, बशर्ते ऐसी जमाओं पर ब्याज दर नीतिगत दर के अनुरूप ही परिवर्तित हो। हालांकि, लगभग सभी बैंक जमा नियत ब्याज दरों वाले हैं। इससे बैंकों की बकाया देयता प्रोफ़ाइल नीतिगत दर में परिवर्तन के प्रति असंवेदनशील हो जाती है। हालांकि, विशेष रूप से संचरण में बाधा की बात करें तो यह मौद्रिक सख्ती के चक्र की तुलना में मौद्रिक नरमी के चक्र में अधिक देखी जाती है। सख्ती के चक्र में जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो जमाकर्ताओं के पास यह विकल्प होता है कि वे समय से पहले अपनी जमाराशि का मोचन कराते हुए इसे उच्चतर ब्याज-दर पर फिर से नियोजित कर दें। बैंकों के पास भी यह विकल्प होता है कि वे जमा ब्याज दरों में वृद्धि करने से पहले क्रेडिट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उधार दरें बढ़ा सकें। दूसरी ओर, सहजता चक्र के दौरान, बैंकों को उच्चतर ब्याज दरों पर करार की गयी जमाराशियों के परिपक्व होने तक इंतजार करना पड़ता है और उन्हें कम दरों पर नवीनीकृत किया जाता है, जिसके कारण उधार दरों में संचरण की गति कम हो जाती है।

² एमसीएलआर के अन्य घटक हैं - नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) पर ऋणात्मक धारण-प्रतिफल, परिचालन लागत और परिपक्वता-अवधि प्रीमियम।

³ जमाराशियों और ऋणों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल में किसी उल्लेखनीय बदलाव की उम्मीद नहीं है, विशेष रूप से अल्पावधि में।

चार्ट 4: जमाराशियों और ऋणों की परिपक्वता स्थिति – मार्च 2019



जब अर्थव्यवस्था मौद्रिक सख्ती के चक्र से नरमी के चक्र में जाने लगती है तो अधिकतम सख्ती की अवधि में अनुबंधित जमाओं के कारण नरमी के चक्र में प्रारंभिक महीनों में जमाराशियों का औसत अधिक बना रहता है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र बैंकों के मामले में ज्यादा प्रभावी तरीके से देखा जा सकता है क्योंकि उनके कुल जमा के 20 प्रतिशत से अधिक जमा ऐसा है जिसकी परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष और इससे अधिक है जबकि इसके विपरीत, विदेशी बैंक में पाँच वर्ष और इससे अधिक परिपक्वता वाली जमाराशि का हिस्सा नगण्य है।

जमा के विपरीत, जो कि नियत दरों पर होते हैं, ऋणों का अधिकांश हिस्सा (75 प्रतिशत से अधिक) परिवर्तनशील दरों पर होते हैं (सारणी 3)। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की परिपक्वता प्रोफाइल लंबी अवधि के ऋणों (एक वर्ष और अधिक) की ओर झुकी होती है, जबकि

विदेशी बैंकों की छोटी अवधि (एक वर्ष तक) की ओर (चार्ट 4 बी)। फ्लोटिंग दरों वाले ऋणों का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वे मौद्रिक संचरण को सुलभ बनाते हैं। हालांकि, उधार दरों में संचरण, भले ही वे नियत ब्याज दरों पर दिए गए हों, लंबी परिपक्वता प्रोफाइल वाले जमा के कारण बाधित होता है।

मौद्रिक नरमी के वर्तमान चक्र (जनवरी 2020 तक) के दौरान नये सावधि जमा पर औसत ब्याज दर (कार्ड की दर) के मध्यमान में 31 बीपीएस की संघी कमी आयी। अब सवाल यह है कि बैंक अपनी जमा ब्याज दरों को समायोजित करने में धीमे क्यों रह जाते हैं। एमसीएलआर प्रणाली के तहत, बैंकों को एमसीएलआर की गणना करते समय बैंकों से यह अपेक्षित होता है कि वे कार्ड जमा दर पर कोई भी परिवर्तन लागू करें। एमसीएलआर का कार्यकाल आम तौर पर एक वर्ष होता है, जबकि घरेलू बैंकों की जमा राशि की भारित औसत परिपक्वता

सारणी 3: नियत और परिवर्तनशील ब्याज दरों वाले ऋणों की हिस्सेदारी - बैंक समूह-वार

(प्रतिशत हिस्सेदारी)

बैंक समूह	नियत दर ऋण				परिवर्तनशील दर ऋण			
	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	दिसं.-19	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	दिसं.-19
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (14)	15.5	13.8	13.9	14.9	84.5	86.2	86.1	85.1
निजी क्षेत्र बैंक (13)	37.0	37.1	39.1	39.9	63.0	62.9	60.9	60.1
विदेशी बैंक (23)	33.3	33.2	32.7	31.9	66.7	66.8	67.3	68.1
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (50)	23.2	21.8	22.9	24.0	76.8	78.2	77.1	76.0

नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े बैंकों की संख्या दर्शाते हैं।

स्रोत : बैंकों से जुटायी गयी सूचना।

लगभग दो वर्ष होती है। एमसीएलआर और जमाराशियों की औसत अवधि में इस बेमेल को देखते हुए, कार्ड दरों में किसी भी प्रकार की कमी लागू किए जाने के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा एमसीएलआर में की गयी किसी भी कमी का लाभ फ्लोटिंग दरों वाले लगभग सभी जबकि केवल 50 प्रतिशत सावधि जमाओं पर ही ब्याज दर 01 वर्ष के भीतर पुनः तय करनी होगी (औसत परिपक्वता अवधि दो वर्ष को देखते हुए⁴)। यानी फ्लोटिंग दरों वाले ऋण पर ब्याज दरें सावधि जमा पर ब्याज दरों की तुलना में तेजी से रीसेट होती हैं। इसलिए, बैंक अपनी जमा ब्याज दरों में बड़े बदलाव नहीं करना चाहते। यदि बैंक अपनी जमा ब्याज दरों में बड़े बदलाव करते हैं, तो उनके शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को धक्का लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उदाहरण के लिए, दर में 25 बीपीएस कटौती का लाभ लगभग सभी फ्लोटिंग दर ऋणों पर एक वर्ष के भीतर पहुंचाना होगा, परंतु बैंकों को अपनी बकाया जमा राशि पर इस कमी का लाभ प्राप्त करने के लिए दो साल तक इंतजार करना होगा। बैंक मौजूदा जमाओं पर नई कार्ड दरें तभी लागू कर सकते हैं जब वे परिपक्वता के उपरांत नवीकरण के योग्य हो जाते हैं। यही वह समय होता है जब बैंकों की निधि-लागत में भारी गिरावट आती है और तब इसका प्रभाव उधार दरों पर पड़ता है, परंतु इस पूरी प्रक्रिया में मौद्रिक नीति संचरण में विलंब हो जाता है।

IV.2 बचत जमा ब्याज दर का अपरिवर्तित बने रहना⁵

हालांकि, रिजर्व बैंक ने बचत बैंक जमा पर ब्याज दरों को विनियमन से मुक्त करने का निर्णय ले लिया था, जो 25 अक्टूबर 2011 से प्रभावी हुआ, ज्यादातर बैंकों ने लगभग छह वर्षों की लंबी अवधि तक अपनी बचत जमा ब्याज दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा, हालांकि इस दौरान नीतिगत दरों में वृद्धि और कमी दोनों हुईं। उदाहरण स्वरूप, सितंबर 2013 के अंत तक, केवल 18 बैंकों - 7 निजी क्षेत्र के बैंक और 11 विदेशी बैंक - जिनकी बाजार हिस्सेदारी कुल जमा में सिर्फ 5.3 प्रतिशत थी, ने विनियमन समाप्त होने के बाद अपनी बचत जमा ब्याज दर में कमी

⁴ इसका यह मतलब नहीं है कि सभी जमाराशियाँ दो साल में परिपक्व हो जाएंगी - बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल की परिपक्वता अवधि के लिए सावधि जमा का विकल्प देते हैं, जिनकी औसत परिपक्वता अवधि दो साल होती है।

⁵ जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस खंड में की गयी चर्चा ₹1 लाख तक की जमाराशि के लिए बचत जमा ब्याज दर से संबंधित है।

सारणी 4: घरेलू बैंक जिन्होंने बचत जमा दरें बदलीं (सितं. 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार)

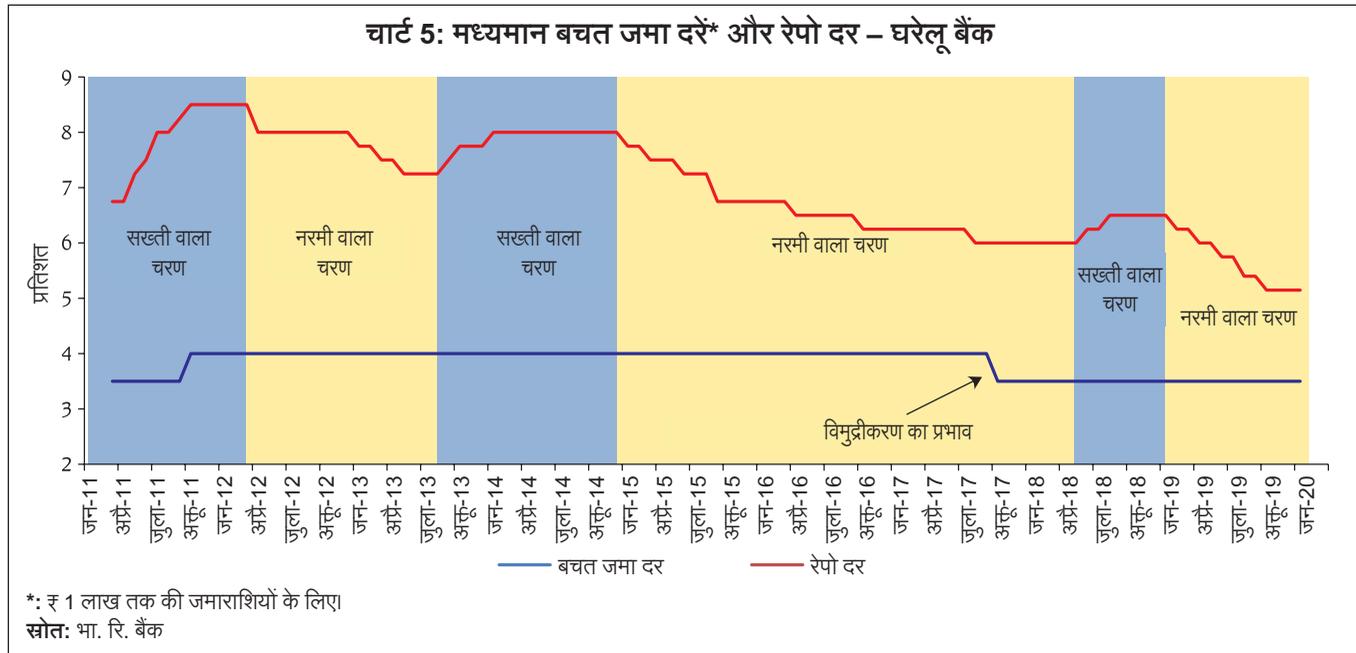
(प्रतिशत प्रति वर्ष)

बैंक	बचत खाते पर ब्याज दर		
	₹ 1 लाख तक के शेष पर	₹ 1 लाख से अधिक के शेष पर	
		न्यूनतम	अधिकतम
1. इंडसइण्ड बैंक	5.50	6.00	6.00
2. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमि.	4.00	4.00	4.50
3. कर्नाटक बैंक	4.00	4.00	4.50
4. कोटक महिंद्रा बैंक	5.50	6.00	6.00
5. आरबीएल बैंक	5.50	5.50	8.00
6. तमिलनाडु मर्कन्टाइल बैंक	4.00	4.00	5.00
7. यस बैंक	6.00	7.00	8.00
रेंज	4.00-6.00	4.00-7.00	4.50-8.00

स्रोत : भा . रि. बैंक

की। निजी क्षेत्र के बैंकों ने ₹1 लाख से कम की बचत जमा पर 150-200 बीपीएस और ₹1 लाख से ऊपर की शेष राशि के लिए 50-400 बीपीएस तक की बढ़ोतरी की (सारणी4)। बचत बैंक जमा में इन बैंकों की बाजार हिस्सेदारी 0.57 प्रतिशत बढ़कर सितंबर 2013 तक 3.5 प्रतिशत हो गई। हालांकि, 25 अक्टूबर 2011 से 30 जुलाई 2017 के बीच एक भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपनी बचत जमा दर में बदलाव नहीं किया।

नवंबर 2016 में हुए विमुद्रीकरण के बाद, भारी मात्रा में अधिशेष तरलता बैंकिंग प्रणाली में आयी जिससे समग्र जमा में बचत राशियों की हिस्सेदारी अक्टूबर 2016 के 26.0 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2018 तक 31.7 प्रतिशत हो गयी। इससे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र बैंक बचत जमा पर ब्याज दरें घटाने को प्रेरित हुए जिसका नेतृत्व भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी बचत जमा दर (एक लाख तक की जमाराशियों पर) घटाकर 3.5 प्रतिशत करने की घोषणा 31 जुलाई 2017 को की (चार्ट 5)। हालांकि, बचत जमा ब्याज दर में यह कमी मौद्रिक नीति से संबंधित नहीं थी बल्कि यह पूरी तरह विमुद्रीकरण के प्रभाव के कारण थी। कुल जमा में बचत जमाराशियों की हिस्सेदारी में जो वृद्धि हुई थी वह अधिकांशतः आगे भी जारी रही है क्योंकि कुल जमा में बचत जमाराशियों की हिस्सेदारी स्थिर बनी रही है, सिवाय जनवरी 2020 माह के जब यह मामूली रूप से घटकर 31.4 प्रतिशत रह गयी है।



यह दिलचस्प है कि विनियमन में ढील दिए जाने के बाद की पूरी अवधि में, विमुद्रीकरण पश्चात किए गए एकाध परिवर्तनों को छोड़ दें तो, बचत जमा दर औसतन स्थिर बनी रही है।⁶ अक्टूबर 2011 में बचत खातों पर ब्याज दर को विनियमन से मुक्त किए जाने के बाद से इसका स्थिर बने रहना एमसीएलआर में और उधार दरों में संचरण के सम्मुख बड़ी बाधा बना हुआ है क्योंकि यह मौद्रिक नरमी के चक्र में निधि-लागत के औसत (और सीमांत भी) को उच्च बनाए रखता है और सख्ती के चक्र में इसे कम बनाए रखता है। यदि कोई बैंक संचरण पूरी तरह करता है जैसे कि नीतिगत रेपो दर में 25 बीपीएस की कटौती का संचरण उसकी सावधि जमा दरों में कर देता है, परंतु अपनी बचत जमा ब्याज दर में बदलाव नहीं करता, तो इसके एमसीएलआर में कटौती केवल 14 बीपीएस की होगी। यह उस धारणा पर आधारित है कि बचत जमा कुल उधार (जमा और अन्य उधार) का 30 प्रतिशत होता है, जो प्रकारांतर से निधियों (उधार और इक्विटी) का 92 प्रतिशत होते हैं। देयताओं की संघटन के मद्देनजर वास्तविक प्रभाव थोड़ा भिन्न हो सकता है। इसलिए, यदि बैंक नीतिगत दर के अनुरूप बचत जमा पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं करते, तो उधार दरों में संचरण हमेशा अधूरा रहेगा।

⁶ 2019-20 के दौरान अब तक (जनवरी 2020 के अंत तक), 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और तीन निजी क्षेत्र के बैंकों ने अपनी बचत जमा दर (₹1 लाख तक) को 25 बीपीएस से घटाकर 3.25 प्रतिशत कर दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ₹1 लाख तक की जमा राशियों की औसत बचत जमा दर घटकर 3.25 प्रतिशत रह गई, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में यह 3.50 प्रतिशत पर ही अपरिवर्तित रही।

IV.3 आधार दर ऋणों की परंपरा

जब 1 अप्रैल 2016 को नये ऋणों के लिए एमसीएलआर प्रणाली लागू की गयी तो सोचा यह गया था कि इससे आधार दर प्रणाली में संचरण के समक्ष मौजूद जड़ता दूर होगी। तथापि, किसी सावधि विधि-खंड की अनुपस्थिति के कारण फ्लोटिंग दर रुपया ऋणों का काफी बड़ा हिस्सा एमसीएलआर प्रणाली लागू होने के तीन वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी आधार-दर से जुड़ा रहा (तालिका 5)।⁷ हालांकि उधारकर्ताओं को यह इजाजत दी गयी है कि वे आधार दर से जुड़े अपने ऋणों को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक शर्तों पर एमसीएलआर प्रणाली में बदल सकते हैं, फिर भी एमसीएलआर प्रणाली में बलने की रफ्तार धीमी रही है, क्योंकि (i) बैंक एमसीएलआर ऋणों में बदलने के विकल्प का व्यापक प्रचार नहीं करते; (ii) बैंक इस बदलाव की सुविधा के लिए शुल्क ले सकते हैं; और (iii) इस बदलाव के तत्काल बाद ब्याज दर में कोई राहत नहीं मिलती क्योंकि मौजूदा ग्राहकों को नए ग्राहकों की तुलना में अधिक स्प्रेड का भुगतान करना होता है, बावजूद इस बात के कि ऋण की कीमत निर्धारण से जुड़े अन्य सभी कारक (जोखिम स्वरूप, परिपक्वता और ऋण का प्रकार) एक ही हों। इन सभी कारणों से, ग्राहक या तो इस विकल्प के बारे में जानते ही नहीं, या वे अपने ऋणों को एमसीएलआर प्रणाली में बदलने के लिए हतोत्साहित कर दिए जाते हैं (भा. रि. बैंक, 2017)।

⁷ जैसा कि हमने टेबल 5 में देखा, परिवर्तनशील दर ऋण बैंकों के ऋण संविभाग का 76 फीसदी हिस्सा होते हैं।

सारणी 5: एससीबी का अस्थायी दर वाला रुपया ऋण

(कुल में प्रतिशत हिस्सेदारी)

बैंक समूह	बीपीएलआर				आधार दर				एमसीएलआर				बाह्य बेंचमार्क			
	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	दिसं-19	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	दिसं-19	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	दिसं-19	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	दिसं-19
सार्वजनिक क्षेत्र (14)	2.3	1.5	1.0	0.9	50.2	26.5	16.8	13.6	47.1	71.4	81.8	83.1	0.4	0.5	0.3	2.4
निजी क्षेत्र (13)	1.4	0.6	0.4	0.3	48.5	19.2	10.6	7.6	49.4	76.7	85.0	81.2	0.7	3.4	4.1	10.9
विदेशी (23)	1.1	0.7	0.4	0.3	24.1	12.5	5.8	4.4	61.2	59.1	61.6	51.8	13.6	27.8	32.2	43.6
एससीबी (50)	2.0	1.3	0.8	0.7	49.4	24.4	14.9	11.8	48.0	72.7	82.4	82.1	0.6	1.7	1.8	5.4

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं।

स्रोत: बैंकों से एकत्रित जानकारी

अप्रैल 2016 से एमसीएलआर और बेस रेट सिस्टम के समानांतर संचालन ने बेस रेट से जुड़े बकाया ऋणों के संबंध में ट्रांसमिशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है (बॉक्स 1 भी देखें)। इसका कारण यह है कि माध्य एमसीएलआर के विपरीत, मौद्रिक नीति के शिथिल और सख्त चरणों के दौरान औसत आधार दर अपेक्षाकृत कठोर बनी हुई है (आरबीआई, 2017)। वर्ष 2017-18 के दौरान मौद्रिक नीति के शिथिल चरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में एमसीएलआर से जुड़े बकाया रूप के लोन पर माध्य डबल्यूएलआर 47 बीपीएस और निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में 36 बीपीएस की गिरावट आई। हालांकि, इसी अवधि के दौरान, बेस रेट से जुड़े ऋणों पर माध्य डबल्यूएलआर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों दोनों के लिए विरोधाभासी रूप से बढ़ा। वर्ष 2018-19 के सख्त चरण के दौरान, जहां अपेक्षित रूप से एमसीएलआर से जुड़े ऋणों पर माध्य डबल्यूएलआर में वृद्धि हुई थी, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए बेस रेट से जुड़े माध्य डबल्यूएलआर में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आई थी (सारणी 6)।

इस प्रकार, ऐसे ऋणों पर ब्याज दरों में परिवर्तन की धीमी गति के साथ संयुक्त आधार दर पर ऋण का एक बड़ा अनुपात बकाया रुपये ऋणों पर ब्याज दरों में संचरण बिगड़ा है।

IV.4 एमसीएलआर सिस्टम के तहत ब्याज दर रीसेट की आवधिकता

एक अन्य कारक जो बकाया रुपये के ऋणों को प्रसारित करता है, वह है फ्लोटिंग दर ऋण पर ब्याज दर रीसेट की लंबी अवधि। रिज़र्व बैंक द्वारा एकत्र की गई जानकारी से पता चलता है कि फ्लोटिंग दर एमसीएलआर ऋण का 75.8 प्रतिशत से अधिक 1 वर्ष और उससे अधिक के एमसीएलआर से संबद्ध है (सारणी 7)। एमसीएलआर से जुड़े फ्लोटिंग रेट लोन पोर्टफोलियो का केवल 15.8 प्रतिशत 3 महीने तक के लिए है। 1-वर्ष के एमसीएलआर से जुड़े ऋण को सालाना रीसेट किया जाता है।

आधार दर/बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) ऋणों, अर्थात् एमसीएलआर-आधारित दरों (जैसा कि पहले बताया गया था) पर उच्च ब्याज दरों के साथ संयुक्त लंबी ब्याज दर रीसेट

सारणी 6: आधार दर और एमसीएलआर से जुड़े बकाया रूप ऋण पर माध्य डबल्यूएलआर

बैंक समूह	एमसीएलआर से जुड़े ओ/एस ऋणों पर डबल्यूएलआर (प्रतिशत)				आधार दर से जुड़े ओ/एस ऋणों पर डबल्यूएलआर (प्रतिशत)			
	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	दिसं-19	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	दिसं-19
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(2)	(3)	(4)	(5)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (14)	10.05	9.58	9.78	9.65	11.33	11.41	11.42	11.08
निजी क्षेत्र के बैंक (13)	10.36	10.00	10.28	10.17	11.13	11.54	11.42	11.65

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं।

स्रोत: बैंकों से एकत्रित जानकारी

सारणी 7: एमसीएलआर से जुड़े अस्थायी दर वाले ऋणों की हिस्सेदारी- परिपक्वता काल-वार (मई 2019)

बैंक समूह	(प्रतिशत)					
	एक-दिवसीय	1-माह	3-माह	6-माह	1-वर्ष	1 वर्ष से अधिक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (11)	2.0	6.2	4.5	3.2	83.6	0.5
निजी क्षेत्र के बैंक (14)	0.1	1.8	15.2	12.8	65.9	4.1
विदेशी बैंक (28)	14.0	13.3	26.7	16.3	14.3	15.4
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (53)	1.3	4.1	10.4	8.4	73.1	2.7

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं।

स्रोत: बैंकों से एकत्रित जानकारी

बॉक्स I: नए रुपए ऋण और बकाया रुपए ऋण पर संचरण – असंबंधन समझाया गया

मौजूदा शिथिलता के दौर में, हाल के महीनों में नए रुपए के ऋणों पर डबल्यूएलआर में सुधार हुआ है। हालाँकि, बकाया रुपए ऋणों में संचरण नगण्य रहा है क्योंकि नए रुपए ऋणों के मामले में 61 बीपीएस की गिरावट के मुकाबले बकाया रुपए ऋणों पर डबल्यूएलआर केवल 12 बीपीएस (फरवरी 2019 - जनवरी 2020) तक कम हुआ है। इसे दो कारकों द्वारा समझाया जा सकता है: (i) मौजूदा ऋणों की लंबी रीसेट आवधिकता; और (ii) आधार दर/बीपीएलआर पर वसीयत ऋणा जहां इन दोनों कारकों के बारे में मुख्य पाठ में बताया गया है, वहीं बकाया रुपए ऋण पर उनके प्रभाव को नीचे चित्रित किया गया है।

रिजर्व बैंक ने फरवरी 2019 से कटौती करने से पहले जून - अगस्त 2018 के दौरान नीतिगत दर में 50 बीपीएस की वृद्धि की थी। उदाहरण के लिए, नीतिगत दर में वृद्धि की प्रतिक्रिया में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी जमा ब्याज दरों को मई 2018 में 8.45 प्रतिशत से बढ़ाकर जनवरी 2019 में 8.75 कर दिया, जो कि उनके एमसीएलआर में बढ़ी (सारणी 1)। इसके बाद, शिथिलता चक्र की शुरुआत के साथ, बैंकों ने अपनी जमा दरों को धीरे-धीरे कम करना शुरू कर दिया। इसके साथ, मार्च 2019 से एमसीएलआर नीचे की ओर फिसलना शुरू हो गया। इसके बावजूद, फरवरी से जुलाई 2019 के दौरान एमसीएलआर एक साल पहले की समान अवधि से अधिक था। नतीजतन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उधारकर्ताओं ने, या कहिए जिन्होंने तत्कालीन प्रचलित एमसीएलआर पर फरवरी-जुलाई 2018 के दौरान 10-वर्षीय अस्थिर दर पर आवास ऋण (एक वार्षिक

रीसेट आवधिकता के साथ 1-वर्षीय एमसीएलआर के लिए बेंचमार्क) लिया था, देखा कि एक वर्ष बाद अर्थात् फरवरी-जुलाई 2019 के दौरान जब ऋणों पर ब्याज दर रीसेट किए गए तो उधारी की उनकी लागत बढ़ रही थी, यह मान कर कि (एमसीएलआर पर) अपरिवर्तित रहा। इसलिए, जहां दिसंबर 2018 से फरवरी 2019 के दौरान एमसीएलआर में कटौती के बाद नए रुपए ऋणों पर डबल्यूएलआर में गिरावट मार्च 2019 से शुरू हो गई, वहीं बकाया रुपए ऋणों पर डबल्यूएलआर जुलाई 2019 तक बढ़ता रहा, अर्थात् शिथिलता चक्र शुरू होने के छह महीनों के बाद।

जैसा कि मुख्य पाठ में बताया गया है, एमसीएलई सिस्टम (दिसंबर 2019 के अंत तक 11.8 प्रतिशत) लागू होने के बाद बैंकों के बकाया लोन पोर्टफोलियो में एक बड़ा हिस्सा आधार दर ऋणों का है। चूंकि अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक शिथिलता चरण के दौरान आधार दर एमसीएलआर के अनुरूप नहीं बदला, इसलिए मार्च 2018 में आधार दर से जुड़े ऋण पर उधार की लागत, एमसीएलआर से जुड़े ऋण की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के 1.83 प्रतिशत अंक और निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में 1.54 प्रतिशत अधिक था। माध्य आधार दर में भी मौजूदा शिथिलता चक्र में बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि माध्य एमसीएलआर में 60 बीपीएस तक की गिरावट आई है। एमसीएलआर में गिरावट को दर्शाते हुए, जहां नए रुपए के ऋणों पर डबल्यूएलआर में गिरावट आई है, वहीं आधार दर ऋणों का घटक ऊपर बना रहा, जो बकाया रुपए ऋणों पर डबल्यूएलआर में गिरावट को प्रभावित करता है।

सारणी 1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 1-वर्षीय माध्य एमसीएलआर

(प्रतिशत)

	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सितं.	अक्तू.	नवं.	दिसं.
I. 2018	8.35	8.35	8.40	8.45	8.45	8.50	8.55	8.60	8.65	8.65	8.70	8.75
II. 2019	8.75	8.75	8.68	8.65	8.68	8.65	8.60	8.50	8.40	8.35	8.35	8.30
(II) - (I)	0.40	0.40	0.28	0.20	0.23	0.15	0.05	-0.10	-0.25	-0.30	-0.35	-0.45

स्रोत: आरबीआई

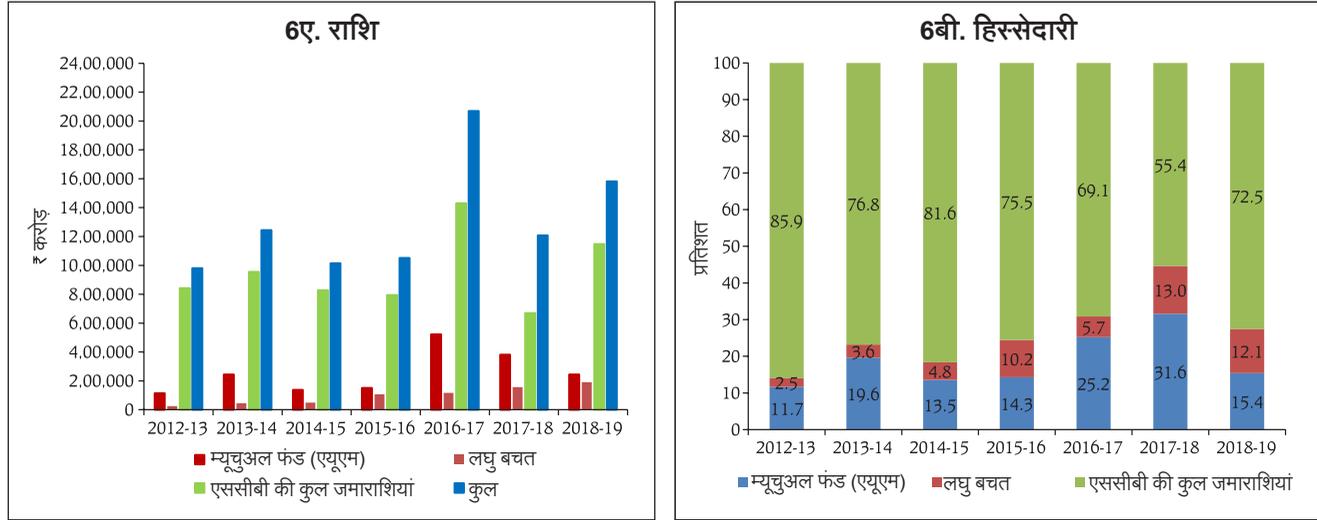
उपबंध ने नए रुपए ऋण और बकाया रुपए ऋणों के ट्रांसमिशन के बीच एक कील सृजित किया है (बॉक्स I)।

IV.5 प्रतियोगी दबाव - म्यूचुअल फंड और लघु बचत योजनाएं

बैंकिंग क्षेत्र मुख्य खंड है जो वित्तीय बचत के बीच मध्यवर्ती की भूमिका अदा करता है (चार्ट 6ए)। हाल के वर्षों में, हालांकि, बैंक जमाराशि की अपेक्षा म्यूचुअल फंड (एमएफ) और लघु बचत का महत्व बढ़ गया है।

पिछले सात वर्षों (2012-13 से 2018-19) के दौरान, म्यूचुअल फंड द्वारा जुटाए गए संसाधन 22.6 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़े हैं - वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि जिस दर पर बढ़ी उससे लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। नतीजतन, वृद्धि संबंधी मामले में, बैंकों, लघु बचत और एमएफ द्वारा जुटाए गए कुल संसाधनों में एमएफ की हिस्सेदारी 2012-13 में 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 31.6 प्रतिशत हो गई, जो 2018-19 में घटकर 15.4 प्रतिशत तक हो गया जबकि लघु

**चार्ट 6: कुल बैंक जमाराशि, म्यूचुअल फंड के प्रबंधन अंतर्गत आस्तियां और लघु बचत –
वृद्धिशील अभिवृद्धि**



स्रोत: (1) हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन सेक्यूरिटीज मार्केट 2018, सेबी
(2) www.indiabudget.gov.in
(3) हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकॉनोमी, आरबीआई
(4) www.amfiindia.com

बचत की हिस्सेदारी भी 2012-13 में 2.5 फीसदी से बढ़कर 2018-19 में 12.1 फीसदी हो गयी (चार्ट 6बी)। लघु बचत योजनाओं, यथा 5-वर्षीय सावधि जमा, लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं के साथ-साथ कर्ज और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर प्रतिलाभ को बैंक सावधि जमाराशि की तुलना में अच्छा कर लाभ मिला।

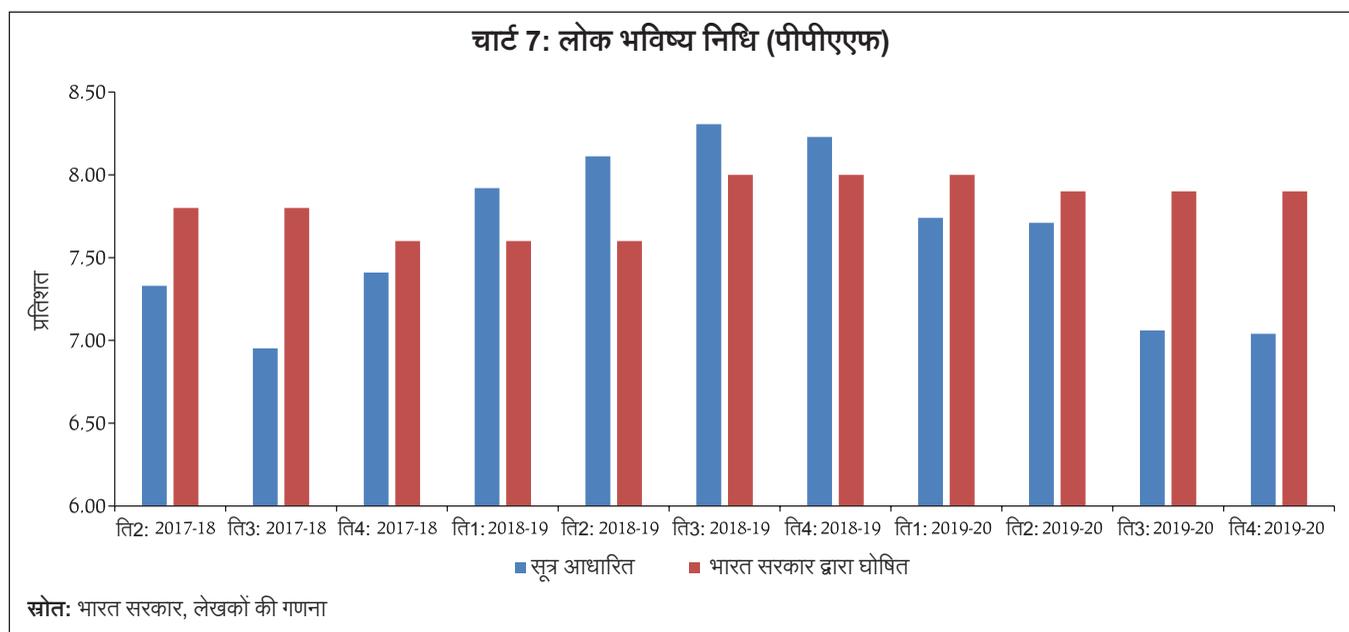
लघु बचत पर ब्याज दर सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है और तुलनीय परिपक्वताओं के जी-सेक पर द्वितीयक बाजार के प्रतिफल से जुड़ी होती है। अप्रैल 2016 से ब्याज दरों को तिमाही आधार पर एक अंतराल के साथ सेट किया जाता है। आमतौर पर, यह देखा गया है कि मौद्रिक नीति के शिथिलता चक्रों - 2017-18 की दूसरी तिमाही से 2017-18 की चौथी तिमाही तक और 2019-20 की पहली तिमाही से 2019-20 की चौथी तिमाही तक, के दौरान लघु बचत दरें सूत्र आधारित दरों की तुलना में अधिक थीं (चार्ट 7)। दूसरी ओर, सख्ती वाले चरण (2018-19 की पहली तिमाही से 2018-19 की तीसरी तिमाही तक) के दौरान, विपर्यय सच था। इसका मतलब यह है कि सांकेतिक नियंत्रित दरों को जी-सेक प्रतिफल के उतार-चढ़ाव के अनुरूप

समायोजित नहीं किया जाता है जो नीतिगत दर में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया दिखाते हैं।

उदाहरण के लिए, विभिन्न योजनाओं पर लघु बचत दरें 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए 18-61 बीपीएस तक ज्यादा थीं। जून-अगस्त और सितंबर-नवंबर 2019 के संबंधित संदर्भ अवधियों के दौरान जी-सेक प्रतिफल में गिरावट के बाद भी सरकार ने लघु बचत दरों को तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के लिए अपरिवर्तित ही रहने दिया। वर्तमान में, लघु बचत योजनाओं पर नियंत्रित ब्याज दरें सूत्र-आधारित दरों की तुलना में 81-160 बीपीएस अधिक हैं (सारणी 8)।

यह तर्क⁸ दिया गया है कि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अभाव में और इस तथ्य के कि कई वरिष्ठ नागरिक जमा आय पर निर्भर करते हैं, जमा दरें एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं गिर सकती हैं। इससे दो मुद्दें निकलते हैं।

⁸ फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 21 दिसंबर, 2019 "बैंक जमा दरों में कटौती के लिए सीमा से परे नहीं जा सकते क्योंकि भारत में सामाजिक सुरक्षा का अभाव है", श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष, एसबीआई द्वारा 21 दिसंबर 2019. को नई दिल्ली में आयोजित 92वें फिक्की वार्षिक सम्मेलन में की गयी टिप्पणी। <https://www.financialexpress.com/industry/banking-finance/banks-cannot-go-beyond-a-threshold-to-cut-deposit-rates-as-india-lacks-social-security-net-sbi-chairman/1800774/>



पहला, जैसे-जैसे निवेश में वृद्धि की रफ्तार कम होती जाती है, निवेश बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में भी कमी आती जाती है। इस प्रकार, ब्याज दरें, बचत और निवेश को संतुलित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती हैं। इसके अलावा, एक शिथिलता चक्र के दौरान, ब्याज दरों को उचित स्तर पर वास्तविक ब्याज दरों को बनाए रखने के लिए निम्न मुद्रास्फीति की दर में कमी करने की आवश्यकता होती है। ब्याज दर के लिए कोई भी कृत्रिम

सीमा बचत और निवेश को संतुलित करने के लिए तंत्र को रोक देगा और सिस्टम में उच्च वास्तविक ब्याज दरों का कारण भी बन सकता है। यह याद किया जा सकता है कि लगभग बीस साल पहले, ब्याज दरें दोहरे अंकों में बहुत अधिक थीं, जो अब एक अंक तक घट गई हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, कई केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत ब्याज दरों को शून्य कर दिया और कुछ यूरोप में उन्हें ऋणात्मक क्षेत्र में भी ले गए, जो अतीत में समझ

सारणी 8: लघु बचत लिखतों पर ब्याज दरें – 2019-20 की चौथी तिमाही

लघु बचत योजनाएं	परिपक्वता (वर्ष)	स्प्रेड (प्रतिशतता अंक)	समान परिपक्वता (सितंबर 2019 से नवंबर 2019) का औसत जी-सेक प्रतिफल (%)	सूत्र आधारित ब्याज दर (%) (जनवरी से मार्च 2020 तक लागू)	चौथी तिमाही में सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर (%)	सरकार द्वारा घोषित दर और सूत्र आधारित दर के बीच अंतर (आधार अंक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (6)-(5)
बचत जमा	-	-	-	-	4.00	-
लोक भविष्य निधि	15	0.25	6.79	7.04	7.90	86
सावधि जमा						
1 वर्षीय	1	0	5.30	5.30	6.90	160
2 वर्षीय	2	0	5.57	5.57	6.90	133
3 वर्षीय	3	0	5.85	5.85	6.90	105
5 वर्षीय	5	0.25	6.40	6.65	7.70	104
डाकघर आवर्ती जमा खाता	5	0	5.85	5.85	7.20	135
डाकघर मासिक आय योजना	5	0.25	6.37	6.62	7.60	98
किसान विकास पत्र	113 माह	0	6.79	6.79	7.60	81
एनएससी VIII निर्गम	5	0.25	6.56	6.81	7.90	109
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	5	1.00	6.40	7.40	8.60	119
सुकन्या समृद्धि खाता योजना	21	0.75	6.79	7.54	8.40	86

स्रोत: भारत सरकार, ब्लूमबर्ग, लेखकों की गणना

से बाहर था। नीतिगत दर के अनुरूप, यूरोप में जमा ब्याज दर घटकर शून्य स्तर के करीब पहुंच गई। इससे पता चलता है कि ब्याज दरों के लिए कोई सीमा नहीं हो सकती है, जो बचत और निवेश का कार्य है।

दूसरा, पेंशनभोगियों/वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे समाज में जिसमें एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का अभाव है। इस संदर्भ में, यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि ब्याज दरों का चक्र होता है। केंद्रीय बैंक तब ब्याज दरों को बढ़ाते हैं जब अर्थव्यवस्था अति-सक्रिय हो रही होती है, यानी जब कुल मांग संभावित आउटपुट (घनात्मक आउटपुट अंतराल) से ऊपर और इसके विपरीत होती है। अंतर्निहित औचित्य अपने संभावित स्तर के प्रति समग्र मांग को पूरा करना है। कुल मिलाकर, हालांकि, जब अर्थव्यवस्था चक्रों से गुजरती है, तो लाभ/हानि मोटे तौर पर उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के लिए समान होती है।

IV.6 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

अपने ऋण पोर्टफोलियो में कम चूक जोखिम वाला एक स्वस्थ बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले ब्याज दर में बदलाव को अपने जमाराशि और ऋण के लिए पास करने में सक्षम होगा। दूसरी ओर, गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) - संभावित या प्राप्त -के उच्च स्तर का सामना करने वाले किसी बैंक के अपने प्रदर्शन वाले ऋणों पर क्रेडिट जोखिम प्रीमियर लोड करके प्रावधानों का निर्माण करने की संभावना है, जिससे उधार दरों को आगे बढ़ाया जा सकता है (जॉन, एवं अन्य 2016)। इस प्रक्रिया में, केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती के जवाब में कम धन लागत के बावजूद, बैंक अपनी उधार दरों को कम नहीं कर सकते हैं या केवल आंशिक रूप से कम कर सकते हैं, जिससे मौद्रिक संचरण बाधित हो सकता है।

प्रभावी मौद्रिक संचरण के लिए बैंकिंग प्रणाली की अच्छी सेहत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भारत में जहां वित्तीय प्रणाली में बैंक का प्रभुत्व है। भारतीय संदर्भ में एक अध्ययन (जॉन, एवं अन्य 2016) से पता चला कि आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट घनात्मक रूप से एनआईएम के साथ केवल 2010-11 की पहली तिमाही से 2015-16 की पहली तिमाही (उप अवधि I) की अवधि में जुड़ी थी। दूसरी ओर, आस्ति की गुणवत्ता में

गिरावट एनआईएम की अवधि 2015-16 की दूसरी तिमाही से 2017-18 की पहली तिमाही (उप-अवधि II) में ऋणात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। गौरतलब है कि उप-अवधि II की तुलना में उप-अवधि I में एनपीए/दबावग्रस्त आस्तियां निम्न स्तर पर थी। इससे पता चलता है कि एनपीए के अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर, बैंक अपनी ऋण दरों पर आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट के बोझ से उबरने और एनआईएम की रक्षा करने में सक्षम थे। उप-अवधि II में, हालांकि, जब एनपीए के उच्च स्तर में परिलक्षित होने के साथ-साथ आस्ति की गुणवत्ता में तेज गिरावट आई, तो एनआईएम दबाव में आ गए क्योंकि बैंक ऋण जोखिम की भरपाई के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने कीमत-लागत अंतर को पर्याप्त रूप से बढ़ाने में सक्षम नहीं थे। इसके बजाय, बैंक जोखिम विमुख हो गए और अपने ऋण जोखिम को कम कर दिया, जिसने बैंक ऋण देने वाले चैनल के माध्यम से मौद्रिक संचरण को प्रभावित किया। कुल स्तर पर उपरोक्त निष्कर्षों को बैंक-समूह-वार स्तर पर भी मंजूरी दी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जिनके पास बड़े एनपीए/दबावग्रस्त आस्ति थे, के एनआईएम ऋणात्मक रूप से प्रभावित थे। आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए घाटे में ऋण आपूर्ति के माध्यम से प्रभावी मौद्रिक संचरण में बाधा उत्पन्न हुई। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के एनआईएम पर ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि अध्ययन के दौरान इन दोनों समूहों के पास एनपीए/दबावग्रस्त आस्ति का स्तर अपेक्षाकृत कम था।

V. उधार दरों की बाह्य बेंचमार्किंग

एक आंतरिक अध्ययन समूह (अध्यक्ष: जनक राज) की सिफारिशों के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सभी नए अस्थायी दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋणों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए जाने वाले अस्थायी दर ऋणों को नीतिगत रेपो दर या 3 महीने की टी-बिल दर या 6 महीने की टी-बिल दर या 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित किसी अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर से जोड़ने के लिए अधिदेश दिया। बैंकों के पास ऋण की उत्पत्ति के समय नए उधारकर्ताओं के लिए बाहरी बेंचमार्क के कीमत-लागत अंतर को ठीक करने की पूरी स्वतंत्रता

सारणी 9: वाणिज्यिक बैंकों के बाह्य बेंचमार्क - जनवरी 2020

बैंक समूह	नीतिगत रेपो दर	सीडी	ओआईएस	एमआईबी ओआर	3-महीना वाला टी-बिल	क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क (रेपो से इतर)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (18)	17	-	-	-	-	1
निजी क्षेत्र के बैंक (22)	17	1	-	-	-	4
विदेशी बैंक (16) @	4	-	1	4	2	-
वाणिज्यिक बैंक (56) @	38	1	1	4	2	5

* - अन्य में एमआईबीओआर, ओआईएस, 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति, सीडी दरें शामिल हैं।

@ 5 बैंकों के पास खुदरा ऋण और एमएसई ऋण सेगमेंट के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है।
नोट: कोष्ठक में आंकड़े बैंकों की संख्या को संदर्भित करते हैं।

स्रोत: आरबीआई द्वारा बैंकों से एकत्रित की गई जानकारी।

है। हालांकि, एक बार जब कीमत-लागत अंतर को दुरुस्त कर लिया जाता है तब बैंकों को केवल उधारकर्ता के ऋण मूल्यांकन में पर्याप्त परिवर्तन की शर्त के तहत कीमत-लागत अंतर को बदलने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि ऋण अनुबंध में सहमति हुई थी जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट जोखिम प्रीमियम में बदलाव हुआ था। इसके अलावा, कीमत-लागत अंतर के अन्य घटकों को तीन वर्षों में एक बार बदला जा सकता है।

1 अक्टूबर, 2019 को इसकी शुरुआत के बाद, बैंकों से एकत्रित जानकारी से पता चलता है कि अधिकांश बैंकों, यानी 56 बैंकों में से 38 ने रिज़र्व बैंक की नीतिगत रेपो दर को खुदरा और एमएसई क्षेत्रों के लिए अस्थायी दर वाले ऋण के लिए बाह्य बेंचमार्क के रूप में अपनाया है; इनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में 34 बैंक शामिल हैं (सारणी 9)। तेरह बैंकों ने अपने ऋणों को एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कई अन्य दरों जैसे एमआईबीओआर, ओआईएस, 3-महीने की टी-बिल दर, सीडी दरों और 10 वर्षीय जी-सेक के प्रतिफल से जोड़ा है। भारतीय स्टेट बैंक जैसे कुछ बैंकों ने स्वैच्छिक रूप से मध्यम स्तर के उद्यमों को दिए गए अपने अस्थायी दर वाले ऋण को से नीतिगत दर⁹ से जोड़ा है।

उन क्षेत्रों के बीच तुलना करने से, जहां बैंकों ने अपने अस्थायी दर वाले ऋणों को रेपो दर से जोड़ा है, यह पता चलता

⁹ 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी, सभी बैंकों को अपनी उधार दरों को मध्यम उद्यमों के लिए बाह्य बेंचमार्क से जोड़ना अपेक्षित होगा।

सारणी 10: बाह्य बेंचमार्क से जुड़े ऋण - नीतिगत रेपो दर पर मेडियन स्प्रेड (जनवरी 2020)

बैंक समूह	व्यक्तिगत ऋण				सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
	आवास	वाहन	शिक्षा	अन्य व्यक्तिगत ऋण	
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (18)	3.3	4.8	4.2	6.7	5.8
निजी क्षेत्र के बैंक (22)	5.2	6.0	6.6	7.0	6.6
घरेलू बैंक (40)	3.9	4.9	4.7	6.8	6.1

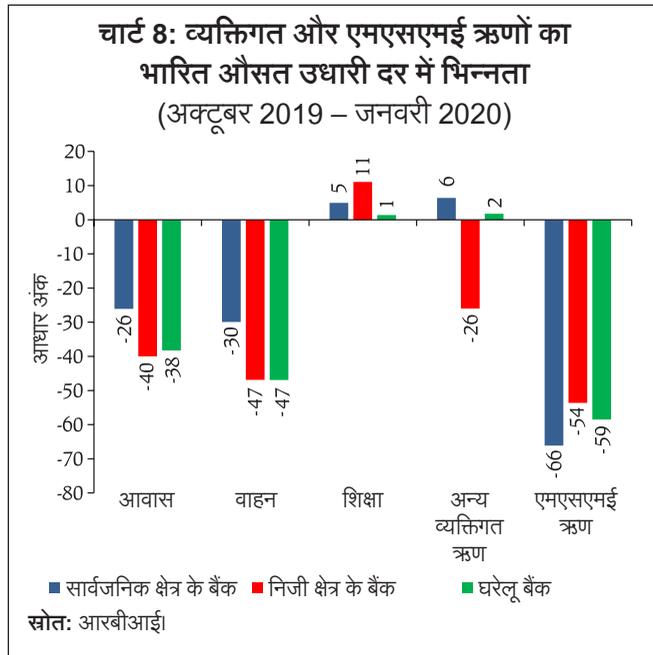
(प्रतिशतता अंक)

स्रोत: आरबीआई द्वारा बैंकों से एकत्रित की गई जानकारी।

है कि अन्य व्यक्तिगत ऋणों, जो मुख्य रूप से असुरक्षित ऋण हैं, के लिए औसत कीमत-लागत अंतर सबसे अधिक था, उसके बाद एमएसई क्षेत्र था (सारणी 10)। माध्य कीमत-लागत अंतर आवास ऋण के मामले में सबसे कम था, जो आमतौर पर संपार्श्विक होते हैं। बैंक-समूहों के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए लगाया जाने वाला माध्य कीमत-लागत अंतर निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में कम था।

उन क्षेत्रों के संबंध में स्वीकृत नए रूप ऋणों के संचरण में सुधार के शुरुआती संकेत हैं, जहां नए अस्थायी दर वाले ऋणों को बाह्य बेंचमार्क से जोड़ा गया है। घरेलू (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र) बैंकों द्वारा आवास क्षेत्रों के लिए मंजूर किए गए नए रूप ऋणों पर लगाए गए डबल्यूएलआर में 38 बीपीएस और अक्टूबर 2019 - जनवरी 2020 के दौरान वाहन ऋण पर 47 बीपीएस तक की कमी आई। जनवरी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋणों के मामले में घरेलू बैंकों के डबल्यूएलआर में भी 59 बीपीएस की गिरावट दर्ज की (चार्ट 8)। हालांकि, जनवरी में शिक्षा क्षेत्र के लिए ऋण के संबंध में डबल्यूएलआर में मामूली वृद्धि हुई है।

बाह्य बेंचमार्क फ्रेमवर्क उधार दरों के लिए संचरण को तेज करेगा (i) क्योंकि बेंचमार्क दर में किसी भी बदलाव से नए उधारकर्ताओं के लिए उधार दरों में बदलाव होगा; (ii) मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए, बैंकों को एमसीएलआर से जुड़े ऋणों के मामले में आमतौर पर एक वर्ष के मुकाबले कम से कम तीन महीने



में एक बार ब्याज दरों को रीसेट करने की आवश्यकता होगी; और (iii) मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए बैंकों को अपने कीमत-लागत अंतर को मनमाने ढंग से समायोजित करने से रोकना। एमसीएलआर प्रणाली के अंतर्गत, उधार दरों में संचरण अप्रत्यक्ष है और जमा ब्याज दरों में बदलाव पर आकस्मिक है। हालांकि, बाह्य बेंचमार्क प्रणाली के तहत, उधारी दरों में संचरण अब जमा ब्याज दरों पर आकस्मिक नहीं होगा। जब कभी मौद्रिक नीति समिति नीतिगत रेपो दर में बदलाव करती है, तो उधार की ब्याज दरें एक तिमाही के भीतर बदल जाएंगी। इसके बाद बैंकों को अपने एनआईएम की सुरक्षा के लिए अपनी जमा दरों को समायोजित करने की आवश्यकता होगी।

VI. समापन टिप्पणियां और कुछ अंतिम विचार

मौद्रिक नीति की सफलता प्रणाली में ब्याज दरों के पूरे स्पेक्ट्रम तक प्रभावी संचरण पर गंभीर रूप से टिकी हुई है। मौद्रिक संचरण की गति और परिमाण विभिन्न वित्तीय बाजार खंडों - मुद्रा, बांड और क्रेडिट बाजार में भिन्न-भिन्न होते हैं।

हाल की अवधि में भारतीय संदर्भ में मौद्रिक संचरण के विश्लेषण से पता चलता है कि मौद्रिक संचरण विभिन्न मनी मार्केट सेगमेंट और निजी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में पूर्ण और यथोचित रूप से तीव्र था। हालांकि, बैंक जमा और उधार दरों में संचरण में देरी हुई है और कई कारणों से आंशिक रूप से।

विलंबित और अपर्याप्त संचरण का मूल कारण बैंकों की जमा ब्याज दरों में सख्ती है। बैंक नियत ब्याज दरों पर दीर्घावधि जमाराशि रखते हैं, जो नीतिगत दरों में परिवर्तन के अनुरूप नहीं बदलते हैं। यहां तक कि जब बैंक नीतिगत दर के अनुरूप जमा ब्याज दरों को कम करते हैं, तो भी इस तरह की कटौती का असर नई जमाराशि पर ही देखने को मिलता है। नतीजतन, बैंक मौजूदा ऋणों पर उधारी दरों को कम करने में असमर्थ हैं, खासकर किसी शिथिलता वाले मौद्रिक नीति चक्र में। इसलिए, बैंक बकाया जमाराशियों के थोक में परिपक्व होने के लिए प्रतीक्षा करते हैं और पिछले ऋणों पर उधार दरों में कमी को संचारित करने से पहले उन्हें कम दरों पर नवीनीकृत करते हैं। इस कारण से, यह लगभग हमेशा होता है कि बकाया ऋणों पर उधारी दरों में शिथिलता चक्र के दौरान बकाया सावधि जमा दरों पर संचरण में कमी आती है। चूंकि बैंक अपने एनआईएम¹⁰ की रक्षा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए जमा ब्याज दरों में सख्ती उनके उधार की ब्याज दरों को संचारित हो जाती है। शिथिलता चक्र के दौरान, बैंकों की सावधि जमा दरों की तुलना में उच्च लघु बचत दरें भी बैंकों को अपनी जमा ब्याज दरों को कम करने से रोकती हैं। हालांकि, बैंक सावधि जमा दरों को सख्ती प्रदान करने वाली नियत ब्याज दरों पर दीर्घावधि जमाराशि और लघु बचत जमा दरों में सख्ती कहानी के केवल एक हिस्से को बताती है। बैंकों ने अपनी बचत जमा दरों में शायद ही बदलाव किया है, जो यह दर्शाता है कि बैंक मौद्रिक नीति चक्र के अनुरूप अपनी लागत को बदलने के लिए ब्याज दरों को एक लिखत के रूप में उपयोग नहीं करना पसंद करते हैं। यह अजीब है कि समान बचत जमा ब्याज दर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अधिकांश निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सख्ती और शिथिलता चरणों के दौरान बनाए रखा गया था। माध्य बचत जमा दर अक्टूबर 2011-सितंबर 2017 के दौरान 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही, जो सख्ती चक्र के दौरान 8.5 प्रतिशत की अधिकतम नीति दर और शिथिलता चक्र के दौरान 6.0 प्रतिशत निम्न नीतिगत दर के अनुरूप नहीं हो सकती है। वर्ष 2017 के अंत तक माध्य बचत जमा ब्याज दर घटकर 3.5 प्रतिशत रह गई और इसके बाद अपरिवर्तित रही। इस अवधि के दौरान,

¹⁰ बैंक जो वित्तीय मध्यस्थता में अपनी दक्षता में सुधार कर सकते हैं, वे लाभप्रदता को कम किए बिना भी कम एनआईएम चार्ज कर सकते हैं।

अधिकतम नीतिगत दर 6.5 प्रतिशत और न्यूनतम नीतिगत दर 5.15 प्रतिशत थी।

यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि यदि जमा ब्याज दरें नीतिगत दर के अनुरूप समायोजित नहीं होती हैं तो यदि ब्याज दरें नीतिगत दरों के अनुरूप बदलती हैं तो उसकी तुलना में रिकवरी धीमी होने की संभावना है और जमा दरों के लंबे समय तक सामान्य/तटस्थ स्तरों की तुलना में निम्न रहने की संभावना है।

बैंकों की उधारी ब्याज दरों के संचरण में आदर्श रूप से जमा ब्याज दरों में बदलाव का पालन करना चाहिए, बशर्ते जमा ब्याज दरें नीतिगत दरों में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया दें। ऐसी स्थिति में जहां जमा ब्याज दरें अवरुद्ध होती हैं और बड़े पैमाने पर ब्याज दर के जोखिम को कम करने की सुविधा के लिए ब्याज दर अदला-बदली करने वाला बाजार पूरी तरह विकसित नहीं है, वहां जब तक कि बैंक अपने एनआईएम पर आघात सहने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक उधार दरों में संचरण प्रभावित होना लाजिमी है। यह मानते हुए कि बैंक हमेशा अपने एनआईएम की रक्षा करेंगे, उधारी ब्याज दरों में प्रभावी संचरण के लिए जमा ब्याज दरों में लचीलापन अपेक्षित होगा। एमसीएलआर प्रणाली के तहत, नीतिगत दर से उधार दरों तक संचरण जमा दरों के माध्यम से चलता है। हालांकि, जमा ब्याज दरों में सख्ती उधार दरों के लिए प्रभावी मौद्रिक संचरण को बाधित करती है। हालांकि, यह बाह्य बेंचमार्क प्रणाली के तहत बदल जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन अब बैंकों द्वारा जमा ब्याज दरों में बदलाव पर आकस्मिक नहीं होगा। किसी बेंचमार्क दर (आमतौर पर, नीतिगत दर) में परिवर्तन के संबंध में उधार दरों में संचरण प्रत्यक्ष और लगभग एकैकी होगा। चूंकि बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने एनआईएम की रक्षा करेंगे, इसलिए तब जाकर वे अपनी जमा ब्याज दरों में अपेक्षित समायोजन करेंगे। यहां तक कि बाह्य बेंचमार्क से जुड़े बकाया

अस्थायी दर वाले ऋण के लिए, बैंकों को एक तिमाही के बाद मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए बेंचमार्क दर में परिवर्तन को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि रीसेट अवधि को भी कम करके वार्षिक से तिमाही कर दिया गया है। बाह्य बेंचमार्क सिस्टम पारदर्शी है, जिसे उधारकर्ताओं द्वारा आसानी से निगरानी किया जा सकता है। इससे त्वरित और लगभग एकैकी मौद्रिक संचरण सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

संदर्भ

Acharya, V. V. (2017), "Monetary Transmission in India: Why is it important and why hasn't it worked well?", Inaugural Speech delivered at the Aveek Guha Memorial Lecture organised by Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) at Homi Bhabha Auditorium, Mumbai, November 16.

(Retrieved from https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1049)

John, J., Mitra, A.K., Raj, J. and Rath, D.P. (2016), "Asset Quality and Monetary Transmission", *Reserve Bank of India Occasional Papers*, Vol 37 (1&2), 35-62.

Reserve Bank of India, "Annual Report", various issues.
....., "Monetary Policy Report", various issues.

..... (2014), "Report of the Expert Committee to Revise and Strengthen the Monetary Policy Framework" (Chairman: Urjit R. Patel). <https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=743>.

..... (2017), "Report of the Internal Study Group to Review the Working of the Marginal Cost of Funds Based Lending Rate System". <https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=878>.

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग : चुनौतियां और संभावनाएं*

भारत विश्व में कई कृषि / खाद्य पदार्थों का एक प्रमुख उत्पादक है, लेकिन इसका केवल 10 प्रतिशत से भी कम हिस्सा प्रसंस्कृत होता है। भारत में आने वाले वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग बढ़नी तय है जिससे अधिक मूल्य संवर्धन, निम्नतर हानि और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कॉर्पोरेट डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि खाद्य प्रसंस्करण फर्मों को लाभ हुआ है, लेकिन मूल्य संवर्धन में काफी वृद्धि करने की आवश्यकता है।

परिचय

भारत ने समय के साथ-साथ अपने लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में काफी प्रगति की है और वह कृषि के क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है। तदनुसार, नीति का ध्यान आत्मनिर्भरता हासिल करने से उठकर खेती करने वाली जनसंख्या की आमदनी बढ़ाने और उसमें स्थिरता लाने पर केंद्रित होने लगा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कृषि उत्पादन के मूल्य संवर्धन, रोजगार के वैकल्पिक अवसर पैदा करने, निर्यात को बेहतर करने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की क्षमता है। भारत, दुनिया में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 11.2 प्रतिशत के साथ, दूध, दालों और जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर है, फलों और सब्जियों में दूसरे और अनाज में तीसरे स्थान पर है (भारत सरकार, 2019)। यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा खाद्य और किराना बाजार भी है (लॉ, और अन्य, 2019)।

2017-18 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विनिर्माण जीवीए में 7.9 प्रतिशत और कृषिजन्य मूल्य संवर्धन में 9.5 प्रतिशत हिस्सा था। यह एक प्रमुख रोजगार प्रदाता भी है, जिसका संगठित विनिर्माण रोजगार में 11.4 प्रतिशत योगदान है। समावेशी विकास को बढ़ावा देने में एफपीआई की अपार संभावनाओं को पहचानते

* यह आलेख भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के धान्या वी, अवधेश कुमार शुक्ल और ऋषभ कुमार द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

हुए, इसे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत ऐसे प्रमुख क्षेत्रों में गिना गया है जिस पर जोर दिया जा रहा है। इस आलेख में मध्यम अवधि में इस क्षेत्र में चुनौतियों के होते हुए भी उच्च वृद्धि की संभावनाओं को परखा गया है।

इस विषय पर सुदृढ़ विश्लेषणात्मक अनुसंधान के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म आंकड़ों की सीमित उपलब्धता, विशेष रूप से क्षेत्रीय स्तर पर, बड़ी अड़चने पैदा करती रही हैं। यह लेख कई स्रोतों से उपलब्ध जानकारी को एक स्थान पर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। समग्र विश्लेषण के लिए, राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। क्षेत्रीय विश्लेषण वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) से प्राप्त डेटा पर आधारित है, जिसके माध्यम से 2016-17 में इस क्षेत्र में उत्पन्न संवर्धित मूल्य के 65.7 प्रतिशत का पता लगाया गया। व्यापार संबंधी डेटा के लिए, विश्व एकीकृत व्यापार समाधान (डब्ल्यूआईटीएस) डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण का उपयोग व्यापार संबंधी डेटा के साथ उद्योग स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है। वित्तीय मापदंडों के विश्लेषण के लिए, हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक कंपनी वित्त अध्ययन के डेटा का उपयोग किया है।

इस संदर्भ में, यह आलेख पाँच खंडों में विभाजित है। खंड II खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विषय में एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। खंड III भारत में एफपीआई की वर्तमान स्थिति का विस्तृत वर्णन करता है और प्रासंगिक सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। खंड IV इस क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करने को लेकर सरकार की पहल पर चर्चा करता है। खंड V आलेख का सार प्रस्तुत करता है।

II. विकास और अंतर-देशीय अनुभव

खाद्य प्रसंस्करण को कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने, जो खाने योग्य रूप में होते हैं या एक खाद्य पदार्थ में मूल्य संवर्धन करते हुए उसे दूसरे खाद्य पदार्थ में बदलने के रूप में परिभाषित किया जाता है (भारत सरकार, 2019)। अंतिम उत्पाद के भौतिक गुणों के आधार पर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दो उप-श्रेणियों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण को वर्गीकृत करता है।

(i) विनिर्मित प्रक्रियाएँ, जिससे उत्पाद के मूल भौतिक गुण एक प्रक्रिया से गुजरते हैं [कर्मचारियों, बिजली, मशीन या धन को शामिल करते हुए] और परिवर्तित उत्पाद खाने योग्य है और

इसका वाणिज्यिक मूल्य होता है एवं (ii) अन्य मूल्य वर्धित प्रक्रियाएं हैं जहां उत्पाद किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया से नहीं गुजरता है, लेकिन बढ़ी हुई शेल्फ लाइफ, शेल्ड और खपत के लिए तैयार आदि जैसे महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन प्राप्त करता है। मूल्यवर्धन के प्रकार और सीमा के आधार पर, इसे प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक प्रसंस्करण कच्चे माल के रूपांतरण से संबंधित है जो खपत के लिए फिट है। इसमें सुखाने, श्रेषिंग, सफाई, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग आदि जैसे कदम शामिल हैं। द्वितीयक प्रसंस्करण में ब्रेड, वाइन, सॉसेज इत्यादि जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्माण शामिल है। खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उत्पादन से खाद्य प्रसंस्करण के एक अन्य श्रेणी, अर्थात्, तृतीयक प्रसंस्करण का जन्म हुआ है (भारत सरकार, 2019)।

उपभोक्ता समूह में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का महत्व विश्व स्तर पर समय के साथ बढ़ा है। उच्च आय, शहरीकरण, जनसांख्यिकीय बदलाव, बेहतर परिवहन और गुणवत्ता एवं सुरक्षा को लेकर उपभोक्ता की धारणाओं में बदलाव के साथ, भोजन की खपत के स्वरूप में पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आया है (रेगमी, 2001 और विल्किंसन एवं रोचा, 2008)। इसके अलावा, मास मीडिया / सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देने से भारत, मलेशिया, चीन, फिलीपींस और थाईलैंड (रेगमी और गेहलहर, 2005) में उच्च मांग वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) का विकास हुआ है। वर्ष 2002 में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की वैश्विक खुदरा बिक्री ताजा भोजन की बिक्री की तुलना में तीन गुना से भी अधिक थी (रेगमी और गेहलहर, 2005)। भारत के मामले में, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की कुल प्रति व्यक्ति बिक्री 2012 में 31.3 अमेरिकी डॉलर से लगभग दोगुनी होकर 2018 में 57.7 अमेरिकी डॉलर हो गई (लॉ और अन्य, 2019)। सारणी 1 दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खाद्य उद्योग के विकास को दर्शाता है।

अनुमान बताते हैं कि पश्चिमी देशों में 60-80 प्रतिशत की अपेक्षा चीन में 30 प्रतिशत खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण किया जाता है (लियू, टेलर और झांग, 2007)। फलों और सब्जियों के मामले में, केपीएमजी (2007) ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल उत्पादन के 65.0 प्रतिशत का प्रसंस्कारण किया जाता है, जबकि फिलीपींस में 78.0 प्रतिशत और चीन में 23.0 प्रतिशत।

सारणी 1: वैश्विक खाद्य मांग का विकास

खाद्य उत्पादों की मांग ↑	आहार, कार्यात्मक और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ				उत्तरी अमेरिका, जापान, पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया
	सुविधाजनक खाद्य पदार्थ, नाश्ता और तैयार भोजन			पूर्वी यूरोप	
	डेयरी, मांस, ताजे फल, फलों के रस, पेय पदार्थ		भारत, चीन और लैटिन अमेरिका		
	कार्बोहाइड्रेट स्टेपल	अफ्रीका (सब सहारन)			
	संकेतक	जीवित	व्यापक बाजार	सुविधा भोजन सेवा स्नैकिंग और गुणवत्ता स्वच्छता	उच्च प्रौद्योगिकी

औद्योगिक विकास →

स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), भारत सरकार।

इसी तरह, कृषि उपज का कुल प्रसंस्करण थाईलैंड में लगभग 30.0 प्रतिशत, ब्राजील में 70.0 प्रतिशत, फिलीपींस में 78.0 प्रतिशत और मलेशिया में 80.0 प्रतिशत है। इसी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रसंस्करण का स्तर बहुत कम है, जो इस प्रकार है - फलों और सब्जियों के लिए 2.2 प्रतिशत, दूध के लिए 35.0 प्रतिशत, मांस के लिए 21.0 प्रतिशत और पोल्ट्री उत्पादों के लिए 6.0 प्रतिशत। वर्ष 2010-11 में, प्रसंस्करण चैनल में प्रवेश करने वाले कच्चे भोजन का हिस्सा 6.8 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है (घोष, 2014)।

विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में एफपीआई शुरुआती अवस्था में है (सारणी 2)। विकासशील देशों में भी मूल्य वर्धित विनिर्माण में भारत की एफपीआई की हिस्सेदारी कम है।

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) आंकड़ों के मुताबिक, 2014 में प्रसंस्कृत वस्तुओं के कुल उत्पादन का आधे से अधिक फसलों से प्रसंस्कृत वस्तुओं का हिस्सा था और इसका हिस्सा 1990 में 52.6 प्रतिशत से बढ़कर 2014¹ में 58.4 प्रतिशत हो

¹ एफएओ समुद्री उत्पादों के बारे में जानकारी नहीं देता है और इसलिए दी गई हिस्सेदारी मछली और मछली उत्पादों को छोड़कर है।

सारणी 2: विनिर्माण जीवीए और कुल जीवीए में प्रसंस्कृत खाद्य, पेय एवं तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण की हिस्सेदारी

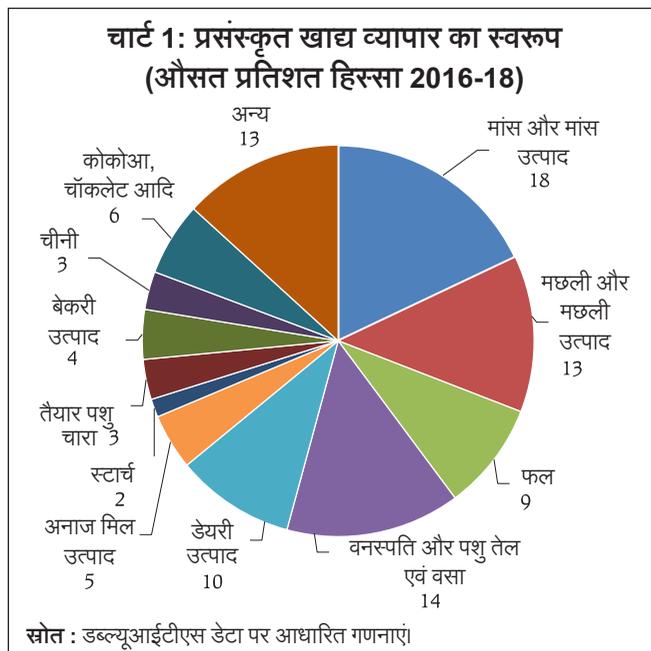
देश	वित्त वर्ष	जीवीए	विनिर्माण
भारत	2017*	1.7	9.7
इंडोनेशिया	2018	7.5	35.5
ऑस्ट्रेलिया	2018	1.5	26.0
न्यूजीलैंड	2013	4.6	34.3
कनाडा	2018	1.8	17.1
यूएसए	2018	1.3	11.4
डेनमार्क	2018	1.5	10.7
फ्रान्स	2018	2.2	16.2
स्विटजरलैंड	2011	2.2	11.4

*: अप्रैल-मार्च 2017-18

स्रोत : सीईआईसी डेटाबेस और लेखकों की गणना।

गया। मांस उत्पाद दूसरे स्थान पर है जिसका कुल प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन में 26.0 प्रतिशत हिस्सा है और इसके बाद दुग्ध उत्पादों का स्थान आता है। जौ और चीनी की बीयर फसल आधारित प्रसंस्कृत वस्तुओं के कुल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा होता है, जबकि प्रसंस्कृत दूध समूह में मलाई रहित दूध प्रमुख वस्तु थी।

2018 में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में फसल आधारित उत्पादों की बड़ी हिस्सेदारी के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने भी इसी तरह का स्वरूप दर्शाया जिसके बाद मांस व मांस उत्पादों, और मछली व मछली उत्पादों का स्थान आता है (चार्ट 1)।

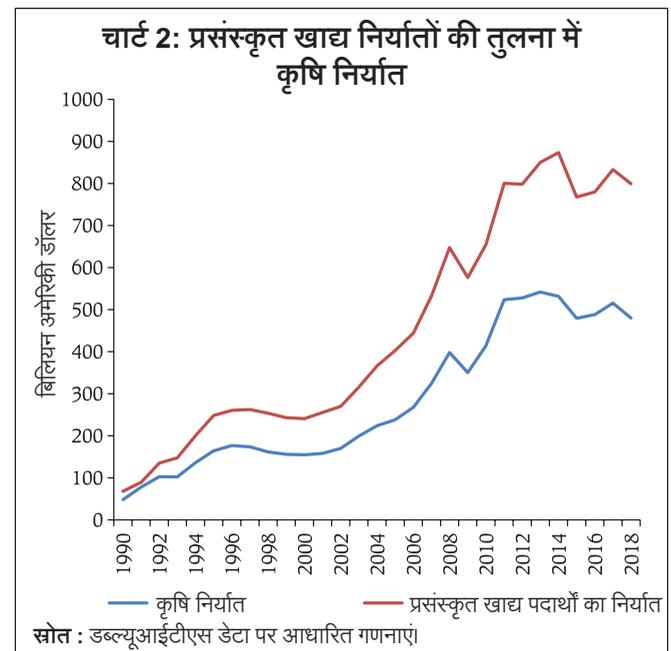


मूल्य के संदर्भ में दुनिया के निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का हिस्सा वर्षों से स्थिर बना हुआ है। 2018 में, यह कुल विश्व प्रसंस्कृत निर्यात का 6.5 प्रतिशत और कुल विश्व निर्यात का 5.7 प्रतिशत था। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात से कृषि निर्यात का पता चलता है, हालांकि उसमें बाद वाले की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर्ज की गई जिसके परिणामस्वरूप उसे उच्च मूल्य प्राप्त हुआ (चार्ट 2)। वर्ष 2018 में, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात कुल कृषि निर्यात की तुलना में 1.6 गुना अधिक था।

उपभोक्ताओं के खाद्य समूह में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते महत्व के साथ, नए नियमों के साथ गुणवत्ता मानक भी एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरे हैं। खाद्य-प्रणाली को निजी-सरकारी मानकों के मिश्रण के माध्यम से विनियमित किया जा रहा है, जिससे रणनीतिपरक प्रतिस्पर्धा पनपती है तो दूसरी ओर प्रवेश को लेकर रोक भी लगायी जाती है (विल्किंसन और रोचा, 2008; और विश्व व्यापार संगठन, 2012)। गुणवत्ता मानकों का कार्यान्वयन विकसित और विकासशील देशों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है।

III. भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शुरुआती अवस्था में है, जिसका भारत के कुल खाद्य पदार्थों में 10 प्रतिशत से भी कम हिस्सा है (भारत सरकार, 2016)। यह उम्मीद की जाती है कि



सारणी 3: प्रमुख बागवानी और अनाज फसलों में क्षति
(उत्पादन के प्रतिशत के रूप में)

	सीआईपीएचईटी रिपोर्ट 2010 के अनुसार	सीआईपीएचईटी रिपोर्ट 2015 के अनुसार
अनाज	3.9 – 6.0	4.65 – 5.99
दलहन	4.3 – 6.1	6.36 – 8.41
तेल के बीज	2.8 – 10.1	3.08 – 9.96
फल और सब्जियां	5.8 – 18.0	4.58 – 15.88
दूध	0.8	0.92
मत्स्य (अंतर्देशीय)	6.9	5.23
मत्स्य (समुद्री)	2.9	10.52
मांस	2.3	2.71
पोल्ट्री	3.7	6.74
बागवानी फसलें		
अमरूद	18.0	15.9
आम	12.7	9.2
सेब	12.3	10.4
अंगूर	8.3	8.6
पपीता	7.4	6.7
केला	6.6	7.8
अनाज फसलें		
गेहूं	6.0	4.9
धान	5.2	5.5
बाजरा	4.8	5.2
मक्का	4.1	4.7

स्रोत : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), भारत सरकार ।

खाद्य प्रसंस्करण में सुधार से कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी। वर्तमान में भोजन की बर्बादी बहुत अधिक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीएचईटी) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख फसलों में बर्बादी, सामान्य रूप से, 2010-2015 के दौरान उच्च स्तर पर रही (सारणी 3)।

एफपीआई का विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में हिस्सेदारी के संदर्भ में क्षेत्रों में प्रमुख स्थान है और अपने श्रम-प्रधान स्वरूप की वजह से इसका समग्र अर्थव्यवस्था पर उच्च गुणक प्रभाव पड़ता है। एएसआई के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई, उद्योग समूहों² में सर्वाधिक रोजगार प्रदाता के रूप में उभरा है। हालांकि, विनिर्माण और कुल जीवीए में इसकी हिस्सेदारी घटी है, जो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी वृद्धि को दर्शाती है (सारणी 4)। दूसरी ओर, कच्चे खाद्य पदार्थों के निर्यात की

² हालांकि, वस्त्र, पहने जाने वाले पोषाकों के साथ मिलकर, 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ संगठित विनिर्माण क्षेत्र में सर्वोच्च नियोजित बन जाता है।

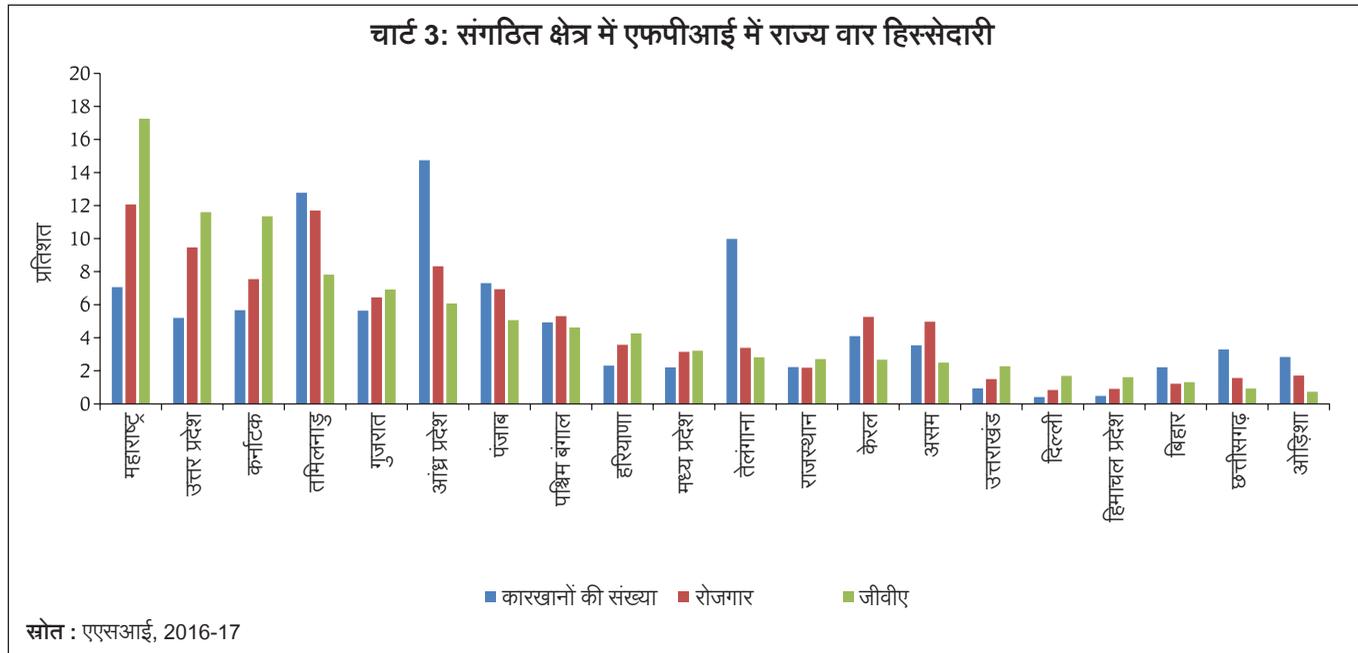
सारणी 4: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थिति
(प्रतिशत)

संकेतक	1990-91	2000-01	2010-11	2016-17	2017-18
कुल मूल्य संवर्धन में हिस्सेदारी	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4
विनिर्माण मूल्य संवर्धन में हिस्सेदारी	9.4	9.4	7.4	7.7	7.9
विनिर्माण रोजगार में हिस्सेदारी	13.2	15.4	12.1	11.4	11.4
कुल विनिर्माण निर्यात में हिस्सेदारी	5.1	5.4	2.9	4.4	4.5
कृषि मूल्य संवर्धन के अनुपात के रूप में	4.1	5.6	7.2	9.2	9.5
कृषि और संबद्ध निर्यात के अनुपात के रूप में	56.0	97.2	70.8	91.4	101.0

स्रोत : राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी पर आधारित लेखकों की गणनाएं।
वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन एंड ऐन्यूअल सर्वे आफ इंडस्ट्रीज डेटा ।

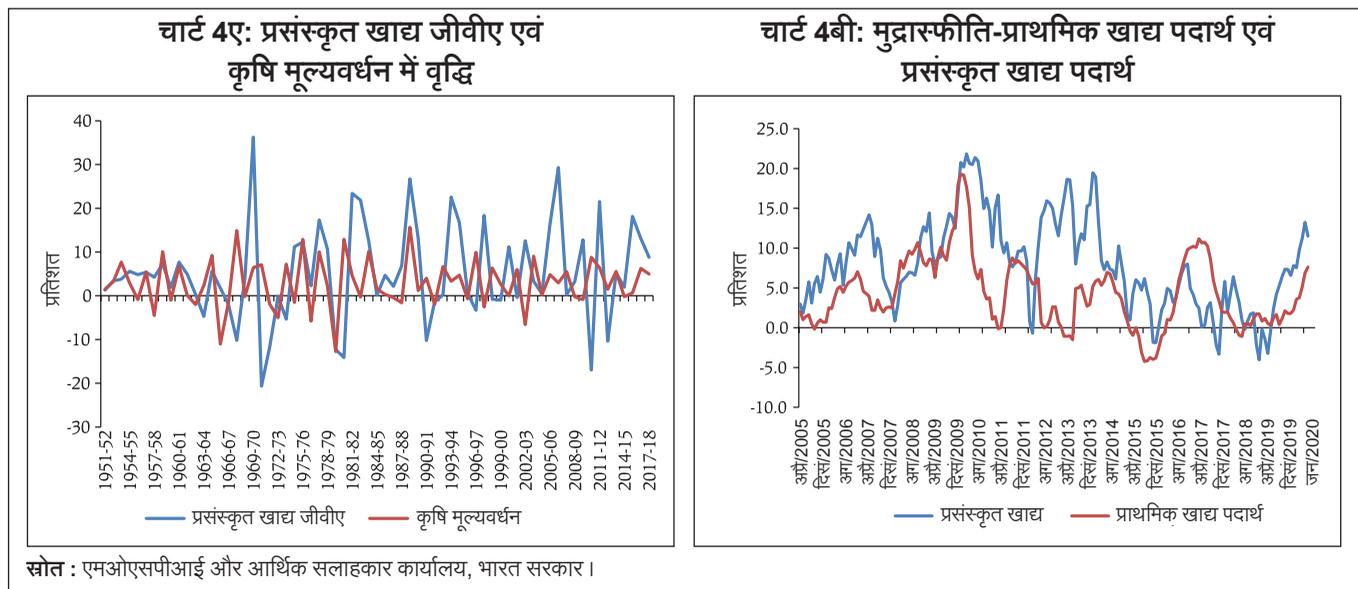
तुलना में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात का अनुपात इस अवधि में काफी बढ़ गया है।

संगठित और असंगठित क्षेत्रों में एफपीआई इकाइयों की तुलना के लिए कोई आम डेटा सेट उपलब्ध नहीं है। हालांकि, एएसआई डेटा के उपयोग से तुलना की जा सकती है, जो संगठित क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और नैशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के अनिगमित गैर-कृषि उद्यम सर्वेक्षण डेटा असंगठित क्षेत्र की जानकारी प्रदान करते हैं। क्रमशः 2016-17 और 2015-16 हेतु इन दो डेटा सेटों की तुलना से संगठित क्षेत्र में एफपीआई उद्यमों का औसत प्रतिशत कम होने का पता चलता है, फिर भी कुल एफपीआई में संगठित क्षेत्र का हिस्सा सकल मूल्य संवर्धन के 80 प्रतिशत से अधिक है। एएसआई के आंकड़ों के अनुसार, 2016-17 में संगठित क्षेत्र में 39,748 खाद्य प्रसंस्करण उद्यम थे, जबकि एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार अनिगमित उद्यमों की संख्या 2015-16 में 24,59,929 थी। संगठित उद्यमों के लगभग आधे राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में थे, जबकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अनिगमित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या सबसे अधिक थी। रोजगार के संदर्भ में भी, असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व है। एएसआई 2017-18 के अनुसार, पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण संस्थाओं में पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 17.7



लाख थी, जो पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में उत्पन्न कुल रोजगार का 11.4 प्रतिशत था। बल्कि, असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने 2015-16 में 51.1 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया (एनएसएसओ के 73वें दौर के अनुसार), जो अपंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का 14.2 प्रतिशत होता है। संगठित क्षेत्र में उत्पन्न मूल्य के संदर्भ में, तीन राज्यों, महाराष्ट्र (17.3 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (11.6 प्रतिशत) और कर्नाटक (11.3 प्रतिशत) ने मिलकर लगभग 40 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 3)।

प्रसंस्कृत खाद्य जीवीए में वार्षिक वृद्धि कृषि जीवीए की तुलना में अधिक अस्थिर रही है (चार्ट 4ए)। थोकमूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति, प्रसंस्कृत खाद्य मुद्रास्फीति और प्राथमिक खाद्य मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव का साथ-साथ होना दर्शाती है, यद्यपि, हाल की अवधि में, बाद वाले की अपेक्षा पहला अधिक बनी हुई है (चार्ट 4बी)। अप्रैल 2005 से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य मुद्रास्फीति की भिन्नता का गुणांक प्राथमिक खाद्य मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक था।



सारणी 5: भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थिति (2000-01 से 2016-17 का औसत)

(प्रतिशत)

मद	उत्पादन में मूल्य संवर्धन	उत्पादन में हिस्सेदारी	रोजगार में हिस्सेदारी	निर्यात में हिस्सेदारी
मैकरोनी, नूडल्स, कूसकूस और इसी तरह के पौष्टिक उत्पादों का विनिर्माण	35.9	0.2	0.3	0.1
तैयार भोजन और व्यंजन का विनिर्माण	30.1	0.4	0.6	-
कोको, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी का विनिर्माण	25.5	1.5	1.8	0.6
फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण और संरक्षण	20.9	1.5	3.3	3.7
बेकरी उत्पादों का विनिर्माण	18.9	2.8	4.6	1.0
अन्य खाद्य उत्पादों का विनिर्माण एन.ई.सी. *	16.6	9.8	28.4	5.1
चीनी का विनिर्माण	16.1	14.1	18.1	6.4
स्टार्च और स्टार्च उत्पादों का विनिर्माण	16.0	1	1.4	0.6
मांस का प्रसंस्करण और संरक्षण	12.7	1.7	1.2	13.1
डेयरी उत्पादों का विनिर्माण	9.9	13.1	7.4	1.6
तैयार पशु चारे का विनिर्माण	9.8	3.9	2.3	0.5
मछली का प्रसंस्करण और संरक्षण	9.1	2.8	2.8	22.8
अनाज मिल उत्पादों का विनिर्माण	7.4	22.8	21.0	26.2
वनस्पति और पशु तेल एवं वसा का विनिर्माण	5.7	24.6	6.7	17.2
कुल	10.7	100	100	100.0

- : उपलब्ध नहीं।

* : अन्यत्र कहीं वर्गीकृत नहीं।

स्रोत : एन्यूअल सर्वे आफ इंडस्ट्रीज डेटा और डब्ल्यूआईटीएस पर आधारित लेखकों की गणनाएं।

एफपीआई क्षेत्र में उत्पादन की तुलना में मूल्य संवर्धन का हिस्सा कम है (2016-17 में 10.2 प्रतिशत)। क्षेत्र के कुल उत्पादन में उच्च मूल्य-संवर्धित पदार्थों जैसे खाने के लिए तैयार पदार्थों की हिस्सेदारी अत्यंत कम है (सारणी 5)। अनाज मिल के उत्पाद हाल के वर्षों में भारत के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में प्रमुख निर्यात वस्तु के रूप में उभरे हैं। निर्यात किए गए विभिन्न खाद्य उत्पादों में प्रसंस्कृत मछली और मांस उत्पादों का प्रति यूनिट मूल्य सबसे अधिक था।

अब तक के विश्लेषण से पता चलता है कि एफपीआई में दूध, मांस और मछली के सिवाय व्यापक संभावनाएं हैं, जबकि अन्य कृषि-खाद्य वस्तुओं में प्रसंस्करण की मात्रा कम अर्थात्, 10 प्रतिशत से कम है। 2017-18 में कुल उपज में प्रसंस्कृत खाद्य का कुल हिस्सा 10 प्रतिशत था। सरकार ने 2025 तक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कुल कृषि उपज का 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।

खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई

2016 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के जरिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, 2017 में, भारत में विनिर्मित और / या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित खुदरा व्यापार के लिए सरकारी मार्ग के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। जहां इस क्षेत्र में एफडीआई का प्रवाह पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, वहीं 2018-19 में इसका हिस्सा अभी भी कम है अर्थात्, 2 प्रतिशत से भी कम (सारणी 6)।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत नेस्ले, कारगिल, मैककेन, मोंडोलेज़, पेप्सी, कोको कोला आदि जैसी खाद्य और पेय कंपनियों एवं साथ ही अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, जैसी खुदरा व्यापार कंपनियों से निवेश आकर्षित करने में कामियाब रहा है (भारत सरकार, 2017)। वर्ष 2018 में, मोंडोलेज़ इंटरनेशनल ने आंध्र प्रदेश में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के बाद रिसर्च के लिए भारत में 15 मिलियन अमेरिकी

सारणी 6: भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में एफडीआई अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

वर्ष	भारत में एफडीआई	खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई	एफडीआई अंतर्वाह में एफपीआई की हिस्सेदारी (%)
2010-11	29,029	189	0.6
2011-12	32,952	170	0.5
2012-13	26,953	401	1.5
2013-14	30,763	3,983	12.9
2014-15	35,283	516	1.5
2015-16	44,907	506	1.1
2016-17	42,215	727	1.7
2017-18	39,431	905	2.3
2018-19	43,302	628	1.5

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस।

डॉलर का निवेश किया। इसी तरह, यूएसए स्थित एग्रो-फूड कंपनी, कारगिल ने विभिन्न आपूर्ति श्रृंखला नोड्स जैसे कर्नाटक में कोल्ड स्टोरेज सुविधा और आंध्र प्रदेश में एक्वा फीड परियोजना में निवेश किया। इसके अलावा, अमेज़न और वॉलमार्ट के भारतीय खाद्य खुदरा क्षेत्र में प्रवेश से इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आने की उम्मीद है।

बाह्य व्यापार

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग काफी हद तक घरेलू उन्मुख है, जिसका निर्यात कुल उत्पादन का केवल 12 प्रतिशत है। फिर भी, यह हाल के वर्षों में धनात्मक व्यापार संतुलन के साथ शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जक है (चार्ट 5)। विश्व स्तर पर, भारत प्रसंस्कृत और संरक्षित मछली और मछली उत्पादों, अनाज मिल उत्पादों के निर्यात में पहले स्थान पर और चीनी के निर्यात में चौथे स्थान पर है। हालांकि, इन उत्पादों में भी, केवल एक चौथाई उत्पाद का निर्यात किया जाता है जो घरेलू अर्थव्यवस्था में खपत के उच्च अनुपात को दर्शाता है।

निर्यात के गंतव्य के संदर्भ में, पारंपरिक रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ भारत के लिए प्रमुख बाजार थे। तथापि, देर ही सही, वियतनाम ने भारत से विनिर्मित खाद्य उत्पादों के प्रमुख आयातकों के रूप में अमेरिका और यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ दिया जो भारत से मांस और मछली उत्पादों के बढ़ते आयात के कारण है। फिर भी, मछली उत्पादों और प्रसंस्कृत फलों और

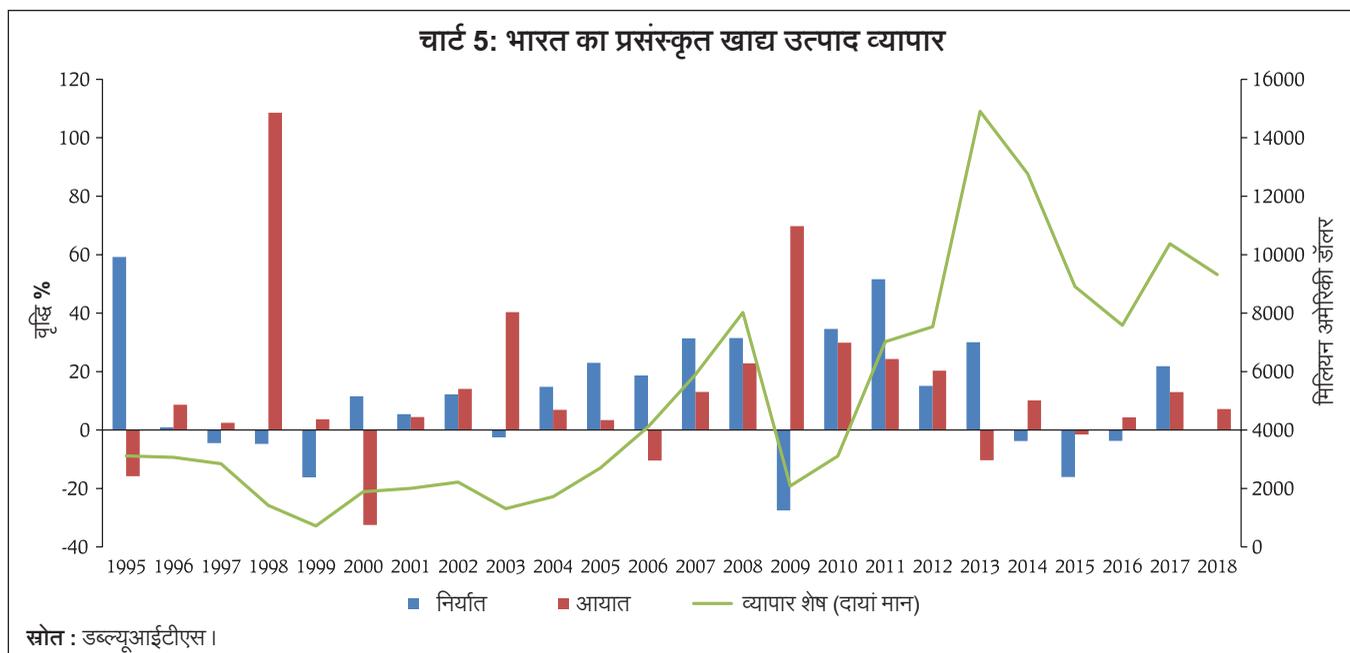
सब्जियों के निर्यात के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ प्रमुख गंतव्य स्थान बने हुए हैं।

उन प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जिनमें भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ है, बालासा (1965) सूचकांक के अनुरूप प्रकट तुलनात्मक लाभ (आरसीए) विश्लेषण की गणना की जाती है।

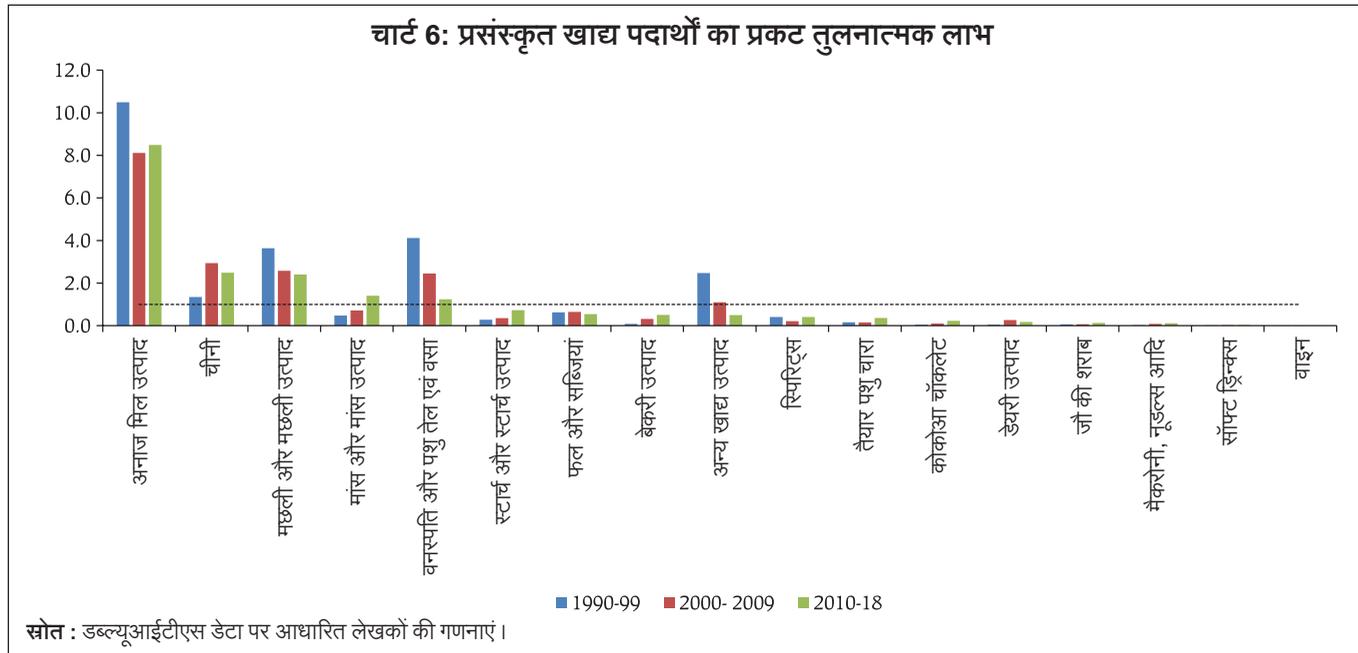
$$RCA_{ij} = \left(\frac{X_{ij}}{X_{it}} \right) / \left(\frac{X_{wj}}{X_{wt}} \right)$$

जहाँ X_{ij} और X_{it} देश i के उत्पाद j के निर्यात और उसके कुल निर्यात के मूल्य हैं, जबकि X_{wj} और X_{wt} क्रमशः विश्व के उत्पाद j के निर्यात और कुल विश्व निर्यात को दर्शाता है। यूनिटी से अधिक मूल्य का अर्थ है कि देश i का उस उत्पाद और उस उत्पाद का देश i में प्रकट तुलनात्मक लाभ है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के कुल 17 उप-समूहों में से, भारत का 5 उत्पादों में प्रकट तुलनात्मक लाभ है, जिसमें अनाज मिल के उत्पादों का उच्चतम अंक है (चार्ट 6)। भारत 2018 में अनाज मिल उत्पादों के निर्यात में पहले स्थान पर था जो विश्व के कुल निर्यात का 18 प्रतिशत था। वनस्पति और पशु तेल और वसा के मामले में, आरसीए में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है, हालांकि अभी भी दशकीय औसत 1.2 पर था। इसके अलावा, मजबूत घरेलू मांग ने भारत को वनस्पति तेलों का शुद्ध आयातक बना दिया है, जिसके लिए 2015 के बाद से आरसीए यूनिटी से कम हो गया है। दूसरी तरफ, मांस और मांस

चार्ट 5: भारत का प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद व्यापार



स्रोत : डब्ल्यूआईटीएस।



उत्पादों के मामले में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है।

मूल्य प्रतिस्पर्धा के अलावा, गुणवत्ता मानक किसी उत्पाद की निर्यात क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। उपभोक्ताओं के गुणवत्ता के प्रति जागरूक होने के साथ, इन उत्पादों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है, लेकिन व्यापार में प्रतिबंध लगाने की परिपाटी में भी वृद्धि हुई है। 1990 के दशक के मध्य से उपभोक्ताओं में उच्च खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की बढ़ती मांग के साथ देशों में सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) उपायों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है (विश्व व्यापार संगठन, 2012)। विश्व व्यापार संगठन के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों के तहत विकसित देशों द्वारा गुणवत्ता मानकों का लगातार उपयोग किया जाता है ताकि विकासशील देशों से किए जाने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सके (आरती, कुमार, नेगी और सिंह, 2012; कुमार, 2016; और गोयल, मुखर्जी और कपूर, 2017)।

जहां एक तरफ कोडेक्स एलेमेंट्रिस मानक जैसे विश्व स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता मानक हैं, वहीं व्यक्तिगत देशों को, डब्ल्यूटीओ के मानदंडों के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक निर्धारित और लागू करने का अधिकार है, बशर्ते वे वैज्ञानिक औचित्य पर आधारित हों और मानव, पशु या वनस्पति की रक्षा के लिए लागू किए गए हों। कई विकसित देशों के स्वास्थ्य मानक

अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत मानकों की अपेक्षा काफी सख्त हैं जिससे कि वे विकासशील देशों से किए जाने वाले आयात से होने वाले संभावित स्वास्थ्य संबंधी खतरों से अपने राष्ट्रों की रक्षा कर सकें (गोयल, मुखर्जी और कपूर, 2017)।

कॉर्पोरेट डेटा विश्लेषण

गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के भीतर अन्य उप क्षेत्रों की अपेक्षा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की ताकत और कमजोरी को समझने के लिए, उनके वित्तीय खातों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इस तरह के विश्लेषण की प्रासंगिकता इस तथ्य से समर्थित है कि एफपीआई क्षेत्र में 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन और संवर्धित मूल्य संगठित क्षेत्र से उत्पन्न होता है। इसके अलावा, स्वामित्व संरचना के संदर्भ में, फर्मों को पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड फर्मों के रूप में विभाजित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण फर्मों के प्रमुख समग्र कार्य-निष्पादन संकेतकों की तुलना सभी गैर-सरकारी और गैर-वित्तीय फर्मों के साथ की जाती है (अनुबंध I, सारणी ए1)।

यह देखा जा सकता है कि एफपीआई के प्रमुख मापदंडों, जैसे, बिक्री, कर पूर्व लाभ (पीबीटी), सकल मूल्य संवर्धन और सकल स्थिर आस्तियों की वार्षिक वृद्धि के आंकड़े अस्थिर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड फर्मों की वृद्धि में पब्लिक लिमिटेड फर्मों की तुलना में अधिक अस्थिरता पाई गई है। यह इंगित करता है कि छोटे फर्मों को अधिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। वर्ष

2013-14 के बाद पब्लिक लिमिटेड फर्मों की सांकेतिक बिक्री वृद्धि में काफी गिरावट आई, जबकि प्राइवेट लिमिटेड फर्मों की स्थिति स्थिर रही। एफपीआई फर्मों की बिक्री वृद्धि के विपरीत, लाभ और जीवीए वृद्धि, हालांकि, स्थिर रही, जो दर्शाता है कि इन फर्मों को संभवतः 2013-14 के बाद वैश्विक पण्य कीमतों के कम होने से लाभ हुआ होगा।

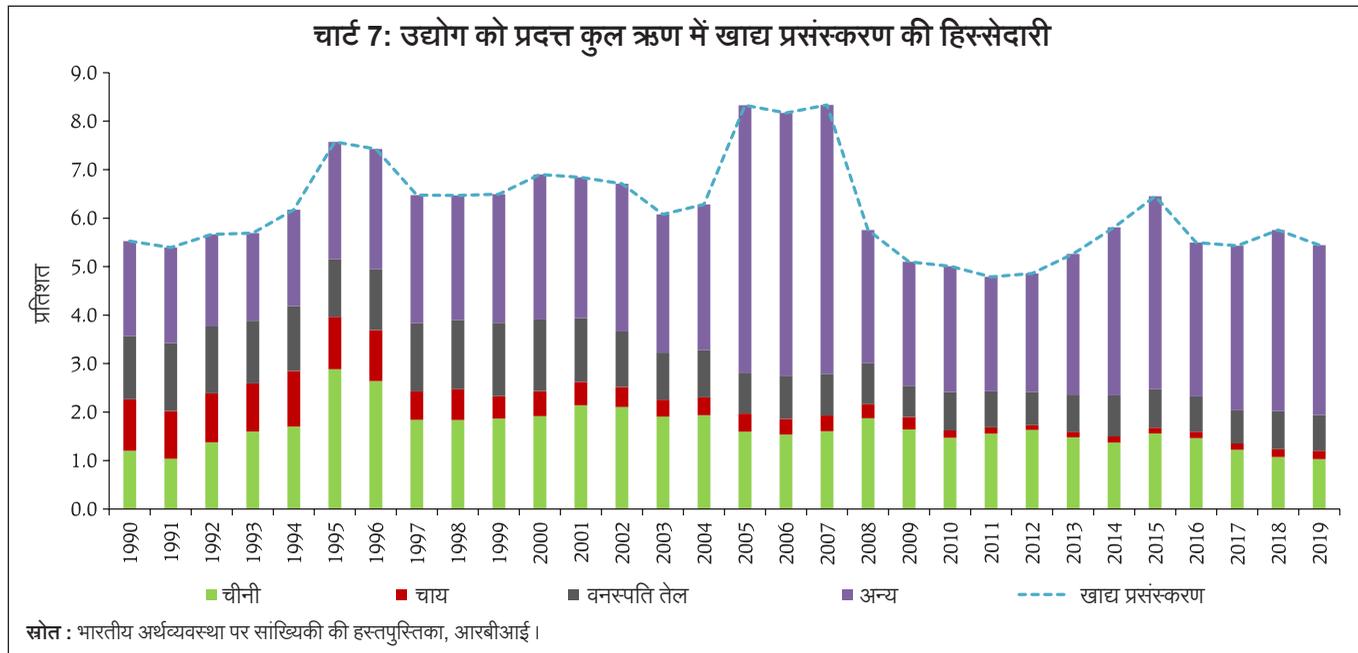
एफपीआई फर्मों का औसत लीवरेज, जिसे कर्ज-इक्विटी अनुपात के रूप में मापा जाता है, 2012-13 के बाद काफी बढ़ा, विशेष रूप से प्राइवेट लिमिटेड फर्मों के मामले में, जो संभवतः मध्यम और लघु उद्यमों में वित्तीय संकट का संकेत है। एफपीआई फर्मों का बिक्री में निर्यात अनुपात और सकल स्थिर आस्तियों में जीवीए अनुपात आम तौर पर समग्र गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के उक्त अनुपात के मुकाबले कम पाया जाता है (अनुबंध I, सारणी ए2)। यह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारतीय एफपीआई क्षेत्र की कमजोर भागीदारी और समग्र क्षेत्रीय उत्पादन में उच्च मूल्य संवर्धन करने की उनकी कम क्षमता का संकेत है। यह भी आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि एफपीआई की अधिकांश फर्म प्राथमिक या गौण प्रसंस्करण गतिविधि में शामिल हैं और बड़े पैमाने पर घरेलू मांग को पूरा करती हैं। यह जोड़ा जा सकता है कि एफपीआई फर्मों का आस्तियों में बिक्री अनुपात, अर्थात्, आस्ति टर्नओवर अनुपात [फर्मों द्वारा भौतिक निवेश के कुशल दोहन का

एक माप] समग्र उद्योग की अपेक्षा काफी अधिक है, जो, फिर भी इस बात का ज्यादा संकेत देता है कि क्षेत्र में अधिक दक्षता की अपेक्षा मूल्य संवर्धन कम हुआ है।

ऋण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में अत्यंत महत्व दिया जाता है। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का दर्जा दिया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों एवं कोल्ड चेन को प्रदत्त ऋणों को कृषि गतिविधियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। बैंकिंग प्रणाली से खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण के लिए प्रति उधारकर्ता ₹100 करोड़ की कुल स्वीकृत सीमा तक के ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा, कृषि अवसंरचना विकसित करने हेतु प्रदत्त ऋणों को भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, भंडारण सुविधाओं (वेयरहाउस, मार्केट यार्ड, गोडाउन और साइलो) के निर्माण के लिए प्रदान किए गए ऋण, जिसमें कृषि उपज / उत्पादों के भंडारण के लिए तैयार की गई कोल्ड स्टोरेज इकाइयां / कोल्ड स्टोरेज चेन शामिल हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आते हैं, साथ ही उसमें खाद्य प्रसंस्करण में शामिल एमएसएमई को प्रदान किए गए ऋण भी आते हैं।

चार्ट 7: उद्योग को प्रदत्त कुल ऋण में खाद्य प्रसंस्करण की हिस्सेदारी



उद्योग को प्रदान किए गए कुल ऋण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की हिस्सेदारी घटती गई, जो 1990 के बाद से 10 प्रतिशत से कम है और जो विनिर्माण जीवीए में एफपीआई की हिस्सेदारी के अनुरूप है (चार्ट 7)।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने में ऋण के महत्व की जांच करने के लिए, हम एसआई उद्योग स्तर के डेटा का उपयोग करके एक पैनेल डेटा विश्लेषण का प्रयास करते हैं। एसआई भारत में औद्योगिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है जो राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) के आधार पर विभिन्न स्तरों पर प्रमुख विशेषताओं के बारे में उद्योग वार वार्षिक डेटा प्रदान करता है। वर्तमान अध्ययन में, स्तर (4 अंक) तक के एसआई आंकड़ों पर विचार किया गया है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रमुख उप क्षेत्रों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। डेटा वार्षिक हैं और 1993-94 से 2015-16 की अवधि से संबंधित हैं।

एसआई उत्पादन, निश्चित निवेश, लाभ और बकाया ऋण के बारे में उद्योग स्तर का डेटा प्रदान करता है। यह शहरीकरण के लिए नियंत्रित सकल उत्पादन और पूंजीगत व्यय पर ऋण के प्रभाव का आकलन करने का अवसर प्रदान करता है। पूंजीगत व्यय को निश्चित निवेश में एक अवधि के अंतर के रूप में लिया जाता है। पैनेल यूनिट रूट टेस्ट से चर I (1) होने का पता चलता है (सारणी 7)।

वेस्टरलुंड (2007) परीक्षण का उपयोग करते हुए पैनेल को-इंटीग्रेशन निम्न दो समीकरणों के लिए अलग-अलग चलाया जाता है ताकि उत्पादन और पूंजीगत व्यय पर ऋण के प्रभाव की जांच की जा सके:

$$\text{Grossoutput}_{it} = \gamma_i + \beta \text{Loanoutstanding}_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Capital expenditure}_{it} = \gamma_i + \beta \text{Loanoutstanding}_{it} + \varepsilon_{it}$$

सारणी 7: इम-पेसरन-शिन पैनेल यूनिट-रूट टेस्ट का परिणाम

चर	पैनेल की संख्या	स्तर	पहला अंतर
सकल उत्पादन	11	3.33	-8.35***
बकाया ऋण	11	1.04	-9.89***
पूंजीगत व्यय	11	3.75	-8.41***

*** : p<0.01.

सारणी 8: सभी पैनेल को को-इंटीग्रेट कर (11 उद्योगों के लिए) वेस्टरलुंड टेस्ट का उपयोग करके पैनेल को-इंटीग्रेशन का भिन्नता अनुपात

एच0: कोई को-इंटीग्रेशन नहीं	
एच1: सभी पैनेल को को-इंटीग्रेट किया जाता है	
सकल उत्पादन	पूंजीगत व्यय
-2.41***	-2.94***

*** : p<0.01.

अशक्त परिकल्पना यह है कि चरों के बीच कोई को-इंटीग्रेशन नहीं है। परिणामों ने चरों के बीच दीर्घकालिक संबंध की उपस्थिति को मान्य ठहराया (सारणी 8)।

चरों के बीच एंडोजेनिटी का समाधान करने के लिए, एरिलानो और बॉन्ड (1991) जेनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमन्ट्स का उपयोग दीर्घ कालिक संबंध का आकलन करने के लिए किया जाता है। परिणामों से पता चला कि ऋण का सकल उत्पादन, और कैपेक्स की वृद्धि के साथ सकारात्मक संबंध है (सारणी 9)। ऋण में एक यूनिट वृद्धि से सकल उत्पादन में 17 प्रतिशत सुधार और पूंजीगत व्यय में 22 प्रतिशत सुधार होगा। इससे पता चलता है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र सुधार के लिए ऋण व्यवस्था संबंधी नीति फायदेमंद हो सकती है।

सारणी 9: दीर्घकालिक संबंध का अनुमान

चर	सकल उत्पादन का लॉग	पूंजीगत व्यय का लॉग
सकल उत्पादन का लॉग[-1]	0.825** (0.058)	
पूंजीगत व्यय का लॉग[-1]		0.723* (0.096)
बकाया ऋण का लॉग	0.173** (0.050)	0.224* (0.095)
कॉन्सटन्ट	0.518 (0.207)	0.398 (0.297)
ऑब्जर्वेशन्स	223	226
क्षेत्रों की संख्या	11	11
वालड ची2 (2)	10704***	862.6***
प्रतिबंध ची2(172) की अधिक पहचान करने वाला सरगन परीक्षण	197.75*	246.16***

कोष्ठकों में क्लस्टर मजबूत मानक त्रुटियां।

*** : p<0.01; ** : p<0.05; और * : p<0.1.

IV. सरकारी पहल

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आय को बढ़ावा देने में एफपीआई की भूमिका को समझते हुए, भारत सरकार ने इसे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में स्थान दिया है। एफपीआई मुख्य रोजगार सृजन क्षेत्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भरता को कम करने का अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए सरकार द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली छह प्रमुख चुनौतियों की पहचान की है: (i) आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना में कमी (अर्थात्, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण सुविधाओं की कमी); (ii) उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच अपर्याप्त सह-संबंध; (iii) परिचालन कार्यों की समयानुकूलता और कम क्षमता उपयोग; (iv) आपूर्ति श्रृंखला में संस्थागत कमी, जैसे, एपीएमसी बाजारों पर निर्भरता आदि; (v) गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर अपर्याप्त ध्यान; और (vi) उत्पाद विकास और नवोन्मेषण की कमी (भारत सरकार, 2018)। तदनुसार, बुनियादी ढांचे का निर्माण, निर्यात को बढ़ावा देने, गुणवत्ता मानकों में सुधार, औपचारिक ऋण की आपूर्ति में विस्तार, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों के लिए और अर्थव्यवस्था में कुशल श्रम समूह को बढ़ाने के जरिए आपूर्ति श्रृंखला को सहज बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्य नीतियों की विशिष्टताओं को अनुबंध II में उल्लिखित किया गया है।

V. सारांश

यद्यपि भारत कच्चे माल के स्तर पर कृषि उत्पादन का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है, लेकिन उनमें से केवल 10 प्रतिशत से भी कम का प्रसंस्करण और व्यापार किया जाता है। इसका एक बड़ा कारण घरेलू स्तर पर बड़े उपभोक्ता आधार का होना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की अपेक्षा ताजे उत्पाद को प्राथमिकता देना है। शहरीकरण की धीमी गति और महिला श्रम बल की भागीदारी में कमी के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर ताजा खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता मिली है। अनुभवजन्य साहित्य बताता है कि जैसे-जैसे अधिक महिलाएं कार्यबल में प्रवेश करती हैं, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ती है (वांग, और अन्य, 2015)। भारत में गुणवत्ता मानकों का पालन करने के जरिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरने की

क्षमता है। गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने के संबंध में सरकार की पहल क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है।

कॉर्पोरेट डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि खाद्य प्रसंस्करण फर्मों की लाभप्रदता अन्य फर्मों के स्तर की अपेक्षा या तो अधिक या तुलनीय है। हालांकि, खाद्य प्रसंस्करण फर्मों में मूल्य वर्धित घटक औद्योगिक क्षेत्र में परिचालन कर रहे अन्य फर्मों की अपेक्षा कम पाया गया। ऋण के संबंध में अर्थमितीय विश्लेषण से इस क्षेत्र में वृद्धि के लिए ऋण के महत्व का पता चलता है। औद्योगिक जीवीए में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की हिस्सेदारी के सापेक्ष, क्षेत्रीय क्रेडिट डेटा बताते हैं कि क्षेत्र के लिए ऋण की पर्याप्त उपलब्धता है।

तेजी से बढ़ती शहरी और युवा आबादी के साथ, आने वाले वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि होना तय है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आवश्यक बुनियादी ढांचे में निवेश करके मांग को पूरा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इस उद्योग को उत्पादकों / किसानों से विशिष्ट गुणवत्ता मानकों और स्थिर कीमतों वाले कच्चे माल के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। कृषक उत्पादक संगठन, छोटे किसानों और कृषि उद्यमियों को एक साथ लाकर, और अधिक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए इस अवसर को बेहतर कर सकते हैं। किसानों के लिए आय के निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के अलावा, उद्योग के साथ बेहतर सह-संबंध से क्षति को कम किया जा सकता है, विशेष रूप से नष्ट होने वाली वस्तुओं के मामले में।

संदर्भ

- Arathi, L. R., Kumar, S., Negi, D. S., & Singh, D. R. (2012). Prevailing Standards and Dimensions Governing Sanitary and Phyto-Sanitary Compliance in Indian Black Pepper Supply Chain. *Agricultural Economics Research Review*, 25, 69-78.
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data : Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. *The Review of Economic Studies*, 58(2), 277-297.
- Balassa, B. (1965). Trade liberalisation and Revealed Comparative Advantage. *The Manchester School*, 33, 99-123.

- Ghosh, N. (2014). *An assessment of the extent of food processing in various sub-sectors*. Revised report submitted to Ministry of Agriculture, Institute of Economic Growth, New Delhi.
- Government of India. (2016). *Government targets doubling food processing levels to 20 per cent World Food Summit to be held in New Delhi in March 2017, Ministry of Food Processing Industries*. Press Information Bureau.
- Government of India. (2017). *Make in India*. Retrieved from <http://www.makeinindia.com/sector/food-processing>.
- Government of India. (2017). *Annual Report-2016-17*. New Delhi: Ministry of Food Processing Industries.
- Government of India. (2018). *Annual Report-2017-18*. New Delhi: Ministry of Food Processing Industries.
- Government of India. (2019). *Annual Report-2018-19*. New Delhi: Ministry of Food Processing Industries.
- Goyal, T. M., Mukherjee, A., & Kapoor, A. (2017). *India's Exports of Food Products: Food Safety Related Issues and Way Forward*. New Delhi: Indian Council for Research on International Economic Relation.
- KPMG (2007). *Processed Food and Agribusiness: Opportunities for Investment in India*. Report prepared for MOFPI, New Delhi.
- Kumar, C. N. (2016). *Sensitivity of India's Agri-Food Exports to the European Union: An Institutional Perspective*. Working Paper, Institute for Social and Economic Change, Bangalore.
- Law, C., Green, R., Kadiyala, S., Shankar, B., Knai, C., Brown, K. A. & Cornelsen, L. (2019). Purchase Trends of Processed Foods and Beverages in Urban India. *Global Food Security*, 23, 191-204.
- Liu, E., Taylor, D., & Zhang, S. (2007). *Peoples Republic of China Food Processing Ingredients Sector*. GAIN Report. Foreign Agriculture Service, United States Department of Agriculture.
- Regmi, A. (2001). *Changing Structure of Global Food Consumption and Trade*. US Department of Agriculture.
- Regmi, A., & Gehlhar, M. (2005). New Directions in Global Food Markets. *Agriculture Information Bulletin (February)*, USDA, p. 82.
- Wang, C. M., Naidoo, N., Ferzacca, S., Reddy, G., Van, D. R., & Wang et al.. (2015). *The Role of Women in Food Provision and Food Choice Decision-Making in Singapore: A Case Study*. *Ecol Food Nutr*.
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*. 69(6): 709-748.
- Wilkinson, J., & Rocha, R. (2008). *Agri Processing in Developing Countries*. World Bank.
- World Trade Organisation. (2012). *World Trade Report 2012-Trade and Public Policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st Century*. WTO.

अनुबंध I

सारणी ए1: खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के चुनिंदा मदों की वृद्धि दर (प्रतिशत)

वित्त वर्ष	खाद्य प्रसंस्करण फर्म					समग्र गैर-वित्तीय फर्म				
	फर्मों की संख्या	बिक्री	कर पूर्व लाभ	सकल मूल्य संवर्धन	सकल स्थिर आस्तियां	फर्मों की संख्या	बिक्री	कर पूर्व लाभ	सकल मूल्य संवर्धन	सकल स्थिर आस्तियां
पब्लिक लिमिटेड फर्म										
2010-11	173	26.5	-7.5	6.3	10.7	3,041	21.2	11.3	15.4	15.5
2011-12	162	25.4	9.0	6.8	11.4	3,041	19.0	-4.7	6.4	11.1
2012-13	291	13.6	9.1	13.3	8.9	3,014	10.5	3.8	10.6	12.6
2013-14	676	13.7	5.2	11.9	10.5	4,388	10.6	4.7	10.4	15.1
2014-15	821	7.3	27.6	13.0	-0.7	16,923	4.8	15.9	12.8	5.8
2015-16	1,108	3.0	75.0	-2.2	5.2	19,602	0.7	9.5	8.7	7.5
2016-17	779	6.9	18.4	25.8	2.5	24,612	5.4	10.3	9.4	8.1
2017-18	779	9.9	42.5	52.1	8.4	16,130	10.1	7.7	7.1	5.5
प्राइवेट लिमिटेड फर्म										
2010-11	95	20.5	31.2	33.9	18.2	1,741	17.9	-14.8	13.3	10.4
2011-12	63	23.5	70.2	27.1	13.9	1,628	24.1	-0.3	19.4	14.7
2012-13	5,610	23.5	30.0	24.7	23.9	2,55,426	13.3	14.6	16.3	21
2013-14	5,436	8.3	-8.8	9.8	10.4	2,37,398	8.7	19.9	20.1	12
2014-15	6,931	10.2	9.3	14.6	-1.1	2,92,308	13.2	18.0	18.1	4.3
2015-16	9,988	10.6	57.0	22.3	25.6	4,06,739	5.9	16	15.1	17.2
2016-17	5,946	45.3	140.8	58.9	22.4	2,45,333	9.1	17.3	15.3	6.2
2017-18	5,946	-15.9	-51.1	-17.3	-6.8	2,45,333	10.6	18.7	14.7	10.7

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस, आरबीआई।

सारणी ए2: खाद्य प्रसंस्करण फर्मों के प्रमुख वित्तीय अनुपात (प्रतिशत)

वित्त वर्ष	खाद्य प्रसंस्करण फर्म				समग्र गैर-वित्तीय फर्म			
	इक्विटी की तुलना में कर्ज	सकल स्थिर आस्तियों की तुलना में बिक्री	बिक्री की तुलना में निर्यात	सकल स्थिर आस्तियों की तुलना में सकल मूल्य संवर्धन	इक्विटी की तुलना में कर्ज	सकल स्थिर आस्तियों की तुलना में बिक्री	बिक्री की तुलना में निर्यात	सकल स्थिर आस्तियों की तुलना में सकल मूल्य संवर्धन
पब्लिक लिमिटेड फर्म								
2010-11	56.8	210.8	10.8	30.7	42.0	148.7	18.6	35.6
2011-12	34.3	311.1	12.9	30.4	39.1	204.6	11.2	50.5
2012-13	39.1	256.3	10.5	32.7	42.9	152.0	20.6	32.1
2013-14	42.3	248.1	9.7	27.7	43.7	139.0	18.4	30.5
2014-15	56.2	–	4.0	33.5	46.9	115.1	14.2	26.4
2015-16	47.2	–	3.2	35.0	52.6	112.1	15.2	23.9
2016-17	40.7	–	2.9	29.7	45.9	106.2	10.7	23.7
2017-18	37.4	–	1.8	42.9	43.2	109.5	8.9	23.8
प्राइवेट लिमिटेड फर्म								
2010-11	26.8	466.4	9.1	42.2	33.1	213.7	10.0	50.3
2011-12	15.5	413.1	4.3	42.0	39.1	204.6	11.2	50.5
2012-13	12.2	431.0	11.6	43.9	40.6	208.1	10.6	50.8
2013-14	39.9	349.5	5.3	28.2	47.2	242.0	5.6	36.8
2014-15	41.8	340.0	3.7	30.2	49.5	234.2	6.3	37.2
2015-16	57.2	–	3.6	34.0	59.4	282.1	2.9	44.8
2016-17	65.7	–	2.6	39.7	56.0	292.6	2.3	45.2
2017-18	56.3	–	3.9	30.9	56.6	298.4	2.1	47.8

- : उपलब्ध नहीं।

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस, आरबीआई।

अनुबंध II

भारत में एफपीआई के विकास के लिए सरकारी पहल

इन्फ्रास्ट्रक्चर : खाद्य प्रसंस्करण में शामिल उद्यमों की संख्या कम होने का निराकरण करने के लिए, सरकार द्वारा क्लस्टर दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाता है जो सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखलाओं के जरिए किसानों और उद्यमियों को एक साथ लाता है और इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं आम सुविधाएं विकसित करना है। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के दो आधारभूत घटक अर्थात्, बुनियादी सक्षम इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़कें, जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, ड्रैनेज, एफ्लुअंट ट्रीटमेंट प्लान, आदि), और कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर/ आम सुविधाएं (वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज इंडविजुअल क्विक फ्रीजिंग, ट्रेडर पैक, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, आदि) एवं ₹25 करोड़ के न्यूनतम निवेश वाले कम से कम 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ होंगे (भारत सरकार, 2017)। वर्ष 2008 में मेगा फूड पार्क (एमएफपी) योजना का कार्यान्वयन, मॉडर्न टर्मिनल मार्केट्स (एमटीएम) और थोक भंडारण सुविधाओं के साथ-साथ बाजारों का आधुनिकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं इस संबंध में किए गए कुछ प्रयास हैं।

इसके अलावा, आम आपूर्ति श्रृंखला इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड चेन, ड्राई स्टोरेज, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, बैंक एंड फ्रंट-एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार, आदि, के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं, ताकि निवेश की लागत को कम किया जा सके, व्यवहार्यता को बढ़ाया जा सके और नियामक मानकों का उच्च अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। परियोजना आयात के तहत, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी सामानों पर उनके टैरिफ वर्गीकरण के बावजूद 5 प्रतिशत का एक समान सीमा शुल्क लगाया जाता है।

खाद्य सुरक्षा मानदंडों का मानकीकरण : विरासत संबंधी मुद्दों और ढांचागत चुनौतियों के कारण, भारतीय राज्यों में खाद्य गुणवत्ता मानकों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर हैं। समय के साथ, बढ़ती मध्यम वर्गीय आबादी, वैश्वीकरण और स्वास्थ्य जागरूकता आदि के कारण खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के बारे में जागरूकता बढ़ी है। खाद्य गुणवत्ता मानकों के समान कार्यान्वयन के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने “एक राष्ट्र, एक खाद्य कानून” प्रारंभ किया है।

ऋण की उपलब्धता : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सस्ती दरों पर ऋण संवितरण को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में ₹2000 करोड़ का एक विशेष कोष स्थापित किया गया है। इसके तहत, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, आधुनिकीकरण और विस्तार एवं निर्दिष्ट फूड पार्क में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए परियोजना लागत का 95 प्रतिशत तक ऋण प्रदान किया जाता है।

मानव संसाधन और कौशल विकास : सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) के समर्थन से श्रमिकों के क्षेत्र विशिष्ट कौशल विकसित करने की पहल की है। वर्ष 2017 में, एक छत्र योजना के तहत सात प्रमुख योजनाओं का विलय किया गया है, अर्थात्, प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना को लागू किया गया है। इससे किसानों के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश की दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी खाते और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक श्रृंखला

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	45
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	46
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	47
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डालर का क्रय/विक्रय	48
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)	49
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	49
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	50
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	51
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	52
9	कुल चलनिधि राशियां	52
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	53
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	53
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	54
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	54
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	55
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	56
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	57
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	58
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	59
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	59
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	59
21	थोक मूल्य सूचकांक	60
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	64
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	64
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	65
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	65
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	66
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	67
28	वाणिज्यिक पत्र	67
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	67
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	68

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	69
32	विदेशी मुद्रा भंडार	69
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	69
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	70
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	70
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	71
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	71
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरिकी डॉलर)	72
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	73
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरिकी डॉलर)	74
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	75
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	76
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	77
	प्रासंगिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	79
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	80
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	81
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	82
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	83
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	84

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

— = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2018-19	2018-19		2019-20	
		ति2	ति3	ति2	ति3
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.0	6.1	5.6	4.8	4.5
1.1.1 कृषि	2.4	2.5	2.0	3.1	3.5
1.1.2 उद्योग	4.5	4.7	4.4	0.1	0.1
1.1.3 सेवाएं	7.5	7.2	7.3	6.8	6.4
1.1क अंतिम खपत व्यय	7.6	9.1	7.0	7.0	6.7
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	9.8	11.5	11.4	-4.1	-5.2
	2018-19	2018	2019	2020	
		दिसंबर	जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	3.8	2.5	1.6	-0.3	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	10.0	8.9	9.6	9.7	9.9
2.1.2 ऋण	13.3	13.9	14.8	7.0	7.2
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	13.4	13.8	14.7	6.9	7.1
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.9	-0.5	-0.1	12.9	11.2
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	14.5	17.0	16.2	10.2	12.3
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.5	10.2	10.4	10.4	11.2
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.25	19.50	19.25	18.50	18.25
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	5.1	4.7	4.8	4.7
3.4 ऋण-जमा अनुपात	77.7	78.2	78.0	76.2	75.8
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	99.9	139.2	127.7	39.0	44.4
3.6 निवेश-जमा अनुपात	26.9	27.9	27.9	28.7	28.0
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	5.4	1.1	4.4	74.1	46.9
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.50	6.50	5.15	5.15
4.2 रिवर्स रिपो दर	6.00	6.25	6.25	4.90	4.90
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.50	6.75	6.75	5.40	5.40
4.4 बैंक दर	6.50	6.75	6.75	5.40	5.40
4.5 आधार दर	8.95/9.40	8.95/9.45	8.95/9.45	8.45/9.40	8.45/9.40
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.05/8.55	8.15/8.55	8.15/8.55	7.65/8.00	7.50/7.95
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/7.50	6.25/7.50	6.25/7.50	6.20/6.40	6.10/6.40
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.25/3.50	3.25/3.50
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.35	6.57	6.43	5.11	4.94
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.31	6.65	6.56	5.03	5.13
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.35	6.84	6.69	5.22	5.24
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.39	6.94	6.78	5.30	5.29
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.34	7.41	7.30	6.74	6.86
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.17	69.98	71.11	71.22	71.51
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	77.70	80.18	80.50	79.19	78.82
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरिकी डालर					
1-माह (%)	6.07	4.37	4.05	3.96	3.52
3-माह (%)	4.80	3.97	4.22	3.90	4.25
6-माह (%)	4.16	4.09	4.11	4.38	4.21
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.4	2.1	2.0	7.4	7.6
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	5.2	6.6	9.6	7.5
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	4.3	3.5	2.8	2.6	3.1
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	2.7	1.4	3.0	11.5	10.0
6.3.2 ईंधन और पावर	11.5	7.6	1.8	-1.5	3.4
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	3.7	3.6	2.8	-0.3	0.3
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	10.4	0.7	1.9	-8.8	-0.7
7.2 निर्यात	8.7	1.8	3.9	-1.6	-1.7

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से सदर्थ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2018-19	2019	2020				
			फरवरी	जनवरी 31	फरवरी 7	फरवरी 14	फरवरी 21
1	2	3	4	5	6	7	
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2113764	2081582	2284695	2311245	2320416	2331422	2321924
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	11	11	10	11	10	13
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2113775	2081593	2284706	2311255	2320427	2331432	2321937
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	79481	77604	95254	94435	95087	97184	100833
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2033559	2003208	2188733	2216111	2224640	2233361	2220225
1.2.3 रुपया सिक्का	735	781	719	709	700	887	879
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	806012	653452	994030	952353	947454	945774	990618
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	101	101	100	101	100	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	565707	503336	550704	531170	556182	544151	550033
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4197	3547	6841	6826	6798	6765	6739
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3494	2420	3002	3033	3139	3125	3132
2.1.1.7 अन्य बैंक	32036	28801	31707	32048	31605	32289	31600
2.1.1.8 अन्य	199734	114483	400909	377649	347327	357760	398150
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	700	722	724	1485	2260	1542	822
2.1.2 अन्य देयताएं	1087686	1158897	1161436	1156768	1156313	1166858	1219283
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	1893698	1812349	2155466	2109121	2103767	2112632	2209901
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	11	11	10	11	10	13
2.2.2 विदेश में रखे शेष	646640	675711	955641	944139	954795	953600	1022250
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	73545	23324	6817	-	5081
2.2.3.2 राज्य सरकारें	10	547	1210	9927	8401	1227	2882
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	180688	147395	16915	19795	15446	37209	54186
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	13463	4504	4416	4416	2146	2463	1815
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	700	722	724	5055	11544	10875	10336
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	923080	886736	983670	983703	983736	983770	983803
2.2.6 अन्य आस्तियां	129106	96723	119334	118752	120871	123478	129535
2.2.6.1 सोना	87169	84101	111665	111107	112784	115272	120566

डेटा अनतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय	
जन. 1, 2020	3169	41214	-	290674	3430	-	-	-	-	-325289
जन. 2, 2020	3054	33722	-	414014	4225	-	-	-	-	-440457
जन. 3, 2020	2694	41498	-	388002	4685	-	-	-	-	-422121
जन. 4, 2020	1930	7197	-	-	2259	-	-	-	-	-3008
जन. 5, 2020	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-16
जन. 6, 2020	2640	23120	-	351658	3710	-	-	-	-	-368428
जन. 7, 2020	2905	19173	12000	331711	5165	-	-	10000	10000	-330814
जन. 8, 2020	2715	20142	-	294516	3833	-212	-	-	-	-308322
जन. 9, 2020	2835	15052	-	283892	2548	-	-	-	-	-293561
जन. 10, 2020	2849	22877	-	264080	3091	-	-	-	-	-281017
जन. 11, 2020	-	795	-	-	-	-	-	-	-	-795
जन. 12, 2020	-	289	-	-	250	-	-	-	-	-39
जन. 13, 2020	2909	22783	-	240516	4080	-56	-	-	-	-256366
जन. 14, 2020	2794	21571	1000	210008	3075	56	-	-	-	-224654
जन. 15, 2020	2864	22191	-	200049	3430	-	-	-	-	-215946
जन. 16, 2020	2769	34628	-	246789	6450	-	-	-	-	-272198
जन. 17, 2020	2939	37992	2100	210838	5989	-	-	-	-	-237802
जन. 18, 2020	9290	3352	-	-	5123	-	-	-	-	11061
जन. 19, 2020	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-15
जन. 20, 2020	3366	23153	-	190023	3916	-	-	-	-	-205894
जन. 21, 2020	3214	21533	5000	165014	3400	-	-	-	-	-174933
जन. 22, 2020	2959	44423	-	141544	2250	-	-	-	-	-180758
जन. 23, 2020	3074	53686	-	130032	3800	185	-	-	-	-176659
जन. 24, 2020	2844	62831	4000	142827	2915	-82	-	2950	10000	-188931
जन. 25, 2020	-	50	-	-	200	-	-	-	-	150
जन. 26, 2020	-	950	-	-	100	-	-	-	-	-850
जन. 27, 2020	2894	76496	-	130027	3325	82	-	-	-	-200222
जन. 28, 2020	2449	84372	3175	138930	2052	284	-	-	-	-215342
जन. 29, 2020	2544	72664	-	125029	2450	-426	-	-	-	-193125
जन. 30, 2020	2974	59773	-	155018	1785	426	-	-	-	-209606
जन. 31, 2020	2944	52333	2000	179394	2340	-	-	-	-	-224443

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डालर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2018-19	2019		2020
		जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डालर) (1.1-1.2)	-15377	293	4360	10266
1.1 क्रय (+)	40804	1025	5374	11486
1.2 विक्रय (-)	56181	732	1014	1220
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	-111946	1763	30894	72793
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरिकी डालर)	-15377	-25610	29741	40007
(करोड़ ₹)	-111945	-182314	205303	278096
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डालर)	-13774	-3032	-1875	-1215

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2018-19	2019		2020
		जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डालर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	13935	75	1690	400
1.2 विक्रय (-)	13935	75	1690	400
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डालर)	0	0	400	0

**सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)**

मद	31 जनवरी 2020 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	3010	1460	1550
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	1384	0	1384
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	7576	1705	5871
4. 1 वर्ष से अधिक	0	10020	-10020
कुल (1+2+3+4)	11970	13185	-1215

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2018-19	2019					2020	
		फरवरी 15	सितंबर 27	अक्तूबर 25	नवंबर 22	दिसंबर 20	जनवरी 31	फरवरी 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	12882	1085	48	4373	3231	3856	2340	4130
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
3.2 बकाया	2678	1794	2372	1884	1604	1615	1872	1815
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	15560	2879	2420	6257	4835	5471	4212	5945

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2018-19	2019		2020	
		जनवरी 18	दिसंबर 20	जनवरी 17	जनवरी 31
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2052209	1986735	2180612	2215516	2218775
1.1 संचलन में नोट	2110883	2039260	2245888	2278414	2284695
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25144	25055	25435	25495	25537
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	84561	78324	91454	89137	92199
2 जनता की जमाराशियां	1658254	1355836	1507735	1486313	1588103
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1626512	1329986	1473756	1453120	1554247
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	25850	33979	33194	33856
3 एम₁ (1 + 2)	3710464	3342571	3688348	3701829	3806879
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	140599	132503	141786	141786	141786
5 एम₂ (3 + 4)	3851063	3475074	3830134	3843615	3948665
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	11721603	11416213	12370541	12515775	12611745
7 एम₃ (3 + 6)	15432067	14758783	16058889	16217604	16418624
8 कुल डाकघर जमाराशियां	367287	352915	409246	409246	409246
9 एम₄ (7 + 8)	15799354	15111698	16468135	16626850	16827870

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2019		2020	
		जनवरी 18	दिसंबर 20	जनवरी 17	जनवरी 31
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4388490	4432878	4918791	4999887	5014594
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	801951	864060	979921	1070018	1057037
1.1.1 सरकार पर दावे	929686	864203	1002864	1070160	1057180
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	928166	858560	1001608	1062661	1055970
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1520	5643	1256	7499	1210
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाशियां	127735	143	22943	142	143
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	127693	101	22901	100	101
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3586539	3568818	3938870	3929869	3957557
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	10382719	9928857	10597315	10665549	10756819
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	15363	8278	6702	6236	6380
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	10367356	9920579	10590613	10659313	10750439
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	9771722	9332555	9945118	10003643	10105180
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	585931	579208	625750	637257	632356
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	9703	8817	19746	18413	12903
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	3070841	2944995	3440836	3489569	3569071
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	2848587	2815725	3222839	3271573	3351074
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	2848800	2815947	3223060	3271791	3351293
3.1.2 विदेशी देयताएं	213	222	221	218	219
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	222254	129271	217997	217997	217997
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25798	26178	26238	26280
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	2435870	2573745	2924232	2963640	2948140
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1058795	1127593	1123096	1137921	1158386
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1377075	1446152	1801136	1825719	1789754
एम₃ (1+2+3+4-5)	15432067	14758783	16058889	16217604	16418624

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2019		2020	
		जनवरी 18	दिसंबर 20	जनवरी 17	जनवरी 31
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	3710464	3342571	3688348	3701829	3806879
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	8911512	8410235	9176532	9255823	9402185
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	15646602	14965655	16203315	16354801	16552195
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2052209	1986735	2180612	2215516	2218775
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	13184397	12591463	13669723	13795330	13988261
1.2.1 मांग जमाराशियां	1626512	1329986	1473756	1453120	1554247
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11557885	11261477	12195966	12342210	12434014
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5201048	5067665	5488185	5553995	5595306
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284993	206310	156633	177185	176959
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6356837	6193812	6707782	6788216	6838708
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	25850	33979	33194	33856
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	378254	361607	319001	310762	311303
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	15659336	15236703	16396664	16555291	16647197
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4388490	4432878	4918791	4999887	5014594
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	801951	864060	979921	1070018	1057037
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3586539	3568818	3938870	3929869	3957557
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11270846	10803825	11477872	11555404	11632603
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	15363	8278	6702	6236	6380
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11255483	10795547	11471170	11549168	11626223
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	879849	863488	871958	879445	865080
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25798	26178	26238	26280
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2801726	2685862	3207853	3236032	3307262
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2815725	3222839	3271573	3351074
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-46861	-129863	-14986	-35541	-43812
2.4 पूंजी खाता	2346743	2365983	2465133	2497233	2497037
2.5 अन्य मदें (निवल)	493605	616725	962246	965527	931507

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2018-19	2019			2020
		जनवरी	नवंबर	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	15646602	14965655	16087659	16203315	16552195
2 डाकघर जमाराशियां	367287	352915	401165	409246	409246
3 एल₁ (1 + 2)	16013889	15318570	16488824	16612561	16961441
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	2932	2932	56839	54287	56400
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2656	2656	3262	3078	2976
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	31	31	49162	46887	49631
4.3 सावधि जमाराशियां	245	245	4415	4322	3793
5 एल₂ (3 + 4)	16016821	15321502	16545663	16666848	17017841
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	..
7 एल₃ (5 + 6)	16048726	16698753	..

टिप्पणी: नवंबर 2019 के बाद से, वित्तीय संस्थानों की देनदारियों पर अद्यतन डेटा इस सारणी में शामिल किया गया है, और इसलिए, पिछले डेटा के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2019		2020	
		जनवरी 18	दिसंबर 20	जनवरी 17	जनवरी 31
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	2065058	2272066	2304652	2310975
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	601969	535479	603702	588344	592254
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	558496	501646	562488	547082	550704
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	25850	33979	33194	33856
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	2770481	2626387	2909747	2926190	2937085
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	954802	912457	783826	766300	718117
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	801951	864060	979921	1070018	1057037
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	800473	858459	978707	1062561	1055869
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	17106	-	87735	73545
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	927427	840646	1000832	974192	981706
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	927427	840646	1000832	974192	981706
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	739	808	776	734	719
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	127693	101	22901	100	101
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1478	5601	1214	7457	1168
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	137488	40119	-202797	-309954	-345300
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	137488	40119	-202797	-309954	-345300
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	15363	8278	6702	6236	6380
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	2678	1704	1615	1403	1872
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25798	26178	26238	26280
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2815725	3222839	3271573	3351074
2.3.1 सोना	159585	152458	192925	203054	206919
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2689019	2663284	3029931	3068536	3144172
2.4 पूंजी खाता	970265	1043200	992085	1002238	1010660
2.5 अन्य मदें (निवल)	88530	84393	131011	135683	147726

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2019		2020			
		फरवरी 1	जनवरी 3	जनवरी 10	जनवरी 17	जनवरी 24	जनवरी 31
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	2770481	2621174	2886419	2911258	2926190	2923115	2937085
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	2061400	2268909	2297761	2304652	2307200	2310975
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	601969	533237	583847	580497	588344	581959	592254
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	26537	33663	33000	33194	33956	33856
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	801951	898829	1135209	1068159	1070018	1009271	1057037
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	137488	-8280	-411335	-321794	-309954	-284126	-345300
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	15363	8278	6273	6211	6236	6014	6380
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2846051	3298419	3259844	3271573	3315932	3351074
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25823	26238	26238	26238	26238	26280
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1058795	1149527	1168385	1127400	1137921	1150214	1158386

सं. 12: वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार/ माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2019		2020	
		जनवरी 18	दिसंबर 20	जनवरी 17	जनवरी 31
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	12410053	11831239	12830205	12953030	13146270
1.1.1 मांग जमाराशियां	1511287	1216819	1354601	1333983	1436076
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	10898766	10614420	11475605	11619047	11710195
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	4904445	4776489	5164022	5228571	5269588
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284993	206310	156633	177185	176959
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	5994321	5837931	6311583	6390476	6440607
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	378254	361607	319001	310762	311303
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	14032206	13562254	14540311	14598493	14707970
2.1.1 सरकार को ऋण	3379001	3361983	3712006	3703340	3730741
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	10653205	10200271	10828305	10895153	10977229
2.1.2.1 बैंक ऋण	9771722	9332555	9945118	10003643	10105180
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9730112	9261606	9859975	9921541	10026280
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	8542	11743	8862	10674	10967
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2055	1448	11330	10354	4965
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	870886	854526	862996	870482	856117
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-46861	-129863	-14986	-35541	-43812
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	262383	159027	278216	248971	242206
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	163719	154735	174575	173565	177731
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	145526	134154	118628	110947	108287
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	538104	530155	846390	935872	977850
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	565707	501646	562488	547082	550704
2.3.2 उपलब्ध नकदी	74877	68628	81105	78836	81846
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	102480	40119	-202797	-309954	-345300
2.4 पूंजी खाता	1352307	1298612	1448878	1470825	1462206
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	382835	471089	773631	764207	722229
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	398120	355680	441282	404883	435464
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-47846	-50275	47417	50776	54049

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 29, 2019 की स्थिति	2019		2020	
		जनवरी 18	दिसंबर 20	जनवरी 17	जनवरी 31
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3381056	3363431	3724228	3713695	3735706
2 वाणिज्यिक पत्र	90362	95517	94864	94900	94533
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	11535	11682	11593	12194	12172
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	69592	70839	66237	67117	70181
3.3 अन्य	6379	6438	5515	5561	5558
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	134819	137959	125665	145052	128910
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	268783	232105	235604	235028	230803
4.3 अन्य	170047	143494	197796	184689	191035
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	20988	64680	45966	44642	42478
5.2 वित्तीय संस्थाएं	98382	91762	79261	80928	79815

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			
	2018-19	2019		2020	2018-19	2019		2020
		जनवरी	दिसंबर	जनवरी		जनवरी	दिसंबर	जनवरी
1	2	3	4	5	6	7	8	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	222	222	219	219	147	148	142	142
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	276350	249877	272087	279961	271426	245414	267210	274771
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	181651	163087	196871	199874	176828	158763	192175	194935
1.2 बैंकों से उधार राशि	79487	74720	62874	66916	79459	74662	62839	66868
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	15212	12070	12341	13172	15139	11989	12196	12968
2 अन्य के प्रति देयताएं	13835976	13166822	14354171	14598326	13495672	12845016	13939154	14179055
2.1 कुल जमाराशियां	12901579	12302330	13474498	13726611	12573772	11994510	13076253	13324001
2.1.1 मांग	1542554	1249258	1424297	1468719	1511287	1221131	1390204	1436076
2.1.2 मीयादी	11359025	11053072	12050201	12257891	11062484	10773379	11686049	11887926
2.2 उधार	381864	371471	331782	315590	378254	366798	327452	311303
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	552533	493021	547891	556126	543646	483708	535449	543751
3 रिजर्व बैंक से उधार	180688	99949	30427	16915	180688	99949	30427	16915
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	180688	99949	30427	16915	180688	99949	30427	16915
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	657555	577763	646500	650929	640584	563952	628399	632550
4.1 उपलब्ध नकदी	76554	72427	89265	84192	74877	70838	86982	81846
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	581001	505336	557235	566737	565707	493114	541417	550704
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	372670	345272	291147	290083	327814	305148	231299	231689
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	245880	234563	178108	177911	223048	213921	151715	151438
5.1.1 चालू खाते में	17216	14852	18565	24106	13329	12578	16197	21442
5.1.2 अन्य खातों में	228663	219712	159543	153805	209719	201342	135518	129997
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	47047	39896	37935	37079	32252	24806	17203	20180
5.3 बैंकों को अग्रिम	32950	32247	34044	32315	29635	31469	28279	24959
5.4 अन्य आस्तियां	46793	38565	41060	42777	42879	34952	34102	35111
6 निवेश	3475607	3436915	3880225	3849826	3381056	3343608	3765269	3735706
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3467845	3430050	3859887	3838863	3379001	3342298	3751590	3730741
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7762	6865	20338	10963	2055	1311	13678	4965
7 बैंक ऋण	10047125	9628393	10287168	10431338	9771722	9351201	9967797	10105180
7क खाद्यान्न ऋण	64636	91818	112463	108222	41610	68791	85433	78899
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	9792287	9401364	10072725	10214129	9521994	9128803	9756870	9891381
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	27641	22458	25082	25518	26223	21114	24406	24595
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	160984	144459	132488	136627	158296	141968	130664	135171
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	24914	23017	24282	22922	24588	22775	23872	22422
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	41299	37095	32591	32142	40622	36541	31985	31611

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2019		2020	वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जनवरी 18	दिसंबर 20	जनवरी 31		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	8674893	8274989	8822209	8978800	3.5	8.5
1.1 खाद्यान्न ऋण	41474	70700	84863	78664	89.7	11.3
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	8633419	8204289	8737346	8900136	3.1	8.5
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1111300	1083159	1139092	1153386	3.8	6.5
1.2.2 उद्योग	2885778	2750038	2794372	2817525	-2.4	2.5
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	375505	371022	365398	373050	-0.7	0.5
1.2.2.2 मझौले	106395	103951	107166	106813	0.4	2.8
1.2.2.3 बड़े	2403878	2275065	2321808	2337662	-2.8	2.8
1.2.3 सेवाएं	2415609	2234030	2370600	2431975	0.7	8.9
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	138524	133198	140438	141293	2.0	6.1
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	18535	18858	18597	18775	1.3	-0.4
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	39005	38682	44745	45394	16.4	17.4
1.2.3.4 नौवहन	7748	7501	6548	6682	-13.8	-10.9
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	171517	169261	172553	172686	0.7	2.0
1.2.3.6 व्यापार	528158	495938	513987	519547	-1.6	4.8
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	250528	218556	228558	237341	-5.3	8.6
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	277630	277381	285429	282206	1.6	1.7
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	202291	198112	219585	227266	12.3	14.7
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	641208	557602	728561	737198	15.0	32.2
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	668623	614880	525586	563134	-15.8	-8.4
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	2220732	2137063	2433282	2497250	12.5	16.9
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	6299	4568	5450	6453	2.4	41.3
1.2.4.2 आवास	1160111	1120792	1289637	1316481	13.5	17.5
1.2.4.3 मीयादी जमा राशि की जमानत पर अग्रिम	82873	68721	64441	67240	-18.9	-2.2
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	6265	5841	5072	5185	-17.2	-11.2
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	88262	84237	105905	110864	25.6	31.6
1.2.4.6 शिक्षा	67988	69175	66895	67038	-1.4	-3.1
1.2.4.7 वाहन ऋण	202154	200582	213601	220240	8.9	9.8
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	606780	583147	682281	703749	16.0	20.7
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2739021	2664619	2787852	2772197	1.2	4.0
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1104988	1076840	1133239	1142576	3.4	6.1
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	1067175	1018050	1061953	1100615	3.1	8.1
1.2अ.2.1 विनिर्माण	375505	371022	365398	373050	-0.7	0.5
1.2अ.2.2 सेवाएं	691670	647028	696555	727566	5.2	12.4
1.2अ.3 आवास	432703	428701	456989	461089	6.6	7.6
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	24101	23521	35104	36176	50.1	53.8
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	53950	56584	53215	53101	-1.6	-6.2
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	397	383	395	413	4.0	7.8
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	662628	608556	711799	715057	7.9	17.5
1.2अ.8 निर्यात ऋण	15566	17519	15152	13503	-13.3	-22.9

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2019		2020	वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जनवरी 18	दिसंबर 20	जनवरी 31		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	2885778	2750038	2794372	2817525	-2.4	2.5
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	41752	41734	42741	41886	0.3	0.4
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	157058	150627	145578	150279	-4.3	-0.2
1.2.1 चीनी	29705	26559	24541	26288	-11.5	-1.0
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	21343	21585	20071	20745	-2.8	-3.9
1.2.3 चाय	4966	5091	5458	5438	9.5	6.8
1.2.4 अन्य	101044	97392	95508	97808	-3.2	0.4
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	14662	14574	15034	14991	2.2	2.9
1.4 वस्त्र	203549	198336	189152	190108	-6.6	-4.1
1.4.1 सूती वस्त्र	97726	96258	85688	87850	-10.1	-8.7
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2119	2144	2215	2198	3.7	2.5
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	26748	24378	26170	26017	-2.7	6.7
1.4.4 अन्य वस्त्र	76956	75556	75079	74043	-3.8	-2.0
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11071	10954	10949	10882	-1.7	-0.7
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	11968	11694	12067	12205	2.0	4.4
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	30319	30024	30697	31085	2.5	3.5
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	63136	57130	53536	55622	-11.9	-2.6
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	191484	179380	177427	183048	-4.4	2.0
1.9.1 उर्वरक	40043	27453	34375	34535	-13.8	25.8
1.9.2 औषधि और दवाइयां	50500	51154	49839	52072	3.1	1.8
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	46717	47990	39154	40697	-12.9	-15.2
1.9.4 अन्य	54224	52783	54059	55744	2.8	5.6
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	45803	45283	49164	49254	7.5	8.8
1.11 कांच और कांच के सामान	9887	9915	8784	8678	-12.2	-12.5
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	55683	55359	58502	57715	3.6	4.3
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	371564	369449	337587	335104	-9.8	-9.3
1.13.1 लोहा और स्टील	282878	283306	254848	252173	-10.9	-11.0
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	88686	86143	82739	82931	-6.5	-3.7
1.14 सभी अभियांत्रिकी	168621	161122	158648	157586	-6.5	-2.2
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	37856	37580	33145	33594	-11.3	-10.6
1.14.2 अन्य	130765	123542	125503	123992	-5.2	0.4
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	79859	80171	82840	79793	-0.1	-0.5
1.16 रत्न और आभूषण	72014	68111	60452	59841	-16.9	-12.1
1.17 निर्माण	99473	95081	102579	105113	5.7	10.6
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1055921	986836	1029417	1036852	-1.8	5.1
1.18.1 पावर	568966	554164	562025	559305	-1.7	0.9
1.18.2 दूरसंचार	115585	92792	134310	136080	17.7	46.7
1.18.3 सड़क	186852	188236	186870	192232	2.9	2.1
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	184518	151644	146212	149235	-19.1	-1.6
1.19 अन्य उद्योग	201954	184258	229218	237483	17.6	28.9

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2018-19	2018		2019					
		दिसंबर, 28	अक्तूबर, 25	नवंबर, 08	नवंबर, 22	नवंबर, 29	दिसंबर, 06	दिसंबर, 20	दिसंबर, 27
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	31	31	29	30	30	30	30	30
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	62003.4	55352.2	63533.5	62705.3	64039.0	65921.6	122809.6	123291.7	123179.7
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	18241.3	17271.8	18303.6	17776.6	18086.2	18502.7	23045.1	24293.2	23483.5
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5842.3	5018.4	5177.4	4984.9	5157.7	5353.2	4226.5	3973.9	4316.8
2.1.1.2 अन्य	9,808.6	9042.9	9675.2	9232.9	9891.0	9997.5	12582.4	13224.2	13180.2
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	249.9	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	25.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	2590.5	2960.5	3431.1	3558.8	3017.5	3152.0	6236.2	7070.1	5986.4
2.2 मीयादी देयताएं	98531.4	86247.2	109253.5	109411.3	110399.6	113574.2	160651.0	162694.5	162534.0
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	45655.9	39261.5	54502.9	55098.0	55354.5	56770.2	48880.0	51079.3	50938.9
2.2.1.2 अन्य	52194.8	46309.3	53858.3	53472.4	54148.0	55924.1	110227.2	110067.5	109999.5
2.2.2 बैंकों से उधार	0.0	0.6	0.0	5.0	0.0	0.0	632.9	673.0	743.7
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	680.7	675.8	892.2	835.9	897.1	879.8	910.8	874.7	851.9
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	50375.4	51603.9	45401.3	43499.4	42985.4	46581.3	46786.6	47670.2	48445.0
4.1 मांग	16826.7	16912.1	12636.9	12842.2	12591.5	13300.6	14149.6	14121.3	14382.0
4.2 मीयादी	33548.7	34691.9	32764.4	30657.2	30393.9	33280.7	32636.9	33548.9	34063.0
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	5721.0	4594.7	6018.5	5213.4	5418.8	6014.5	6813.0	9236.7	8941.9
5.1 उपलब्ध नकदी	319.1	302.1	297.0	300.1	311.1	307.9	856.6	770.4	712.5
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5401.9	4292.6	5721.5	4913.3	5107.7	5706.7	5956.3	8466.3	8229.5
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1543.2	1279.2	726.5	740.1	974.0	716.0	1185.1	814.3	677.7
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	30885.3	30914.9	32366.1	33174.3	33051.2	32995.3	48688.4	49795.3	49891.9
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	16190.2	23287.6	18737.1	17643.3	17282.6	20094.5	22024.8	23287.8	25021.1
9 बैंक ऋण (10.1+11)	60089.8	56179.2	62836.7	61915.1	74721.2	63337.3	98678.5	98692.2	100148.6
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	60086.2	56176.2	62835.0	61914.6	74720.6	63336.8	98678.0	98691.7	100148.1
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	82610.9	81784.8	78322.8	77988.3	78925.3	80806.6	77427.8	77825.3	77214.1
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	3.7	3.1	1.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2018-19			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जनवरी 19	दिसंबर 19	जनवरी 20	जनवरी 19	दिसंबर 19	जनवरी 20	जनवरी 19	दिसंबर 19	जनवरी 20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	139.5	138.4	139.1	137.4	154.3	153.1	137.3	156.3	154.5	137.4	155.0	153.6
1.1 अनाज और उत्पाद	137.7	137.2	137.5	136.6	142.8	143.7	138.3	144.9	145.6	137.1	143.5	144.3
1.2 मांस और मछली	149.5	147.5	148.8	152.5	165.3	167.2	149.4	164.5	167.5	151.4	165.0	167.3
1.3 अंडा	137.3	137.3	137.3	138.2	149.5	153.5	143.5	153.7	156.9	140.2	151.1	154.8
1.4 दूध और उत्पाद	142.7	141.3	142.2	142.4	148.7	150.5	141.7	147.5	149.3	142.1	148.3	150.1
1.5 तेल और चर्बी	124.0	117.6	121.6	123.9	127.5	132.0	118.1	122.7	126.3	121.8	125.7	129.9
1.6 फल	146.8	143.4	145.2	135.5	144.3	142.2	135.2	147.2	144.4	135.4	145.7	143.2
1.7 सब्जी	141.4	142.1	141.6	131.7	209.5	191.7	130.5	231.5	207.9	131.3	217.0	197.2
1.8 दाल और उत्पाद	124.1	115.3	121.1	121.3	138.8	141.0	118.2	137.2	139.1	120.3	138.3	140.4
1.9 चीनी और उत्पाद	111.9	110.8	111.5	108.4	113.6	113.8	110.4	114.7	114.8	109.1	114.0	114.1
1.10 मसाले	138.8	140.7	139.4	138.9	149.1	151.6	140.4	148.0	149.5	139.4	148.7	150.9
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	134.9	127.5	131.8	137.0	139.3	139.7	128.1	130.8	131.1	133.3	135.8	136.1
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	155.3	151.3	153.4	155.8	158.3	158.7	153.2	157.7	158.5	154.6	158.0	158.6
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	159.4	162.9	160.4	162.7	167.8	168.5	164.7	170.4	170.8	163.2	168.5	169.1
3 कपड़ा और जूते	150.3	139.3	145.9	149.9	151.9	152.1	141.1	144.6	144.9	146.4	149.0	149.2
3.1 कपड़ा	151.2	141.0	147.2	150.6	152.6	152.9	143.0	146.8	147.0	147.6	150.3	150.6
3.2 जूते	145.2	129.5	138.7	145.1	147.3	147.4	130.4	132.8	133.2	139.0	141.3	141.5
4 आवास	--	145.6	145.6	--	--	--	147.7	152.8	153.9	147.7	152.8	153.9
5 ईंधन और लाइट	147.0	129.3	140.3	146.2	149.9	150.4	128.6	133.6	135.1	139.5	143.7	144.6
6 विविध	138.6	131.1	134.9	141.7	147.1	148.1	131.8	137.7	138.4	136.9	142.5	143.4
6.1 घरेलू सामान और सेवा	145.9	134.8	140.6	150.1	151.2	151.7	136.3	139.8	140.1	143.6	145.8	146.2
6.2 स्वास्थ्य	143.5	135.5	140.5	149.6	154.8	155.7	137.8	143.2	143.8	145.1	150.4	151.2
6.3 परिवहन और संचार	128.5	120.3	124.2	128.6	135.0	136.2	118.6	125.2	126.0	123.3	129.8	130.8
6.4 मनोरंजन	140.4	130.3	134.7	142.9	149.5	150.0	131.9	136.8	137.2	136.7	142.3	142.8
6.5 शिक्षा	149.4	144.5	146.5	155.2	161.1	161.7	146.6	151.9	152.1	150.2	155.7	156.1
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	132.6	129.9	131.5	133.5	140.6	142.5	131.7	140.2	142.1	132.8	140.4	142.3
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	141.3	137.7	139.6	141.0	152.3	151.9	138.0	148.3	148.2	139.6	150.4	150.2

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2018-19	2019		2020
				जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	300	307	330	330
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	907	915	1014	1016
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	915	923	1019	1021

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2018-19	2019		2020
		जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	31193	32230	38092	39984
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	38404	39100	44576	46498

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2019			2020
			जनवरी	नवंबर	दिसंबर (अ)	जनवरी (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	119.8	119.2	122.3	122.8	122.9
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	134.2	133.8	147.2	148.8	147.2
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	143.7	144.2	162.6	162.5	160.8
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	146.7	151.8	162.5	163.4	164.9
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	147.3	140.5	199.5	196.6	183.6
1.1.1.3 दूध	4.440	143.1	143.4	146.6	147.5	148.7
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	138.0	142.6	148.7	148.8	152.2
1.1.1.5 मसाले	0.529	129.6	129.1	153.0	154.1	156.9
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.4	146.1	142.2	143.5	143.5
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	123.1	123.4	127.0	134.0	132.1
1.1.2.1 फाइबर	0.839	127.0	127.2	123.5	123.7	124.3
1.1.2.2 तिलहन	1.115	140.5	144.1	149.6	152.9	157.1
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	107.3	102.9	104.1	105.4	105.8
1.1.2.4 फूल	0.204	164.1	191.4	238.5	348.3	280.7
1.1.3 खनिज	0.833	136.5	136.7	142.6	153.6	142.6
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	123.0	123.4	133.0	147.3	133.0
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.5	183.3	176.4	176.0	176.4
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	92.4	84.7	86.0	86.0	88.3
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	104.1	99.3	101.3	101.3	102.7
1.2.1 कोल	2.138	123.3	123.6	126.5	126.5	126.5
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	132.9	133.9	141.9	141.9	141.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	120.3	120.0	131.1	131.1	131.1
1.2.2 खनिज तेल	7.950	96.7	88.4	91.1	91.2	93.5
1.2.3 बिजली	3.064	109.6	110.7	110.0	110.0	110.0
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	117.9	118.1	117.8	118.0	118.5
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	128.6	128.4	135.4	136.6	138.2
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	136.7	135.3	137.6	135.0	135.9
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस,मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	132.1	135.7	137.9	136.6	134.3
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	112.4	114.9	115.0	114.9
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	117.6	114.8	119.4	124.9	131.1
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	136.2	134.6	147.6	149.1	151.2
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	141.6	144.4	148.1	147.6	146.6
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	116.6	124.7	135.1	136.3	134.2
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	129.3	130.0	133.9	134.4	135.7
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	111.2	111.4	119.5	119.1	119.8
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.7	127.7	126.8	128.0	126.1
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स,और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	134.5	136.4	132.6	123.4	131.7
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	137.7	131.1	142.8	138.4	130.1
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	122.2	124.9	137.1	134.8	135.9
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.0	128.4	128.3	127.8	129.6
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.6	148.2	163.9	165.2	164.5
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	157.5	159.1	178.2	175.2	174.6
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	120.7	121.9	123.7	123.4	124.0
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.8	115.3	118.4	118.3	118.5
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	120.5	121.6	125.1	125.1	125.7
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	131.2	131.9	130.5	129.5	131.0
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	150.4	150.7	153.0	152.9	151.0
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	150.4	150.7	153.0	152.9	151.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2019			2020
			जनवरी	नवंबर	दिसंबर (अ)	जनवरी (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.9	119.0	116.5	116.9	116.4
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	110.6	111.3	105.2	106.2	105.6
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	127.3	128.4	130.2	129.8	129.5
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	112.9	112.8	114.7	114.6	114.7
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	130.3	134.5	134.8	135.0	135.1
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	138.7	140.2	146.0	146.5	147.2
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	118.3	119.4	117.9	116.8	116.0
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.8	138.3	138.6	139.1	138.0
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.4	139.3	139.6	140.1	138.6
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	137.0	135.7	136.1	136.6	136.4
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	121.8	121.3	119.2	118.9	118.3
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	111.0	107.7	106.0	104.4	103.0
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	134.7	135.7	136.3	136.4	137.1
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	123.5	124.0	121.1	121.2	120.7
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	133.5	134.2	133.1	133.1	133.1
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	124.5	125.5	121.0	120.5	119.8
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	136.3	137.2	135.8	135.2	136.2
1.3.7.3 बिल्डरों की बढईगीरी	0.036	158.7	157.0	176.3	177.8	178.0
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	124.1	124.0	121.6	123.7	120.7
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	123.3	124.9	119.7	119.5	119.1
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	129.3	131.5	122.6	123.0	122.6
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.5	117.9	114.0	112.9	112.7
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	120.6	121.3	120.8	120.6	119.9
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	146.6	145.4	151.7	150.3	151.5
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	146.6	145.4	151.7	150.3	151.5
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	119.1	119.6	116.5	116.2	116.3
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	125.0	125.5	117.0	116.8	116.8
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	121.1	122.7	123.4	123.8	123.2
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	117.6	115.7	110.8	109.0	110.8
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	120.2	122.5	122.9	121.4	121.5
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	112.7	113.9	114.0	114.0	114.3
1.3.10.6 साबुन और डिटरजेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	116.8	118.8	117.8	118.6	119.1
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	116.6	116.4	114.0	113.7	113.1
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.0	102.3	96.6	96.2	95.6
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	123.5	126.1	127.5	127.9	127.8
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	123.5	126.1	127.5	127.9	127.8
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	109.6	110.1	107.7	108.3	107.9
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	100.1	97.8	98.4	98.7
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.7	92.8	94.1	93.9	93.8
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	117.6	117.7	114.5	115.2	114.6
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	115.9	116.3	115.7	115.8	115.5
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	121.4	124.5	121.2	125.3	126.0
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	111.1	112.3	108.5	106.9	107.6
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	98.0	98.8	103.3	105.6	102.1
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.7	112.3	112.5	113.3	114.8
1.3.13.5 सीमेन्ट, गूना और प्लास्टर	1.645	114.3	115.2	118.5	118.3	117.8

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2019			2020
			जनवरी	नवंबर	दिसंबर (अ)	जनवरी (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेंट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.5	122.5	122.1	122.5	122.7
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	118.8	118.9	119.1	119.0	118.5
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	130.4	122.2	84.9	80.6	78.1
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	112.2	110.1	103.4	103.5	105.8
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	113.0	108.8	96.0	96.5	102.1
1.3.14.2 मेटेलिक आयसन	0.653	117.8	115.5	101.8	102.8	107.8
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.5	97.9	93.2	93.6	96.0
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	110.2	109.5	101.9	103.1	104.3
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	119.6	115.6	102.2	103.4	106.5
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	111.7	109.3	99.5	97.8	100.0
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	112.7	107.4	99.4	98.7	98.6
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.6	127.8	123.7	123.4	126.4
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.2	109.6	106.7	106.3	107.0
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.8	110.3	112.6	111.4	113.4
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	126.8	137.5	151.4	149.7	147.1
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.1	116.4	115.7	115.6	115.4
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	112.8	114.2	113.5	113.5	113.6
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	127.3	127.6	125.6	124.9	124.2
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरस को छोड़कर	0.145	105.9	104.8	106.3	106.3	106.3
1.3.15.4 धातु की फॉर्मिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.3	98.7	101.4	100.3	99.3
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	99.7	99.6	100.3	100.0	100.6
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	123.1	125.7	123.5	124.3	124.4
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	111.8	111.5	109.7	110.0	109.7
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	100.9	99.5	97.8	97.6	97.7
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	132.5	135.0	135.0	135.0	135.0
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	116.7	116.5	118.8	118.9	116.8
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.8	103.8	95.3	96.7	96.9
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	109.1	105.3	113.5	113.5	111.9
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.9	135.6	139.7	139.7	140.5
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.2	104.4	103.1	101.4	101.4
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.7	107.3	109.4	111.0	112.0
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	111.7	112.1	112.1	110.6	110.8
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	107.7	108.2	111.2	108.1	108.4
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.7	117.3	117.9	115.8	116.7
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	126.1	128.8	104.1	108.1	108.0
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	111.2	111.4	109.5	110.0	110.2
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.6	108.5	111.7	110.4	111.3
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.6	120.9	120.3	120.3	118.3
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	110.1	107.3	106.9	108.1
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	111.3	111.8	112.8	113.0	113.0
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	103.0	103.8	104.2	105.0	105.2
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	118.2	118.6	120.0	120.1	120.1
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.9	109.5	111.0	111.1	111.5
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गैयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.2	109.1	107.4	109.1	108.0
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	78.2	78.0	80.4	80.6	80.9
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	110.4	112.3	111.9	112.0	111.7

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2019			2020
			जनवरी	नवंबर	दिसंबर (अ)	जनवरी (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	129.6	129.1	130.4	130.5	128.4
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	116.9	118.7	120.9	121.1	121.1
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	101.8	103.6	107.9	109.0	108.2
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	75.7	75.4	74.3	75.2
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.7	126.9	123.6	124.2	126.3
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.9	119.1	119.9	117.2	119.3
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	123.8	122.8	126.7	127.0	126.7
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	67.3	67.0	65.6	65.4	65.4
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	112.8	113.3	115.0	114.9	115.1
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.3	113.6	115.2	115.0	115.0
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	112.2	113.0	114.8	114.8	115.3
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	111.7	112.9	118.4	118.4	118.7
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	104.7	105.8	106.6	106.6	106.6
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	106.6	107.9	114.7	114.7	115.2
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	127.8	129.3	130.5	130.5	128.2
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	123.5	125.0	126.9	127.0	127.4
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	127.3	130.9	129.2	129.9	129.7
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	127.3	130.9	129.2	129.9	129.7
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	107.0	106.9	113.5	114.1	113.1
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	103.9	103.7	110.6	111.3	110.3
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.1	172.1	175.9	172.7	177.2
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	127.4	129.4	130.9	131.4	131.7
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	132.2	135.1	137.0	138.7	134.6
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	159.2	160.8	162.5	162.5	162.9
2 खाद्य सूचकांक	24.378	138.1	138.3	152.4	152.8	152.3

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारंक	2017-18	2018-19	अप्रैल-दिसंबर		दिसंबर	
				2018-19	2019-20	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	125.3	130.1	128.4	129.1	133.9	133.5
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन और उत्खनन	14.37	104.9	107.9	103.4	104.0	114.4	120.6
1.2 विनिर्माण	77.63	126.6	131.5	129.8	130.5	135.8	134.2
1.3 बिजली	7.99	149.2	156.9	159.3	160.5	150.4	150.2
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	121.8	126.1	124.6	125.0	126.6	129.4
2.2 पूंजीगत माल	8.22	105.6	108.4	107.5	94.3	114.7	93.8
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	125.1	126.2	123.8	138.9	129.9	146.1
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	132.0	141.7	139.6	135.9	146.1	142.3
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	123.6	130.4	131.0	122.4	124.2	115.9
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	139.9	145.5	141.8	145.8	163.4	157.3

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-जनवरी			
	2019-20 (संशोधित अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	2018-19 (वास्तविक)	संशोधित अनुमानों का प्रतिशत	
				2019-20	2018-19
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	1850101	1250120	1181414	67.6	68.3
1.1 कर राजस्व (निवल)	1504587	998037	1019288	66.3	68.7
1.2 करेतर राजस्व	345514	252083	162126	73.0	66.1
2 पूंजीगत प्राप्तियां	81605	32737	49323	40.1	52.9
2.1 ऋण की वसूली	16605	14386	13717	86.6	104.3
2.2 अन्य प्राप्तियां	65000	18351	35606	28.2	44.5
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	1931706	1282857	1230737	66.4	67.5
4 राजस्व व्यय	2349645	2000595	1771851	85.1	82.8
4.1 ब्याज भुगतान	625105	471916	463325	75.5	78.9
5 पूंजी व्यय	348907	267734	229731	76.7	72.6
6 कुल व्यय (4+5)	2698552	2268329	2001582	84.1	81.5
7 राजस्व घाटा (4-1)	499544	750475	590437	150.2	143.7
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	766846	985472	770845	128.5	121.5
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	141741	513556	307520	362.3	656.7

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2019		2020				
		फरवरी 1	दिसंबर 27	जनवरी 3	जनवरी 10	जनवरी 17	जनवरी 24	जनवरी 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18521	30528	15629	11330	7855	8772	6106	7116
1.2 प्राथमिक व्यापारी	17878	9216	13566	10958	11914	13023	12681	12593
1.3 राज्य सरकारें	26999	57436	55446	54866	54611	50561	46206	40201
1.4 अन्य	27747	48665	105392	106699	104899	98308	96286	90368
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	31953	44314	69389	70625	71989	74700	73785	73542
2.2 प्राथमिक व्यापारी	38738	37319	26616	24601	25705	24126	26534	27297
2.3 राज्य सरकारें	28036	34544	6945	6991	7097	7097	7151	7155
2.4 अन्य	18567	16266	19404	21279	19808	19658	19176	19654
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	48811	47272	58261	57378	56795	55509	55090	55279
3.2 प्राथमिक व्यापारी	74170	76024	58889	53306	52679	51853	53981	55714
3.3 राज्य सरकारें	18892	8392	21790	21790	22318	22368	22369	22369
3.4 अन्य	62393	64826	55247	63153	64726	67573	66858	65783
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	165605	145239	140863	95935	72317	76374	138311	141449
4.4 अन्य	252	327	372	1081	273	369	464	382
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	412704	474803	506574	502976	500395	493547	486223	477071

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां				स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य					
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
91-दिवसीय खज़ाना बिल											
2019-20											
जनवरी 1	4000	61	26845	1007	5	3993	1007	5000	98.78	4.9386	
जनवरी 8	4000	54	13213	507	24	3993	507	4500	98.76	5.0525	
जनवरी 15	4000	55	14425	1814	24	3986	1814	5800	98.74	5.1381	
जनवरी 22	4000	65	18620	2007	16	3993	2007	6000	98.74	5.1167	
जनवरी 29	4000	61	11114	7	27	3993	7	4000	98.74	5.1266	
182-दिवसीय खज़ाना बिल											
2019-20											
जनवरी 1	6000	64	22541	658	23	5999	658	6657	97.46	5.2204	
जनवरी 8	6000	86	26513	17	24	5983	17	6000	97.47	5.2098	
जनवरी 15	6000	82	20351	10	34	5990	10	6000	97.46	5.2267	
जनवरी 22	6000	75	19993	30	43	5970	30	6000	97.46	5.2267	
जनवरी 29	6000	82	16002	7	61	5993	7	6000	97.45	5.2396	
364-दिवसीय खज़ाना बिल											
2019-20											
जनवरी 1	3000	63	11164	2	24	2998	2	3000	94.98	5.2998	
जनवरी 8	3000	80	13151	381	16	2999	381	3380	94.99	5.2871	
जनवरी 15	3000	70	13585	0	11	3000	0	3000	94.98	5.2998	
जनवरी 22	3000	75	13351	5	32	2995	5	3000	94.99	5.2887	
जनवरी 29	3000	67	9308	0	35	3000	0	3000	94.99	5.2890	

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1		2
जनवरी	1, 2020	3.60-5.25	5.12
जनवरी	2, 2020	3.00-5.25	5.01
जनवरी	3, 2020	2.75-5.25	4.89
जनवरी	4, 2020	4.15-5.15	4.69
जनवरी	6, 2020	2.75-5.25	4.89
जनवरी	7, 2020	3.00-5.25	4.92
जनवरी	8, 2020	3.40-5.25	4.91
जनवरी	9, 2020	3.50-5.25	4.96
जनवरी	10, 2020	3.60-5.25	4.98
जनवरी	13, 2020	3.60-5.25	4.97
जनवरी	14, 2020	3.60-5.25	4.97
जनवरी	15, 2020	3.60-5.25	4.94
जनवरी	16, 2020	3.60-5.25	4.95
जनवरी	17, 2020	3.50-5.25	5.00
जनवरी	18, 2020	4.25-5.20	4.77
जनवरी	20, 2020	3.60-5.25	4.96
जनवरी	21, 2020	3.60-5.25	4.94
जनवरी	22, 2020	3.60-5.25	4.96
जनवरी	23, 2020	3.60-5.25	4.97
जनवरी	24, 2020	3.50-5.45	4.96
जनवरी	27, 2020	3.70-5.25	4.92
जनवरी	28, 2020	3.70-5.25	4.94
जनवरी	29, 2020	3.70-5.25	4.95
जनवरी	30, 2020	3.70-5.25	4.92
जनवरी	31, 2020	3.50-5.25	4.96
फरवरी	1, 2020	4.25-5.25	4.90
फरवरी	3, 2020	3.70-5.25	4.93
फरवरी	4, 2020	3.70-5.25	4.98
फरवरी	5, 2020	3.70-5.40	4.93
फरवरी	6, 2020	3.70-5.25	4.99
फरवरी	7, 2020	3.60-5.25	5.03
फरवरी	10, 2020	3.70-5.30	5.02
फरवरी	11, 2020	3.70-5.25	5.00
फरवरी	12, 2020	3.70-5.25	4.92
फरवरी	13, 2020	3.70-5.25	4.95
फरवरी	14, 2020	3.50-5.25	5.01
फरवरी	15, 2020	4.25-5.05	4.81

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2019		2020		
	जनवरी 18	दिसंबर 20	जनवरी 3	जनवरी 17	जनवरी 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	190078.58	160669.00	178432.00	181344.00	181309.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	15103.27	13837.13	27207.97	7692.49	16507.91
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.75-9.00	4.97-5.84	4.93-6.76	5.10-6.86	5.20-7.50

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2019			2020	
	जनवरी 31	दिसंबर 15	दिसंबर 31	जनवरी 15	जनवरी 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	528741.20	457213.55	414906.30	434895.30	421988.85
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	107391.55	97114.00	83567.75	37801.80	72673.75
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.54-12.62	4.88-12.65	4.99-13.18	4.75-14.29	5.12-13.05

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2019		2020				
		जनवरी 25	दिसंबर 27	जनवरी 3	जनवरी 10	जनवरी 17	जनवरी 24	जनवरी 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	31280	40765	27553	22786	17015	12535	16270	14691
2 नोटिस मुद्रा	4930	765	238	3834	677	7873	805	8821
3 मीयादी मुद्रा	740	245	939	694	511	750	511	964
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	213010	261298	339731	411821	339237	372094	325737	362137
5 बाजार रिपो	200970	153261	230092	299793	216533	266469	201848	249932
6 कापरेट बांड में रिपो		3500	1528	1822	1177	918	1554	3235
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	50189	66546	55052	59430	60802	56489	72057
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	65800	61568	70654	64434	80793	64069	61839	60694
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	4320	4047	5891	5203	7929	2674	4644	4535
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3380	1794	6094	6227	1204	3860	2059	2049
10.2 182-दिवसीय	1450	2406	1577	2200	741	804	1267	1705
10.3 364-दिवसीय	1620	1815	1019	3953	1264	556	1018	597
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1400			12812	8074	7784	3206	2179
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	77970	71629	85234	94829	100005	79747	74033	71760
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	-	2764	4670	4739	4989	507	2594	37

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2018-19		2018-19 (अप्रै.-जन.)*		2019-20 (अप्रै.-जन.)*		जनवरी 2019		जनवरी 2020*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	129	16754	114	16550	63	64522	8	2030	7	3486
1ए प्रीमियम	124	16085	111	15927	61	42878	7	1912	6	3467
1.1 पब्लिक	119	14605	106	14452	51	9836	6	1776	6	56
1.1.1 प्रीमियम	115	14123	104	14005	49	9414	6	1698	5	42
1.2 राइट्स	10	2149	8	2098	12	54685	2	255	1	3430
1.2.1 प्रीमियम	9	1962	7	1922	12	33463	1	214	1	3425
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	25	36680	20	32557	27	11746	5	3992	–	–
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	25	36680	20	32557	27	11746	5	3992	–	–
3.1.1 पब्लिक	25	36680	20	32557	27	11746	5	3992	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	154	53433	134	49107	90	76267	13	6022	7	3486
4.1 पब्लिक	144	51284	126	47010	78	21582	11	5768	6	56
4.2 राइट्स	10	2149	8	2098	12	54685	2	255	1	3430

टिप्पणी : अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2018-19	2019					2020
			जनवरी	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड़ ₹	2307726	186801	186148	187074	185417	194747	185204
	मिलियन अमरिकी डालर	330078	26409	26095	26334	25950	27355	25970
1.1 तेल	करोड़ ₹	325929	22705	24718	25192	29286	27731	23555
	मिलियन अमरिकी डालर	46554	3210	3465	3546	4099	3895	3303
1.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	1981797	164096	161430	161882	156130	167016	161649
	मिलियन अमरिकी डालर	283525	23199	22630	22788	21851	23460	22667
2 आयात	करोड़ ₹	3594675	293225	268450	264581	272250	274866	293419
	मिलियन अमरिकी डालर	514078	41455	37633	37244	38103	38609	41145
2.1 तेल	करोड़ ₹	986275	79597	64373	68763	79087	76136	92503
	मिलियन अमरिकी डालर	140921	11253	9024	9680	11069	10694	12971
2.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	2608400	213629	204078	195818	193163	198731	200916
	मिलियन अमरिकी डालर	373158	30202	28609	27565	27034	27915	28173
3 व्यापार शेष	करोड़ ₹	-1286948	-106424	-82303	-77507	-86833	-80119	-108215
	मिलियन अमरिकी डालर	-184000	-15046	-11538	-10910	-12153	-11254	-15174
3.1 तेल	करोड़ ₹	-660346	-56892	-39655	-43571	-49800	-48404	-68948
	मिलियन अमरिकी डालर	-94367	-8043	-5559	-6133	-6970	-6799	-9668
3.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	-626602	-49532	-42648	-33936	-37033	-31715	-39267
	मिलियन अमरिकी डालर	-89633	-7003	-5979	-4777	-5183	-4455	-5506

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2019	2020					
		फरवरी 15	जनवरी 10	जनवरी 17	जनवरी 24	जनवरी 31	फरवरी 7	फरवरी 14
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड़ ₹	2837250	3272431	3285560	3328631	3363145	3378130	3398212
	मिलियन अमरिकी डालर	398273	461214	462157	466693	471300	473001	476092
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड़ ₹	2643930	3033747	3045938	3087772	3120106	3136686	3154503
	मिलियन अमरिकी डालर	371070	427582	428449	432919	437248	439186	441949
1.2 स्वर्ण	करोड़ ₹	161700	202156	203054	204812	206920	205541	207871
	मिलियन अमरिकी डालर	22764	28492	28562	28715	28997	28779	29123
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1049	1046	1046	1046	1046	1046	1045
	करोड़ ₹	10370	10235	10277	10290	10267	10259	10207
	मिलियन अमरिकी डालर	1455	1442	1446	1443	1439	1436	1430
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड़ ₹	21250	26294	26291	25757	25852	25644	25631
	मिलियन अमरिकी डालर	2983	3697	3701	3615	3615	3599	3590

* अंतर, यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरिकी डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2018-19	2019		2020	2018-19	2019-20
		जनवरी	दिसंबर	जनवरी	अप्रैल-जनवरी	अप्रैल-जनवरी
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130423	125204	133138	133471	8080	6636
1.1 एफसीएनआर (बी)	23170	21413	24018	24408	-613	1238
1.2 एनआर (ई) आरए	92017	89054	92889	92838	6842	3886
1.3 एनआरओ	15236	14737	16230	16225	1850	1512

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	2018-19	2018-19	2019-20	2019		2020
		अप्रैल-जनवरी	अप्रैल-जनवरी	जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	30712	27974	34109	3682	3882	5668
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	43302	37559	43960	4047	5065	6742
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	62001	52477	60022	5937	6817	8494
1.1.1.1.1 ईक्विटी	45055	38467	42905	4470	4717	5631
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	2429	2130	3051	97	45	24
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिजर्व बैंक	36315	31297	33212	3477	3646	4751
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	5622	4474	6076	834	967	795
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	689	566	566	61	58	61
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	13672	11239	11170	1217	1150	1217
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3274	2772	5946	251	950	1646
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	18699	14918	16062	1890	1752	1752
1.1.1.2.1 ईक्विटी	18452	14695	15893	1879	1748	1748
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	247	224	169	12	4	4
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	12590	9586	9851	365	1183	1074
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	7201	5777	5355	259	413	810
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3032	2527	2571	253	253	253
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5202	3331	3923	252	729	223
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	2845	2050	1998	398	212	212
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	-618	-10416	12432	-362	10	-227
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	1820	1820	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	-2225	-13378	12650	316	109	-127
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	213	-1142	217	678	100	100
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	30094	17558	46541	3320	3892	5441

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	2018-19	2019			2020
		जनवरी	नवंबर	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	13787.58	1336.42	1482.00	1563.72	1804.50
1.1 जमाराशियां	455.94	29.64	39.42	42.38	55.94
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	84.53	4.85	7.14	4.85	6.67
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	422.90	26.85	73.99	27.57	26.20
1.4 उपहार	1370.24	106.06	153.02	150.90	158.44
1.5 दान	8.67	0.57	0.48	0.89	1.10
1.6 यात्रा	4803.81	506.06	522.28	620.32	712.56
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2800.88	242.83	262.96	276.74	310.83
1.8 चिकित्सा उपचार	28.59	2.98	3.04	2.68	2.59
1.9 विदेश में शिक्षा	3569.87	400.34	400.98	420.45	510.26
1.10 अन्य	242.15	16.23	18.69	16.93	19.90

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2017-18	2018-19	2019	2020	
			फरवरी	जनवरी	फरवरी
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	76.94	72.64	71.64	72.26	72.73
1.2 रीर	119.71	114.01	112.07	118.69	119.47
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	78.89	74.18	73.19	73.72	74.09
2.2 रीर	121.94	116.32	114.43	121.42	122.04
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	67.91	63.07	62.29	62.98	63.37
1.2 रीर	129.19	121.70	119.72	126.72	127.18
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	92.88	91.73	92.74	93.32
2.2 रीर	100.00	94.20	92.67	98.09	98.45

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरिकी मिलियन डालर में)

मद	2018-19	2019		2020
		जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	999	76	109	110
1.2 राशि	28387	2267	1257	5869
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	21	1	4	4
2.2 राशि	13537	150	840	2532
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1020	77	113	114
3.2 राशि	41924	2417	2097	8401
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.20	4.70	4.70	7.10
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.20	1.19	1.41	1.24
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-15.00	0.00-11.00	0.00-25.00	0.00-11.10

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	जुलाई-सितंबर 2018			जुलाई-सितंबर 2019 (प्र.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	290140	292008	-1868	301536	296418	5118
1 चालू खाता (1.1+1.2)	160019	179073	-19054	161210	167487	-6276
1.1 पण्य	83399	133436	-50037	80014	118097	-38083
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	76620	45637	30984	81196	49390	31806
1.2.1 सेवाएं	50094	29839	20256	52380	31937	20443
1.2.1.1 यात्रा	7038	5813	1225	7643	6031	1611
1.2.1.2 परिवहन	4641	5086	-446	5183	6009	-826
1.2.1.3 बीमा	646	396	250	603	354	249
1.2.1.4 जीएनआईई	140	261	-122	169	298	-128
1.2.1.5 विविध	37629	18282	19348	38782	19245	19537
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	20757	1472	19286	23247	2182	21064
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	9408	9690	-282	10878	11211	-333
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1311	1132	180	1239	594	645
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	606	278	328	635	354	281
1.2.2 अंतरण	20891	1560	19331	21986	1999	19986
1.2.2.1 आधिकारिक	35	215	-180	50	251	-202
1.2.2.2 निजी	20856	1346	19511	21936	1748	20188
1.2.3 आय	5635	14238	-8603	6831	15454	-8623
1.2.3.1 निवेश आय	4560	13646	-9086	5426	14791	-9364
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1074	592	482	1404	663	741
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	129539	112935	16604	140326	128273	12053
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	77035	69423	7612	85399	75487	9913
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	14827	7417	7410	15298	7862	7436
2.1.1.1 भारत में	14076	4055	10021	14523	4482	10041
2.1.1.1.1 इक्विटी	10081	3894	6187	9935	4446	5489
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3344		3344	3310		3310
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	652	161	490	1279	37	1242
2.1.1.2 विदेश में	751	3361	-2610	775	3380	-2605
2.1.1.2.1 इक्विटी	751	1376	-625	775	1478	-703
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	758	-758	0	780	-780
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1228	-1228	0	1122	-1122
2.1.2 संविभाग निवेश	62208	62006	202	70101	67625	2476
2.1.2.1 भारत में	61036	61616	-580	68312	66307	2005
2.1.2.1.1 एफआईआई	59216	61616	-2400	68312	66307	2005
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	50860	52179	-1319	48252	51608	-3355
2.1.2.1.1.2 ऋण	8356	9436	-1081	20059	14699	5361
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	1820	0	1820	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1173	391	782	1789	1318	471
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	23578	16652	6926	21567	18396	3171
2.2.1 बाह्य सहायता	1216	1264	-48	1805	1362	443
2.2.1.1 भारत द्वारा	12	30	-18	5	24	-19
2.2.1.2 भारत को	1204	1234	-30	1800	1338	462
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	8951	6766	2185	9030	5656	3374
2.2.2.1 भारत द्वारा	1515	1349	166	1287	1082	205
2.2.2.2 भारत को	7436	5417	2019	7743	4574	3169
2.2.3 भारत को अल्पावधि	13411	8622	4789	10731	11378	-646
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	7392	8622	-1230	10731	10940	-209
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	6019	0	6019	0	437	-437
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	21194	20672	522	23881	25699	-1818
2.3.1 वाणिज्य बैंक	21194	20670	524	23881	25364	-1483
2.3.1.1 आस्तियां	5370	5638	-268	9914	10148	-235
2.3.1.2 देयताएं	15823	15031	792	13967	15216	-1249
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	15402	12075	3326	13458	11178	2280
2.3.2 अन्य	0	2	-2	0	335	-335
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	1	-1	0	2	-2
2.5 अन्य पूंजी	7732	6187	1545	9479	8689	790
3 भूल-चूक	582		582		658	-658
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	1868	0	1868	0	5118	-5118
4.1 आईएमएफ	0	0	0			
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	1868	0	1868		5118	-5118

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जुलाई-सितंबर 2018			जुलाई-सितंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2035381	2048484	-13103	2123697	2087648	36049
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1122561	1256224	-133664	1135391	1179595	-44204
1.1 पण्य	585056	936075	-351019	563533	831746	-268213
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	537505	320150	217355	571858	347850	224009
1.2.1 सेवाएं	351421	209324	142097	368905	224927	143978
1.2.1.1 यात्रा	49373	40780	8593	53826	42478	11348
1.2.1.2 परिवहन	32556	35682	-3126	36504	42320	-5817
1.2.1.3 बीमा	4534	2780	1755	4245	2494	1751
1.2.1.4 जीएनआईई	981	1834	-853	1193	2096	-904
1.2.1.5 विविध	263977	128249	135728	273138	135539	137599
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	145615	10323	135292	163725	15370	148355
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	65998	67978	-1981	76611	78960	-2348
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	9200	7939	1261	8729	4187	4543
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4252	1951	2302	4475	2494	1981
1.2.2 अंतरण	146556	10945	135611	154844	14081	140763
1.2.2.1 आधिकारिक	246	1506	-1260	349	1768	-1419
1.2.2.2 निजी	146310	9439	136871	154495	12313	142182
1.2.3 आय	39528	99881	-60353	48109	108842	-60733
1.2.3.1 निवेश आय	31992	95729	-63736	38218	104171	-65953
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	7535	4152	3383	9891	4671	5220
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	908738	792260	116478	988305	903419	84886
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	540417	487014	53403	601461	531648	69814
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	104014	52029	51985	107745	55373	52372
2.1.1.1 भारत में	98746	28449	70297	102287	31568	70719
2.1.1.1.1 इक्विटी	70719	27316	43403	69970	31310	38661
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	23456	0	23456	23309	0	23309
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	4570	1132	3438	9007	258	8749
2.1.1.2 विदेश में	5268	23581	-18313	5458	23805	-18346
2.1.1.2.1 इक्विटी	5268	9650	-4382	5458	10409	-4950
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5318	-5318	0	5496	-5496
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	8613	-8613	0	7900	-7900
2.1.2 संविभाग निवेश	436403	434985	1418	493716	476275	17441
2.1.2.1 भारत में	428177	432244	-4067	481114	466993	14122
2.1.2.1.1 एफआईआई	415410	432244	-16834	481114	466993	14122
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	356793	366047	-9253	339837	363469	-23632
2.1.2.1.1.2 ऋण	58616	66197	-7581	141277	103523	37754
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	12768	0	12768	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	8226	2741	5485	12602	9283	3320
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	165403	116817	48586	151892	129560	22332
2.2.1 बाह्य सहायता	8528	8864	-336	12711	9592	3120
2.2.1.1 भारत द्वारा	81	209	-128	36	169	-132
2.2.1.2 भारत को	8447	8655	-208	12675	9423	3252
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	62796	47467	15329	63600	39837	23764
2.2.2.1 भारत द्वारा	10627	9465	1162	9066	7623	1444
2.2.2.2 भारत को	52168	38001	14167	54534	32214	22320
2.2.3 भारत को अल्पावधि	94079	60487	33592	75580	80132	-4551
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	51855	60487	-8632	75580	77050	-1470
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	42224	0	42224	0	3081	-3081
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	148677	145018	3659	168191	180998	-12807
2.3.1 वाणिज्य बैंक	148677	145002	3675	168191	178639	-10448
2.3.1.1 आस्तियां	37674	39555	-1881	69820	71474	-1654
2.3.1.2 देयताएं	111003	105447	5556	98370	107165	-8794
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	108045	84711	23334	94785	78728	16056
2.3.2 अन्य	0	16	0	0	2359	-2359
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	9	-9	0	15	-15
2.5 अन्य पूंजी	54241	43401	10840	66761	61198	5563
3 भूल-चूक	4083	0	4083	0	4633	-4633
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	13103	0	13103	0	36049	-36049
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/कमी +)	13103	0	13103	0	36049	-36049

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	जुलाई-सितंबर 2018			जुलाई-सितंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	160019	179051	-19033	161208	167462	-6254
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क. + 1.अ.ख.)	133493	163275	-29781	132394	150033	-17640
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	83399	133436	-50037	80014	118097	-38083
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	83400	124239	-40839	79356	113743	-34388
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-1	0	-1	658	0	658
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		9197	-9197		4353	-4353
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	50094	29839	20256	52380	31937	20443
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	58	8	50	58	33	25
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	43	259	-216	44	253	-208
1.अ.ख.3 परिवहन	4641	5086	-446	5183	6009	-826
1.अ.ख.4 यात्रा	7038	5813	1225	7643	6031	1611
1.अ.ख.5 निर्माण	766	635	131	677	714	-37
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	646	396	250	603	354	249
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1311	1132	180	1239	594	645
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	162	1942	-1780	248	1776	-1528
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	21428	1869	19559	23947	2654	21293
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	9408	9690	-282	10878	11211	-333
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	447	774	-328	551	923	-372
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	140	261	-122	169	298	-128
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	4007	1972	2035	1139	1085	54
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	5635	14238	-8603	6831	15454	-8623
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1074	592	482	1404	663	741
1.आ.2 निवेश आय	3486	13340	-9854	4372	14576	-10204
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1788	6108	-4320	1756	6902	-5146
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	53	3525	-3471	54	3760	-3706
1.आ.2.3 अन्य निवेश	135	3694	-3559	602	3899	-3297
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1508	13	1495	1960	15	1945
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1075	306	769	1055	215	840
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	20891	1539	19352	21984	1975	20009
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20856	1346	19511	21936	1748	20188
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	20224	991	19233	21291	1336	19955
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	633	354	278	645	412	233
1.इ.2 सामान्य सरकार	35	193	-159	48	227	-179
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	75	96	-21	90	186	-97
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	2	4	-2	9	93	-84
2.2 पूंजी अंतरण	72	92	-19	81	93	-12
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	131333	112861	18472	140238	133230	7008
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	14827	7417	7410	15298	7862	7436
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	14076	4055	10021	14523	4482	10041
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	13425	3894	9531	13244	4446	8799
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	10081	3894	6187	9935	4446	5489
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3344		3344	3310		3310
3.1.अ.2 ऋण लिखत	652	161	490	1279	37	1242
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	652	161	490	1279	37	1242
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	751	3361	-2610	775	3380	-2605
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	751	2134	-1383	775	2258	-1483
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	751	1376	-625	775	1478	-703
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		758	-758		780	-780
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1228	-1228	0	1122	-1122
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1228	-1228		1122	-1122
3.2 संविभाग निवेश	60388	62006	-1618	70101	67625	2476
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	59216	61616	-2400	68312	66307	2005
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	50860	52179	-1319	48252	51608	-3352
3.2.2 ऋण प्रतिभितियां	8356	9436	-1081	20059	14699	5361
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1173	391	782	1789	1318	471
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	5623	4344	1278	7395	7138	257
3.4 अन्य निवेश	48627	39093	9534	47444	45487	1957
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	1820	0	1820	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	15402	12078	3324	13458	11513	1945
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	2	-2	0	335	-335
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	15402	12075	3326	13458	11178	2280
3.4.2.3 सामान्य सरकार						
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र						
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	15959	16624	-665	21258	21204	54
3.4.3अ भारत को ऋण	14433	15245	-812	19965	20098	-132
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	1527	1379	147	1292	1106	186
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	36	142	-106	54	71	-17
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	13411	8622	4789	10731	11378	-646
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	1999	1626	373	1942	1321	621
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार				0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	1868	0	1868	0	5118	-5118
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण						
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए						
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए						
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	1868	0	1868	0	5118	-5118
4. कुल आस्तियां / देयताएं	131333	112861	18472	140238	133230	7008
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	71867	63085	8782	71511	66838	4672
4.2 ऋण लिखत	53779	48150	5629	66786	59952	6833
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	5687	1626	4060	1942	6439	-4498
5. निवल भूल-चूक	582	0	582	0	658	-658

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोड़ ₹)

मद	जुलाई-सितंबर 2018			जुलाई-सितंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	1122558	1256075	-133518	1135379	1179423	-44044
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	936477	1145399	-208922	932438	1056673	-124234
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	585056	936075	-351019	563533	831746	-268213
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	585065	871555	-286490	558895	801084	-242189
1.अ.क.2 वाणिज्यिक अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-10	0	-10	4638	0	4638
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	64520	-64520	0	30661	-30661
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	351421	209324	142097	368905	224927	143978
1.अ.ख.1 अन्य के स्वाभिमूर्त्त वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	408	56	351	408	235	173
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	305	1818	-1513	310	1779	-1468
1.अ.ख.3 परिवहन	32556	35682	-3126	36504	42320	-5817
1.अ.ख.4 यात्रा	49373	40780	8593	53826	42478	11348
1.अ.ख.5 निर्माण	5373	4456	917	4770	5031	-261
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4534	2780	1755	4245	2494	1751
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	9200	7939	1261	8729	4187	4543
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1137	13626	-12489	1749	12511	-10762
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	150318	13109	137210	168656	18693	149963
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	65998	67978	-1981	76611	78960	-2348
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3133	5433	-2300	3882	6503	-2621
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	981	1834	-853	1193	2096	-904
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	28107	13834	14273	8021	7641	380
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	39528	99881	-60353	48109	108842	-60733
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	7535	4152	3383	9891	4671	5220
1.आ.2 निवेश आय	24452	93582	-69130	30790	102655	-71866
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	12545	42849	-30304	12365	48608	-36243
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	375	24727	-24352	380	26481	-26100
1.आ.2.3 अन्य निवेश	950	25914	-24964	4241	27463	-23223
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	10581	92	10489	13803	103	13700
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	7540	2147	5394	7428	1515	5913
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	146553	10796	135757	154831	13908	140923
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	146310	9439	136871	154495	12313	142182
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	141872	6953	134920	149953	9410	140544
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4438	2486	1951	4542	2903	1639
1.इ.2 सामान्य सरकार	243	1357	-1113	336	1596	-1260
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	523	672	-150	632	1312	-680
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नाम) / निस्तारण (जमा)	14	28	-14	63	656	-593
2.2 पूँजी अंतरण	509	644	-135	569	656	-87
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	921321	791737	129585	987686	938328	49358
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)	104014	52029	51985	107745	55373	52372
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	98746	28449	70297	102287	31568	70719
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	94175	27316	66859	93280	31310	61970
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	70719	27316	43403	69970	31310	38661
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	23456	0	23456	23309	0	23309
3.1.अ.2 ऋण लिखत	4570	1132	3438	9007	258	8749
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	4570	1132	3438	9007	258	8749
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	5268	23581	-18313	5458	23805	-18346
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	5268	14968	-9700	5458	15904	-10446
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	5268	9650	-4382	5458	10409	-4950
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5318	-5318	0	5496	-5496
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	8613	-8613	0	7900	-7900
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	8613	-8613	0	7900	-7900
3.2 संविभाग निवेश	423635	434985	-11350	493716	476275	17441
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	415410	432244	-16834	481114	466993	14122
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	356793	366047	-9253	339837	363469	-23632
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	58616	66197	-7581	141277	103523	37754
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	8226	2741	5485	12602	9283	3320
3.3 वित्तीय डेबिटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	39443	30477	8966	52083	50270	1813
3.4 अन्य निवेश	341126	274245	66881	334142	320362	13780
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	12768	0	12768	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशिया	108045	84728	23317	94785	81087	13697
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	0	16	-16	0	2359	-2359
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	108045	84711	23334	94785	78728	16056
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईपीबी और बैंकिंग पूँजी)	111956	116621	-4665	149718	149339	379
3.4.3.अ भारत को ऋण	101248	106947	-5699	140615	141548	-932
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	10709	9675	1034	9103	7791	1311
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	253	999	-746	383	501	-117
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	94079	60487	33592	75580	80132	-4551
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	14024	11410	2614	13676	9303	4373
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	13103	0	13103	0	36049	-36049
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	13103	0	13103	0	36049	-36049
4. कुल आस्तियां / देयताएं	921321	791737	129585	987686	938328	49358
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	504159	442549	61611	503643	470736	32907
4.2 ऋण लिखत	377267	337778	39489	470367	422240	48127
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	39895	11410	28485	13676	45352	-31676
5. निवल भूल-चूक	4083	0	4083	0	4633	-4633

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2018-19		2018		2019			
			सितंबर		जून		सितंबर	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	169964	399234	163537	362031	173017	417292	175622	416476
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	111122	382105	107925	346220	112890	399381	114373	398164
1.2 अन्य पूंजी	58841	17129	55613	15811	60127	17911	61249	18312
2 संविभाग निवेश	4699	260313	2641	237895	5012	267073	4541	259993
2.1 इक्विटी	590	147479	1804	135249	1806	151162	2344	144039
2.2 ऋण	4109	112834	837	102645	3206	115912	2197	115953
3 अन्य निवेश	54538	419279	41541	395576	54511	429560	55904	430051
3.1 व्यापार ऋण	924	105191	904	104340	2140	107224	1707	106581
3.2 ऋण	9884	168112	7084	157613	9765	173962	7895	174988
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	25158	130644	16628	122137	24169	133846	27563	133105
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18574	15332	16925	11486	18437	14529	18739	15378
4 रिज़र्व्स	412871		400525		429837		433707	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	642072	1078827	608244	995501	662378	1113926	669775	1106520
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-436755		-387257		-451548		-436745

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	विव 2018-19	2019		2020	विव 2018-19	2019		2020
		जनवरी	दिसंबर	जनवरी		जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)			2.83	3.01			12196681	12826782
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)			1.04	1.09			8085475	8442926
1.1.1 आउटराइट			0.61	0.66			853262	957188
1.1.2 रेपो			0.21	0.21			2950776	2999019
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो			0.21	0.22			4281437	4486719
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन			1.75	1.88			3831685	4083916
1.3 रूपये के डेरिवेटिव @			0.04	0.05			279520	299940
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)			136.02	137.29			10316937	9880821
1.1 ग्राहक लेनदेन			133.82	135.09			8847761	8558049
1.2 इंटरबैंक लेनदेन			2.20	2.20			1469176	1322772
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.7)			20029.92	21194.27			2440803	2454422
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @			0.84	0.76			35	37
2.2 एपीबीएस \$			1369.14	1511.41			6000	9427
2.3 ईसीएस जमा			0.10	0.09			53	43
2.4 आईएमपीएस			2564.67	2595.26			210934	216811
2.5 एनएसीएच जमा \$			674.26	1431.01			79028	82398
2.6 एनईएफटी			2336.88	2605.55			1942231	1929464
2.7 यूपीआई @			13084.02	13050.19			202521	216243
2.7.1 जिसमें से यूएसएसडी@			0.80	0.78			14	14
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.4)			790.71	812.33			72455	73506
3.1 भीम आधार पे @			7.37	9.36			112	141
3.2 ईसीएस नामे			0.00	0.00			-	-
3.3 एनएसीएच नामे \$			769.31	777.36			72306	73316
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @			14.02	25.61			37	49
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)			6615.52	6654.46			149688	151147
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)			2036.64	2017.27			65736	66573
4.1.1 पीओएस आधारित \$			1181.09	1160.35			35157	35124
4.1.2 अन्य \$			855.55	856.92			30579	31449
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)			4578.88	4637.19			83953	84575
4.2.1 पीओएस आधारित \$			2634.18	2587.38			39740	38907
4.2.2 अन्य \$			1944.70	2049.81			44213	45667
5 प्रीपेड भुगतान साधन (5.1 से 5.2)			5073.44	5237.05			18922	18286
5.1 वालेट			3652.64	3876.23			15835	15408
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)			1420.80	1360.82			3088	2878
5.2.1 पीओएस आधारित \$			121.90	128.35			1012	997
5.2.2 अन्य \$			1298.91	1232.47			2076	1880
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)			865.46	887.16			646583	660249
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)			864.44	886.38			645573	659590
6.2 अन्य			1.02	0.78			1010	658
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)			33375.05	34785.26			3328451	3357610
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)			33511.06	34922.55			13645388	13238431
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			32645.60	34035.39			12998805	12578182

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	विव 2018-19	2019		2020	विव 2018-19	2019		2020
		जनवरी	दिसंबर	जनवरी		जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	-	-	14322.15	14402.70	-	-	493342	521368
1.1 इंटर-बैंक \$	-	-	1280.66	1304.45	-	-	101679	107648
1.2 इंटर-बैंक \$	-	-	13041.49	13098.24	-	-	391663	413720
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	-	-	2734.52	2747.49	-	-	3034061	3155249
2.1 इंटर-बैंक @	-	-	626.24	612.05	-	-	1438218	1641369
2.2 अंतर-बैंक @	-	-	2108.29	2135.43	-	-	1595843	1513879
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	-	-	6518.97	6568.95	-	-	293087	298514
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	8.91	8.53	-	-	422	399
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	6481.81	6531.99	-	-	291704	297116
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	28.25	28.43	-	-	961	999
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	-	-	78.52	102.47	-	-	148	177
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	71.47	92.41	-	-	134	163
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	7.05	10.06	-	-	14	14
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	-	-	326.35	400.77	-	-	9163	11109
5.1 एईपीएस @	-	-	326.35	400.77	-	-	9163	11109

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	विव 2018-19	2019		2020
		जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	-	-	8606.57	8728.47
1.1 क्रेडिट कार्ड	-	-	553.33	561.20
1.2 डेबिट कार्ड	-	-	8053.24	8167.26
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	-	-	17625.43	17574.74
2.1 वॉलेट @	-	-	16615.68	16575.31
2.2 कार्ड @	-	-	1009.75	999.43
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	-	-	2.32	2.33
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	-	-	2.10	2.10
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	-	-	0.22	0.23
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	-	-	2.42	2.56
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	-	-	49.88	49.47
6 भारत क्यूआर @	-	-	17.13	17.79

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रैन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

3. केवल धरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

प्रासंगिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2018-19	2018	2019		
			नवंबर	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	115714	8671	-432	9717	14106
	बकाया	918459	870336	974938	985145	999208
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	91108	7262	-2412	7874	10876
	बकाया	618418	584853	662945	670819	681695
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	31037	1650	-9655	1704	1881
	बकाया	140247	127270	143422	145126	147007
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-31	38	-19	-12	80
	बकाया	3107	2947	2947	2935	3015
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	53	-2	-2	-5	823
	बकाया	10	-11	-9	-14	809
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	10967	938	1246	1086	1584
	बकाया	192658	188723	199037	200123	201707
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	13990	1197	1521	1408	1706
	बकाया	55708	50840	64280	65688	67394
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25000	2089	3229	2606	3625
	बकाया	124292	114411	142095	144701	148326
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	71534	66578	81128	82377	84270
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	5910	5478	6451	6531	6637
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6901	6792	7155	7193	7262
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	39947	35563	47361	48600	50157
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	10081	1352	1268	1087	1177
	बकाया	102401	100689	111177	112264	113441
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	11	0	0	0	0
	बकाया	-26	-37	-25	-25	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	16067	1223	2230	1634	2580
	बकाया	221517	214368	232925	235049	237586
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	11318	962	1304	905	1717
	बकाया	98492	91250	105156	106061	107778
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	334	0	-53	-1	0
	बकाया	263	283	-288	-289	-289
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18678	-1669	-1135	-822	-1090
	बकाया	19303	26391	9665	8843	7753
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	23018	1915	2120	1552	1953
	बकाया	93630	84895	107743	109295	111248
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	93	15	-6	0	0
	बकाया	2	-81	-179	-179	-179
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-18	0	0	0	0
	बकाया	-80	-81	-82	-82	-82
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	9907	11711	10910	11400	11357
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	8539	186	-250	209	650
	बकाया	78524	71115	79068	79277	79927

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी: अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डेटा निवल रसीदें हैं, अर्थात् सकल रसीद माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

श्रेणी	केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां				
	2018	2019			
	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	5758103	5921026	6072243	6314426	6512659
1. वाणिज्य बैंक	40.51	40.28	39.05	39.66	39.05
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.33	0.31	0.36	0.42	0.39
3. बीमाकृत कंपनियां	24.57	24.34	24.88	24.86	24.90
4. म्यूच्युअल फंड	0.64	0.35	0.64	0.77	1.53
5. सहकारी बैंक	2.38	2.29	2.17	2.01	1.97
6. वित्तीय संस्थाएं	1.01	1.05	1.05	1.15	1.14
7. कॉरपोरेट	1.05	0.97	0.99	0.92	0.84
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.60	3.22	3.27	3.31	3.33
9. भविष्य निधियां	5.54	5.47	5.35	4.87	4.93
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	13.81	15.27	15.67	14.99	14.72
11. अन्य	6.55	6.46	6.57	7.05	7.23
11.1 राज्य सरकार	1.97	2.00	2.02	1.99	1.97

श्रेणी	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां				
	2018	2019			
	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	2669393	2777229	2826935	2905169	3047353
1. वाणिज्य बैंक	34.00	33.87	32.57	32.53	32.46
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.60	0.58	0.81	0.72	0.64
3. बीमाकृत कंपनियां	33.90	33.04	33.94	33.39	32.50
4. म्यूच्युअल फंड	1.23	1.20	1.24	1.12	1.20
5. सहकारी बैंक	4.67	4.55	4.65	4.24	4.16
6. वित्तीय संस्थाएं	0.37	0.42	0.44	0.33	0.31
7. कॉरपोरेट	0.22	0.29	0.32	0.28	0.31
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.09	0.09	0.08	0.05	0.04
9. भविष्य निधियां	21.29	22.15	21.88	22.36	23.66
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	3.64	3.81	4.08	4.98	4.73
11.1 राज्य सरकार	0.07	0.11	0.14	0.16	0.17

श्रेणी	खजाना बिल				
	2018	2019			
	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	529826	412704	524618	538041	514588
1. वाणिज्य बैंक	53.76	57.56	53.60	50.81	45.19
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.06	2.68	1.85	1.92	2.07
3. बीमाकृत कंपनियां	4.74	6.61	5.13	5.55	5.76
4. म्यूच्युअल फंड	5.65	2.78	13.00	14.08	20.42
5. सहकारी बैंक	1.21	2.48	2.54	2.55	2.07
6. वित्तीय संस्थाएं	1.88	2.49	2.14	1.82	2.12
7. कॉरपोरेट	1.86	2.23	1.67	1.57	1.66
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.02	0.08	0.07	0.01	0.01
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	28.81	23.10	19.99	21.70	20.70
11.1 राज्य सरकार	24.04	17.91	15.59	17.91	16.36

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
	1	2	3	4	(सं.अ.) 5	(ब.अ.) 6
1. कुल वितरण	3285210	3760611	4265969	4515946	5516932	6071777
1.1 गतिविधियां	1872062	2201287	2537905	2635110	3344948	3660857
1.1.1 राजस्व	1483018	1668250	1878417	2029044	2543965	2830634
1.1.2 पूंजी	332262	412069	501213	519356	694352	732102
1.1.3 ऋण	56782	120968	158275	86710	106630	98121
1.2 गैर गतिविधियां	1366769	1510810	1672646	1812455	2089516	2315637
1.2.1 राजस्व	1269520	1379727	1555239	1741432	2002766	2204742
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	584542	648091	724448	814757	901783	1009776
1.2.2 पूंजी	94687	127306	115775	69370	85375	109030
1.2.3 ऋण	2563	3777	1632	1654	1375	1865
1.3 अन्य	46379	48514	55417	68381	82469	95284
2. कुल प्राप्तियां	3189737	3778049	4288432	4528422	5364245	6003162
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2387693	2748374	3132201	3376416	4205473	4653758
2.1.1 कर प्राप्तियां	2020728	2297101	2622145	2978134	3512454	3910428
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1212348	1440952	1652377	1853859	2186529	2399337
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	805176	852271	965622	1121189	1323113	1506912
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3204	3878	4146	3086	2812	4179
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	366965	451272	510056	398282	693019	743330
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	39622	35779	33220	34224	36739	33619
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	60955	59827	69063	142433	136636	170056
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	22072	16561	20942	42213	56398	63131
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	38883	43266	48122	100219	80238	106926
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	836563	952410	1064704	997097	1174823	1247962
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	-37476	231090	617123	144792	386389	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	-334185	60472	195816	-144847	325987	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	861106	708572	429585	844375	793327	----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	664058	673298	689821	794856	831554	959294
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	-56580	-78515	-105038	-163222	-217165	-208528
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	34339	35261	45688	42351	42703	42482
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	5109	-3322	-6436	18423	-14577	-871
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	27545	13470	17792	25138	16011	13706
3ख.1.6 नकद शेष	95474	-17438	-22463	-12476	152688	68615
3ख.1.7 अन्य	53684	316908	427343	284095	368504	376216
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	26.3	27.3	27.8	26.4	29.0	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	25.6	27.4	27.9	26.5	28.2	28.5
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	19.2	20.0	20.4	19.8	22.1	22.1
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.2	16.7	17.1	17.4	18.5	18.5
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.7	6.9	6.9	5.8	6.2	5.9

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी 2020 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	1562	31	1013	20	1614	7
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	133	2	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	665	29	307	13
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	292	24	753	18	266	4
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	9	2	-	-	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	231	30	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	226	22	767	20	234	14
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	903	13	-	-	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	358	1	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	जनवरी 2019 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	7905	778	--	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1261	1	--	0
3	असम	4185	50	--	3000
4	बिहार	7570	--	--	0
5	छत्तीसगढ़	4225	--	1	5500
6	गोवा	568	285	--	0
7	गुजरात	13036	459	--	0
8	हरियाणा	1991	1146	--	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	0
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	--	--	--	0
12	कर्नाटक	4047	--	--	11500
13	केरल	2050	--	--	0
14	मध्य प्रदेश	--	874	--	0
15	महाराष्ट्र	39310	408	--	15000
16	मणिपुर	361	96	--	0
17	मेघालय	585	29	9	0
18	मिज़ोरम	526	38	--	0
19	नगालैंड	1566	32	--	0
20	उड़ीसा	12792	1391	81	23395
21	पुदुचेरी	305	--	--	898
22	पंजाब	230	--	8	0
23	राजस्थान	--	--	129	1800
24	तमिलनाडु	6329	--	40	8632
25	तेलंगाना	5405	1174	--	0
26	त्रिपुरा	315	5	--	0
27	उत्तराखंड	--	--	180	0
28	उत्तरप्रदेश	3008	76	--	0
29	पश्चिम बंगाल	10527	507	214	0
	कुल	128098	7346	661	69725

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2017-18		2018-19		2019-20						2019-20 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	नवंबर		अक्तूबर		जनवरी		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	22800	18922	30200	23824	4206	4206	513	222	5000	4708	33967	26385
2	अरुणाचल प्रदेश	888	703	719	693	-	-	-	-	-	-79	472	393
3	असम	7760	6797	10595	8089	2000	2000	1900	1900	1500	1500	9100	9100
4	बिहार	10000	8908	14300	10903	-	-600	-	-607	4000	4000	18642	15642
5	छत्तीसगढ़	8100	8100	12900	12900	-	-700	2000	2000	2000	2000	6000	5300
6	गोवा	1800	1400	2350	1850	200	200	300	200	381	381	2081	1581
7	गुजरात	24000	15785	36971	27457	1000	1000	2500	1500	8000	6500	30900	21400
8	हरियाणा	16640	15840	21265	17970	-	-	2000	1000	2500	2500	19001	16101
9	हिमाचल प्रदेश	4600	2551	4210	2108	-	-	-	-900	1500	1200	3500	2300
10	जम्मू और कश्मीर	6200	3974	6684	4927	800	800	309	309	600	600	5592	5053
11	झारखंड	6000	4807	5509	4023	-	-	500	500	-	-	2000	156
12	कर्नाटक	22098	17348	39600	31383	8200	6200	7700	7700	7000	7000	36100	31350
13	केरल	20500	16203	19500	14784	1000	324	-	-500	920	920	15602	11626
14	मध्य प्रदेश	15000	13125	20496	14971	1000	1000	2000	440	3000	1447	12000	7327
15	महाराष्ट्र	45000	36480	20869	3117	-	-	3000	3000	6000	5000	31500	20500
16	मणिपुर	525	278	970	667	-	-	-	-	-	-	803	614
17	मेघालय	1116	920	1122	863	-	-	295	295	-	-50	745	471
18	मिज़ोरम	424	277	0	-123	-	-	92	92	-	-	450	349
19	नगालैंड	1135	766	822	355	150	61	250	150	-	-	650	201
20	उड़ीसा	8438	8438	5500	4500	1000	1000	-	-	500	500	4500	4500
21	पुदुचेरी	825	488	825	475	200	200	200	-300	100	100	700	200
22	पंजाब	17470	13349	22115	17053	1900	880	2035	1570	2800	2600	22655	13770
23	राजस्थान	24914	16777	33178	20186	1750	750	1000	-	3750	2750	30082	20000
24	सिक्किम	995	745	1088	795	-	-	-	-	142	142	593	593
25	तमिलनाडु	40965	36023	43125	32278	8700	6700	8000	6000	8000	6000	53390	42190
26	तेलंगाना	24600	21828	26740	22183	3000	3000	1324	1116	3000	2792	26124	20706
27	त्रिपुरा	1137	1137	1543	1387	615	615	-	-100	400	400	2080	1830
28	उत्तराखंड	41600	37178	46000	33307	3000	1694	5500	3922	7500	7500	42000	30140
29	उत्तरप्रदेश	6660	5830	6300	5289	-	-	750	750	-	-	2350	1750
30	पश्चिम बंगाल	36911	25304	42828	30431	6500	4169	5000	4000	6000	6000	39010	23700
	कुल	419100	340281	478323	348643	45221	33499	47168	34258	74593	66411	452588	335228

- : शून्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम्₂ और एनएम्₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
 एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
 जहाँ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहाँ अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं आरआरबी को छोड़कर हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वेप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनपुगी सस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आँकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आँकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के फरवरी 2405 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के जनवरी अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रि-पक्ष रेपो का परिचालन 05 दिसंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: जनवरी 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रीडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

○ बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।

○ जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2018-19 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 31 मई 2019 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2019-20 से लिया गया है। वर्ष 2017-18 से एनसीटी दिल्ली और पदुचेरी के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खजाना बिलों (364-दिन के खजाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खजाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2020	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित [@]) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर [@])	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2019-20 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नंस; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपेयन, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001।

एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शि कायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।